चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 17 मई–23 मई 2010

पीएमओ-10 जनपथ बढ़ रही है दूरी

पेज 3

राजा, टाटा, अंबानी और नीरा राडिया

पेज 5

बड़े पत्रकार बड़े दलाल

पेज 5

साई की महिमा

पेज 12

राहुल को असफल करने की कोशिश

कांग्रेस में जेनरेशन वार शुरू हो गई है. एक वर्ग है, जो नौजवानों को अभी सत्ता चलाने लायक़ नहीं मानता और नौजवान हैं कि अगली विधानसभा और लोकसभा में पूरा चरित्र बदलना चाहते हैं. राहुल गांधी की योजना है कि विधानसभा के लिए अस्सी प्रतिशत टिकट युवाओं को दिए जाएं. नौजवानों को सत्ता की हिस्सेदारी नहीं देने वालों का नेतृत्व ख़ुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर रहे हैं. उनके साथ प्रणव मुखर्जी और चिदंबरम हैं. ये लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनें, क्योंकि इन्हें लगता है कि राहुल गांधी अभी देश की ज़मीनी हक़ीक़त नहीं जानते. कांग्रेस में राहुल को असफल करने की रणनीति भी बनती दिख रही है और उस पर अमल भी हो रहा है.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

संतोष भारतीय

एक महीने बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, जिसमें कांग्रेस अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी. नि:संदेह वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को ही कांग्रेस पुन: अपना अध्यक्ष चुनेगी. इसी अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का चुनाव और मनोनयन होगा तथा कांग्रेस के केंद्रीय संगठन का भी पुनर्गठन होगा. कई महामंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में चले गए हैं, इसलिए नए महामंत्री बनाए जाएंगे. गुलाम नबी आज़ाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल से वापस बुलाया जाएगा और उन्हें संगठन में पुन: महामंत्री बनाया जाएगा तथा चुनाव वाले राज्यों की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी.

कांग्रेस के सामने बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चुनौती हैं. बिहार में कांग्रेस को नए सिरे से ज़िंदा करने की कोशिशें सफल होती नहीं दिखाई दे रहीं. बिहार के प्रभारी जगदीश टाइटलर हैं. बिहार की गुटबंदी चरम सीमा पर है और वहां के वरिष्ठ नेता बुरी तरह बंटे हुए हैं. प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा और जगदीश टाइटलर कई बार आमने-सामने आ चुके हैं. राहुल गांधी बिहार में कोशिश कर चुके हैं और यह मान चुके हैं कि बिहार में कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता.

लेकिन कांग्रेस का मानना है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ किया जा सकता है. उसके लिए अभी से पूरा नक्शा बनाया जा चुका है. उत्तर प्रदेश की कमान पूरी तरह राहुल गांधी ने संभाल ली है. पहले चरण में पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन को सक्रिय करने के लिए चौदह यात्राएं निकाली गई हैं, जिनके नेतृत्व के लिए व्यक्तियों का चयन राहुल गांधी ने ख़ुद किया है. राहुल गांधी के सामने एक सवाल है, जिसका उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का अगला कांग्रेस अध्यक्ष कौन हो. रीता बहुगुणा जोशी स्व. हेमवती नंदन बहुगुणा की पुत्री हैं, वह मेहनत भी कर रही हैं, लेकिन विवाद ज़्यादा पैदा कर रही हैं. कांग्रेस के सामने सामाजिक वर्गों को भी साथ लाने की चुनौती है.

कांग्रेस को लगता है कि ब्राह्मण उनके साथ वापस आ सकता है. कांग्रेस को इस बात का अफसोस है कि भाजपा से जब ब्राह्मण हटे, तो वे कांग्रेस की नाक के नीचे से, उसकी काहिली की वजह से बसपा के साथ चले गए. इसीलिए कांग्रेस ने रीता बहुगुणा जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था. पर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व यह नहीं समझ पाया कि उत्तर प्रदेश का मैदानी ब्राह्मण, पहाड़ के ब्राह्मण को ब्राह्मण ही नहीं मानता. इसीलिए रीता बहुगुणा उत्तर प्रदेश में लगभग असफल हो गई हैं. सोनिया गांधी को अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को अपने साथ लाना है तो उन्हें एक बहुत मज़बूत ब्राह्मण व्यक्तित्व को उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष पद के लिए भेजना होगा.

हमारी जानकारी के अनुसार सोनिया गांधी के यहां विचार हो रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर भेजा जाए और उन्हें संभावित मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित किया जाए. शीला दीक्षित देश के ब्राह्मणों की न केवल सबसे बड़ी, बल्कि निर्विवाद नेता हैं. वह उमाशंकर दीक्षित जी की बहू हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अभी भी याद करता है. शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश से सांसद व मंत्री रही हैं तथा उत्तर प्रदेश की बहू हैं. उनसे उत्तर प्रदेश की हर पार्टी के ब्राह्मण नेता, बसपा तक के, संपर्क रखते हैं. शीला दीक्षित कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जीत के लिए ट्रंप कार्ड हैं. देखना यह है कि सोनिया गांधी इस कार्ड को कब चलती हैं.

कांग्रेस जिस दूसरे वर्ग पर आशा टिकाए है, वह है मुस्लिम वोट. उसे लगता है कि जैसे लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने उसे समर्थन दिया, विधानसभा में भी वैसा ही होगा. पर यहां कांग्रेस के पास मुस्लिम चेहरे की कमी है. सलमान खुर्शीद और ज़फर अली नक़वी केवल दो नाम हैं, जिनके अपने प्लस और माइनस हैं. मुसलमान कांग्रेस में अपनी जगह तलाशना चाहता है, पर वह उसे दिखाई नहीं देती. जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो देश के किसी भी प्रदेश में न मुसलमान मुख्यमंत्री है, न विपक्ष का नेता और न ही किसी प्रदेश का अध्यक्ष. मुसलमान जिन मुस्लिम नेताओं से बातचीत करने में सहजता महसूस करता है, वैसे नेताओं को कांग्रेस सूत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं करती. केंद्रीय मंत्रिमंडल में, जहां से संदेश जाते हैं, गुलाम नबी आज़ाद और सलमान खुर्शीद हैं. गुलाम नबी आज़ाद के साथ कश्मीर का मुसलमान होना जुड़ा है, वैसे ही जैसे रीता बहुगुणा जोशी पहाड़ की ब्राह्मण हैं.

कांग्रेस के कोर ग्रुप में इस रणनीति के ऊपर विचार हो रहा है कि यदि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी ऐसे मुसलमान नेता को दी जाए, जो लोकप्रिय हो. इसके पीछे तर्क है कि इस क़दम से न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि बिहार में भी कांग्रेस को फ़ायदा होगा और ब्राह्मण तथा मुसलमान कांग्रेस के साथ दोबारा जुड़ जाएंगे.

राहुल गांधी की राय से ही उत्तर प्रदेश की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीतने के बाद ही देश में यह संदेश जाएगा कि राहुल गांधी में एक सफल जननेता बनने के गुण हैं और वह एक सफल प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं. कांग्रेस को इस बात का भी आभास हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान, ख़ासकर अट्ठारह से पच्चीस वर्ष का युवक राहुल के प्रति बुरी तरह आकर्षित हो रहा है.

इसीलिए कांग्रेस में राहुल को असफल करने की रणनीति भी बनती दिख रही है और उस पर अमल भी हो रहा है. ताज़ा उदाहरण कटमोशन पर वोटिंग का है. उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने सारी ताक़त मायावती के मुक़ाबले लोगों को खड़ा करने में लगा दी. अंबेडकर नगर में चौदह अप्रैल को एक लाख के आसपास लोगों की सभा की और सारे प्रदेश में यात्राएं निकालने की शुरुआत की. वहीं सत्ताइस अप्रैल को लोकसभा में कांग्रेस नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी का समर्थन ले लिया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इसके बदले सरकार ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के इनकम टैक्स मसलों को सुलझाने का वायदा किया है.

अब राहुल गांधी की रणनीति बनाने वालों की समझ में नहीं आ रहा है कि जब लालू यादव और मुलायम सिंह ने साफ कर दिया था कि वे भाजपा के साथ मतदान नहीं करेंगे, तो क्यों मायावती से समर्थन लिया गया. सरकार को कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती सोनिया गांधी को डराया गया कि सरकार गिर सकती है, अत: कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए. इसका सबसे मज़ेदार पहलू यह है कि यह फ़ैसला लेते समय राहुल गांधी को बताया ही नहीं गया. इस एक क़दम से राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिशों में पलीता लग गया.

क्या यह राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में असफल करने की कोशिश है? कम से कम राहुल गांधी के साथ काम कर रहे कांग्रेस नेताओं का यही मानना है. इसका एक उदाहरण वे दिग्विजय सिंह का देते हैं. दिग्विजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने की मुहिम तेज़ की. इसकी शुरुआत उन्होंने आजमगढ़ से की. उन्होंने मांग की कि बाटला हाउस कांड के आरोपियों की सुनवाई विशेष अदालत में जल्दी-जल्दी हो, ताकि यदि वे दोषी साबित हों तो जेल में सड़ें और निर्दोष साबित हों तो रिहा किए जाएं. दिग्विजय सिंह से इतनी ही मांग इन आरोपियों के घर वालों ने की थी. दिग्विजय सिंह को मांगों में वज़न लगा और उन्होंने इसका समर्थन किया. लेकिन कांग्रेस में इस मांग से भूचाल आ गया. दिग्विजय सिंह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव राहुल गांधी के कहने पर ही सोनिया गांधी ने बनाया है. दिग्विजय सिंह और परवेज़ हाशमी की जोड़ी ने आसाम, हरियाणा में कमाल का काम किया था. राहुल गांधी चाहते थे कि गंभीर राजनैतिक पहल उत्तर प्रदेश में हो, इसीलिए उन्होंने दिग्विजय सिंह और परवेज़ हाशमी को उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए कहा. लोकसभा में वोट के लिए लिए गए फ़ैसले ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की निकलने वाली सारी यात्राओं का महत्व फीका कर दिया.

धीरे-धीरे पर्दा हट रहा है और दिखने लगा है कि दस जनपथ और सात रेसकोर्स रोड कुछ अलग-अलग से हैं. सोनिया गांधी को अपनी राय खत लिखकर प्रधानमंत्री को बतानी पड़ती है और प्रधानमंत्री खत लिखकर ही उस राय को अस्वीकार कर देते हैं. सोनिया गांधी मोटे तौर पर अपने बेटे राहुल गांधी के साथ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी ने मंत्री पद अस्वीकार कर उनका मान बढ़ाया है. छह साल पहले सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री पद अस्वीकार कर दिया था और अपनी जगह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था. खेमे भी बंटने लगे हैं.

कांग्रेस में जेनरेशन वार शुरू हो गई है. एक वर्ग है, जो नौजवानों को अभी सत्ता चलाने लायक़ नहीं मानता और नौजवान हैं कि अगली विधानसभा और लोकसभा में पूरा

(शेष पृष्ठ 2 पर)

धीरे-धीरे पर्दा हट रहा है और दिखने लगा है. 27 अप्रैल को लोकसभा में कांग्रेस नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी का समर्थन ले लिया. अब राहुल गांधी की रणनीति बनाने वालों की समझ में नहीं आ रहा है कि मायावती से समर्थन क्यों लिया गया. सरकार को कोई ख़तरा नहीं था, फिर भी कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को डराया कि सरकार गिर सकती है. हैरानी की बात यह है कि फ़ैसला लेते समय राहुल गांधी को बताया ही नहीं गया.

रोचक बात तो यह है कि दोबारा बहाल किए जा रहे उक्त अधिकारी अपने पुराने पदों से कम महत्व वाले पदों पर भी नियुक्त किए जा रहे हैं.

दिल्ली का बाबू

नौकरशाहों का बढ़ा रुतबा

प्रशासन में विशेषज्ञ और सामान्य के बीच का मतभेद नया नहीं है और न ही यह बात किसी से छुपी है कि विशेषज्ञों को उनके काम के मुताबिक़ महत्व नहीं मिलता. इन दिनों सड़क परिवहन मंत्रालय के इंजीनियरों की फौज नौकरशाहों से ख़फ़ा है. इंजीनियरों का आरोप है कि नौकरशाह उन्हें किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कहना है कि नौकरशाह उन तकनीकी मामलों में भी हस्तक्षेप करते हैं, जिनमें फ़ैसला लेने के लिए ज़रूरी योग्यता भी उनके पास नहीं है.

सूत्रों के मुताबिक़, एक ओर जहां देश के सड़क तंत्र में दस हज़ार किलोमीटर का इज़ाफ़ा होने वाला है, तो दूसरी ओर इंजीनियरों की संख्या लगातार कम होती जा रही है. वर्तमान समय में सड़क परिवहन मंत्रालय में इंजीनियरों के 70 पद खाली पड़े हैं. इन पदों को भरा नहीं जा रहा तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि नौकरशाह तकनीकी विशेषज्ञता की ज़रूरत वाले क्षेत्रों में भी अपना अधिकार जमाते जा रहे हैं. ख़बर यह भी है कि मंत्रालय जानबूझ कर प्रशासनिक सेवा वाले पदों का सृजन कर रहा है. विशेषज्ञों की घटती संख्या भविष्य के लिहाज़ से अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन मंत्रालय इसकी चिंता से बेफ़िक्र नज़र आता है.

दागदार हैं तो क्या हुआ

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी झेल रहा पंजाब अकेला राज्य नहीं है, लेकिन इस समस्या से निबटने के लिए उसने अनोखा रास्ता निकाल लिया है. राज्य में पंजाब प्रशासनिक सेवा के कुल 288 स्वीकृत पद हैं, लेकिन फिलहाल 160 अधिकारी ही उपलब्ध हैं. राज्य प्रशासन के आला अधिकारियों ने हाल के दिनों में सेवानिवृत्त अधिकारियों को फिर से बहाल करना शुरू किया है. इन अधिकारियों को कांट्रैक्ट पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट टैक्स एवं एक्साइज़ कमिश्नर जैसे पदों पर दोबारा नियुक्त किया जा रहा है. लेकिन राज्य के नौकरशाह इस नई शुरुआत से बेफ़िक्र हैं. कहा जा रहा है कि दोबारा नियुक्त किए गए कई अधिकारियों का इतिहास दागदार रहा है, लेकिन राज्य के मुख्य सचिव एस सी अग्रवाल की अध्यक्षता वाली अप्वायंटमेंट कमेटी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया.

रोचक बात तो यह है कि दोबारा बहाल किए जा रहे उक्त अधिकारी अपने पुराने पदों से कम महत्व वाले पदों पर भी नियुक्त किए जा रहे हैं. हालांकि सूत्र बताते हैं कि सरकार ने अब जाकर राज्य लोक सेवा आयोग को योग्य अधिकारियों को पदोन्नत करने का आदेश दिया है.

इन्हें मत छूना!

सार्वजनिक उपक्रमों एवं वित्तीय संस्थाओं के बड़े अधिकारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए नौकरशाहों की एक कमेटी गठित करने के फ़ैसले को जहां भ्रष्ट अधिकारियों की नकेल कसने का एक और तरीक़ा माना जा रहा है, वहीं इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के पर कतरने की एक पहल के रूप में भी देखा जा रहा है.

इस फ़ैसले ने क़रीब 240 सार्वजनिक उपक्रमों और 40 बैंकों, बीमा कंपनियों एवं वित्तीय संस्थाओं के 1000 से भी ज़्यादा अधिकारियों को सतर्कता आयोग के दायरे से बाहर कर दिया है. कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर इस कमेटी के अध्यक्ष हैं. सूत्रों का मानना है कि फ़ैसले ने ऐसे अधिकारियों की एक फौज खड़ी कर दी है, जिनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती.

दिलीप चेरियन
dilipcherian@chauthiduniya.com

संसद के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चंद्रशेखर के चित्र के अनावरण के मौक़े पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व सांसद कमल मोरारका, सुषमा स्वराज एवं जयपाल रेड्डी.

संसद के सेंट्रल हॉल में स्व. चंद्रशेखर के चित्र का अनावरण

चार मई को संसद के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चंद्रशेखर के चित्र का अनावरण किया गया. अनावरण उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के हाथों संपन्न हुआ. इस मौक़े पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व सांसद कमल मोरारका, सीपीआई नेता डी राजा समेत विभिन्न पार्टियों के कई नेता मौजूद थे. स्व. चंद्रशेखर का जन्म एक जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में हुआ था. उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की. वह छात्र जीवन के दौरान ही समाजवादी आंदोलन में शामिल हो गए और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने. 1965 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ सैद्धांतिक मतभेदों के चलते आपातकाल के दौरान उन्हें जेल में बंद कर दिया गया. जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी. बाद में भारत की हालत को नज़दीक से समझने के लिए उन्होंने देश भर की पदयात्रा की, जो काफी सफल रही. भारतीय राजनीति में युवा तुर्क के नाम से मशहूर चंद्रशेखर 1962 से 1967 तक राज्यसभा के सदस्य रहे. फिर लोकसभा के सदस्य बने और उन्होंने आठ बार बलिया संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस्तीफ़े के बाद 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक वह देश के प्रधानमंत्री रहे. 8 जुलाई 2007 को 80 साल की उम्र में उनका देहावसान हो गया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राहुल को असफल करने की कोशिश

पृष्ठ 1 का शेष

चरित्र बदलना चाहते हैं, राहुल गांधी की योजना है कि इस बार अस्सी प्रतिशत टिकट पच्चीस से पैंतीस वर्ष की उम्र के लोगों को विधानसभा के लिए दिए जाएं. इसका प्रयोग बिहार और बाद में उत्तर प्रदेश में होने वाला है, लेकिन जो वर्ग नौजवानों को अभी सत्ता की हिस्सेदारी नहीं देना चाहता, उसका नेतृत्व ख़ुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर रहे हैं. उनके साथ देश के वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी और गृहमंत्री चिदंबरम हैं. ये लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनें, क्योंकि इन्हें लगता है कि राहुल गांधी अभी देश की ज़मीनी हक़ीक़त नहीं जानते.

राहुल गांधी ने कई जगह बातचीत में कहा है कि हिंदू–मुसलमान जैसी क्या चीज़ होती है. हमें नौजवानों को एक वर्ग मानना चाहिए. वह नौजवानों के विभिन्न सामाजिक वर्गीकरण और उससे जुड़े हितों पर भी बातचीत नहीं करना चाहते और ये नेता इसे राहुल गांधी का कच्चापन मान रहे हैं. इन्हें लग रहा है कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को अधकचरी राजनैतिक शिक्षा दे रहे हैं, इसीलिए ये सारे दिग्विजय सिंह के ख़िलाफ़ खड़े दिखाई दे रहे हैं.

देश का प्रधानमंत्री पद भी बड़ी कमाल की चीज़ है. प्रणव मुखर्जी के लिए यह आख़िरी लोकसभा है, क्योंकि उनकी उम्र प्रधानमंत्री बनने की उम्र से बहुत ज़्यादा हो रही है. कांग्रेस में अकेले

दिग्विजय सिंह माने जा रहे हैं कि अगर कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने से इंकार करें तो वह ही हैं, जिन पर नज़रें टिकती हैं. इसलिए कांग्रेस का वरिष्ठ तबका दिग्विजय सिंह को राजनैतिक हाशिए पर ले जाने के लिए सारी योजनाएं बना रहा है.

राहुल गांधी के राजनैतिक साथी जहां मायावती का कटमोशन पर समर्थन लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की धार भोथरी होने से हैरान हैं, वहीं वे अपने गृहमंत्री चिदंबरम को भी नहीं समझ पा रहे हैं. क़ानून व्यवस्था राज्य का विषय है. नक्सलवादी समस्या पर राज्य तो खामोश हैं, लेकिन चिदंबरम दहाड़ रहे हैं और पिछले छह महीने में ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर लड़ाई नक्सलवाद से लड़नी है तो यह केंद्र लड़ेगा. राज्य इस ज़िम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं. अब चाहे दंतेवाड़ा हो या लालगढ़, हार की ज़िम्मेदारी केंद्रीय सरकार के माथे आ गई है. राहुल गांधी के राजनैतिक सिपहसालार माथा पीट रहे हैं कि इस स्थिति को रोकने की जगह चिदंबरम बढ़ा रहे हैं.

राहुल गांधी के राजनैतिक साथी राहुल गांधी के दिमाग़ के बारे में बताते हैं कि राहुल केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई प्रधानमंत्री होने से काफी परेशान हैं. शरद पवार, ए राजा, ममता बनर्जी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, मानों वे अपने विभाग के प्रधानमंत्री हों. वे अपने को न संसद के प्रति जवाबदेह मानते हैं और न प्रधानमंत्री के प्रति. दूसरी ओर प्रधानमंत्री इन्हें नियंत्रित या तो करना नहीं चाहते या नियंत्रित कर नहीं पा रहे. मनरेगा जैसी योजना का अपेक्षित परिणाम न ला पाना भी राहुल गांधी की चिंता का विषय है.

इसका एक पहलू यह है कि न प्रधानमंत्री, न प्रणव मुखर्जी और न चिदंबरम भीड़ खींच पाते हैं. कांग्रेस में सिर्फ़ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही आज स्टार प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं. शायद इसीलिए दस जनपथ ने तय किया है कि बिहार व उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए प्रियंका गांधी से कहा जाए. प्रियंका गांधी से कांग्रेस के लोगों को यह आशा है कि वह पूरी तरह हारी बाज़ी जिताने की ताक़त रखती हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हार रहे सतीश शर्मा को रायबरेली में जीत रहे अरुण नेहरू के मुक़ाबले जितवा लिया था. बिहार और उत्तर प्रदेश में दस जनपथ इस महत्वपूर्ण दांव को खेलने जा रहा है.

विपक्ष के सभी दलों के लिए या कहें कि कांग्रेस के अलावा सभी दलों के लिए एक संकट पैदा हो जाएगा, यदि कांग्रेस राहुल गांधी की बात मान विधानसभा व लोकसभा में अस्सी प्रतिशत टिकट नौजवानों को देती है तो. इससे दूसरे दलों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे नौजवानों को टिकट दें. अगली जुलाई से भारतीय राजनीति में उम्र के गुणात्मक दौर का प्रारंभ हो जाएगा, पर यह इस पर निर्भर होगा कि ख़ुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को कितना सफल होने देते हैं.

आख़िर में पुनः जुलाई में होने वाले कांग्रेस के अखिल भारतीय अधिवेशन की बात करते हैं. इस अधिवेशन में राहुल गांधी को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष बनाया जा सकता है. सोनिया गांधी चाहती हैं कि राहुल गांधी एक विजेता की तरह भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हों और इसके लिए बिहार, उत्तर प्रदेश तथा लोकसभा जीतना ज़रूरी है. राहुल गांधी के नेतृत्व में यदि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ती है तो उसे देश के नौजवानों का अभूतपूर्व समर्थन मिल सकता है, ऐसा उनका मानना है. प्रियंका गांधी का साथ इसे ठोस शक्ल देता है. बाक़ी राजनैतिक दल बैकफुट पर आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास नौजवानों को आकर्षित करने के लिए कोई चेहरा ही नहीं है.

राजनीति के सबसे बड़े खेल को देखने के लिए तैयार हो जाइए.

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 10
दिल्ली, 17 मई–23 मई 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

मनमोहन सिंह अब अपने बारे में बनाई गई धारणाओं को तोड़ रहे हैं. वह साबित करना चाहते हैं कि वह अब कठपुतली प्रधानमंत्री नहीं रहे, जिसकी डोर सोनिया गांधी के हाथों में थी.

पीएमओ-10 जनपथ बढ़ रही है दूरी

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

शशि शेखर

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब सोनिया गांधी की बातों को नज़रअंदाज़ करने लगे हैं. मनमोहन सिंह के लिए अब सोनिया गांधी की बातों का कोई मतलब नहीं है. बात थोड़ा चौंकाने वाली है, लेकिन सच है. अब यूपीए सरकार में दस जनपथ का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाता. पहले कहा जाता था कि प्रधानमंत्री ऐसा कोई काम नहीं करते, जो यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को पसंद न हो. अब शायद वक़्त करवट ले रहा है. बिना कोई शोर मचाए, मनमोहन सिंह अब अपने बारे में बनाई गई धारणाओं को तोड़ रहे हैं. वह साबित करना चाहते हैं कि वह अब कठपुतली प्रधानमंत्री नहीं रहे, जिसकी डोर सोनिया गांधी के हाथों में थी. मनमोहन सिंह यह भी साबित करना चाहते हैं कि सत्ता का असली केंद्र 10 जनपथ नहीं, पीएमओ ही है. शायद तभी उन्होंने पहली बार एक ऐसा काम किया, जिसकी उम्मीद ख़ुद सोनिया गांधी को भी न रही होगी. दरअसल, इस पूरी कहानी की शुरुआत एक क़ानून में होने वाले प्रस्तावित संशोधन से जुड़ी है. सूचना का अधिकार क़ानून (आरटीआई एक्ट) यूपीए-1 सरकार की बहु प्रचारित उपलब्धियों में से एक रही है. ख़ुद राहुल गांधी ने इस क़ानून के प्रति काफी दिलचस्पी दिखाई थी और अब भी दिखा रहे हैं. केंद्र सरकार पिछले कई सालों से इस क़ानून में आमूलचूल परिवर्तन (संशोधन) करना चाहती है. इसी मामले में सोनिया गांधी एक पत्र के ज़रिए मनमोहन सिंह से यह कहती हैं कि उनकी समझ से सूचना का अधिकार क़ानून में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस क़ानून को बने अभी सिर्फ चार साल ही हुए हैं और इतने कम समय में यह क़ानून आम आदमी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है. अब आप कल्पना कीजिए कि मनमोहन सिंह ने इस पत्र के जवाब में क्या लिखा होगा?

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जवाब दिया कि वह आरटीआई क़ानून के प्रभाव को लेकर उनके (सोनिया गांधी) विचारों से सहमत हैं,– लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं, जिनके लिए इस क़ानून में संशोधन करना ज़रूरी हो गया है. ज़ाहिर है, प्रधानमंत्री का यह जवाब ख़ुद में इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि वह आंख मूंदकर सोनिया गांधी की हर बात नहीं मान सकते.

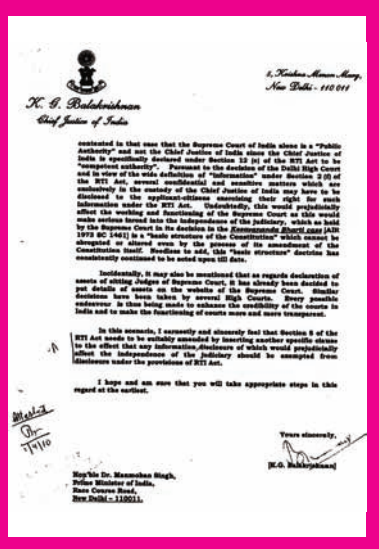

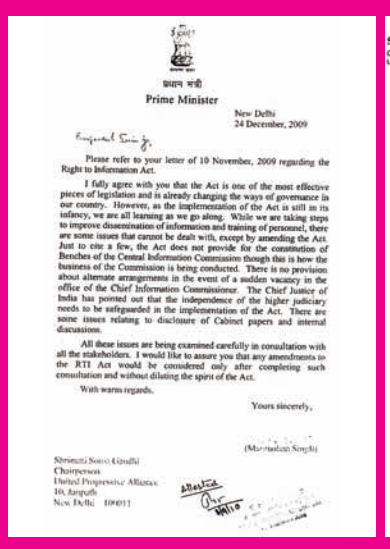

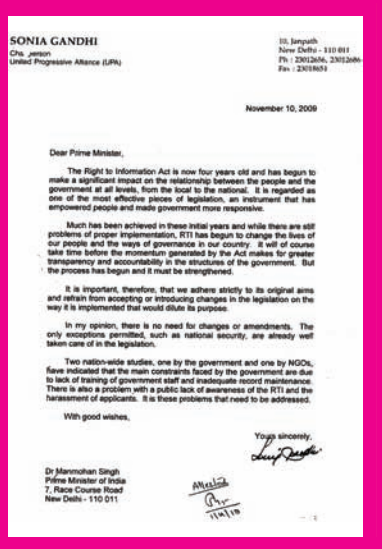

हम दोनों पत्रों को छाप रहे हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने एक-दूसरे को भेजा है. क़ानून में प्रस्तावित संशोधन के पीछे की कहानी यह है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बड़े-बड़े अधिकारी यह नहीं चाहते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत फाइल नोटिंग को सार्वजनिक किया जाए. उन्हें इस बात का ख़तरा है कि अगर फाइल नोटिंग को सार्वजनिक किया गया तो नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों के बीच की मिलीभगत का ख़ुलासा हो जाएगा. हक़ीक़त यह है कि ज़्यादातर अधिकारी किसी भी फाइल पर कुछ लिखने से पहले मंत्री से अनौपचारिक रूप से बात करते हैं, जो अपने आप में ग़लत है. पिछले कुछ सालों में सूचना के अधिकार के ज़रिए सरकारी ख़र्चों का ब्योरा, सरकारी कामकाज के तरीक़े, सरकारी पैसे की उपयोगिता और बंटवारा, अधिकारियों द्वारा फ़ैसले लिए जाने की प्रक्रिया, सरकारी अवार्ड देने के तरीक़े तक की जानकारी सबके सामने आ गई, जिससे मंत्रालयों में बैठे बड़े-बड़े अधिकारियों पर उंगलियां उठ गईं और उन्हें शर्मसार होना पड़ा. अधिकारियों को अब यह अहसास होने लगा है कि जिस तरह से आम नागरिक इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, उससे सरकारी कामकाज के तरीक़ों पर सवाल उठने लग जाएंगे, इसलिए इस क़ानून में बदलाव लाना ज़रूरी हो गया है. सरकार के पास इस क़ानून को संशोधित करने के लिए अच्छे तर्क नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के मामले को आगे रखकर सरकार इस क़ानून की धार ख़त्म करना चाहती है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का मामला यह है कि केंद्रीय सूचना आयोग और दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फ़ैसले में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरटीआई के क़ानून के दायरे में आते हैं. फ़िलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. इस बीच तत्कालीन चीफ जस्टिस जी बालाकृष्णन ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र भेजा, जिसमें न्यायपालिका को आरटीआई क़ानून के दायरे से बाहर रखने का आग्रह किया गया था. इसके पीछे तर्क यह था कि इस क़ानून की वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है. इस चिट्ठी के आते ही मंत्रालय में बैठे बड़े-बड़े अधिकारियों को एक मौक़ा हाथ लग गया और उन्होंने सूचना के अधिकार के क़ानून को कुंठित करने के लिए संशोधन का रास्ता साफ़ कर लिया. इन अधिकारियों ने सरकार को यह समझाया कि न्यायपालिका के साथ-साथ ऐसे कई मसले हैं, जिन्हें आरटीआई से बाहर रखा जाए. अधिकारियों ने नोटिंग से लेकर संवेदनशील दस्तावेज़ की लंबी लिस्ट बना ली. इसका असर यह हुआ कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के पत्र के जवाब में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह भरोसा दिलाया कि वह इस मामले में विधि मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं और इस संबंध में जो भी ज़रूरी क़दम होगा, वह उठाया जाएगा.

जब कुछ ग़ैर सरकारी संगठनों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस मामले में सोनिया गांधी से हस्तक्षेप की मांग की. तब सोनिया गांधी ने 9 नवंबर 2009 को पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि वह इस क़ानून में किसी भी तरह के संशोधन के ख़िलाफ़ हैं. सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा है कि सिर्फ़ 4 सालों में ही इस क़ानून ने आम आदमी को बहुत कुछ दिया है, जबकि इस क़ानून को ठीक ढंग से लागू करने में अभी भी काफी समस्याएं हैं. फिर भी इस क़ानून ने प्रशासन के रवैये को बदलना शुरू कर दिया है. सोनिया गांधी ने लिखा कि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए इस क़ानून में उपलब्ध कराए गए प्रावधानों को और कारगर बनाने में निश्चित रूप से समय लगेगा. क़ानून और इसके प्रावधानों को कारगर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और अब यह ज़रूरी है कि इसे हर हाल में मज़बूती प्रदान की जाए. सोनिया अपने पत्र में आगे लिखती हैं कि मेरी राय में राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे अभी भी इस क़ानून से बाहर हैं और ऐसी सूरत में इस क़ानून में किसी भी संशोधन की ज़रूरत नहीं है. इतना ही नहीं, अपने पत्र के माध्यम से सोनिया ने प्रधानमंत्री को यह भी बता दिया कि सरकार इस क़ानून के क्रियान्वयन में कहां और क्यों असफल हो रही है. सोनिया विभिन्न सरकारी और ग़ैर सरकारी संगठनों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पत्र में लिखती हैं कि सरकार की असली समस्या कर्मचारियों में प्रशिक्षण का अभाव और सरकारी आंकड़ों का बेतरतीब रखरखाव है.

लेकिन, सोनिया गांधी के उक्त तर्क कहीं असर नहीं दिखा पाते और प्रधानमंत्री साफ़-साफ़ यह बता देते हैं कि देश में कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं, जिन्हें इस क़ानून में संशोधन किए बग़ैर हल नहीं किया जा सकता. उन्होंने अपने पत्र में सोनिया गांधी को यह भी समझाने की कोशिश की है कि न्यायपालिका के हित में आरटीआई क़ानून में संशोधन ज़रूरी है. दरअसल, भारतीय व्यवस्था में अधिकारियों और सरकारी बाबुओं को यह कभी भी अच्छा नहीं लगता कि एक आम आदमी उनसे सवाल पूछने की हिम्मत करे, लेकिन यह क़ानून आम आदमी को यही ताक़त देता है. इसी से परेशान होकर ऐसे अधिकारी शुरू से ही इस क़ानून को कमज़ोर बनाने की कोशिश करते रहे हैं. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री को भी बार-बार यह समझाने की कोशिश होती रही है कि सूचना क़ानून की वजह से सरकारी कामकाज बाधित होता है, इसलिए इसमें संशोधन किया जाए. इस बार मनमोहन सिंह भी इन चतुर-चालाक अधिकारियों की बातों में आ गए. और, इतना आ गए कि सोनिया गांधी की बातों का भी उनके लिए कोई मतलब नहीं रहा और उन्होंने सीधे-सीधे उनकी राय से असहमति जता दी. तो क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि आरटीआई एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के मसले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के रिश्तों में दरार पड़ गई है और आने वाले दिनों में कांग्रेस की राजनीति में कुछ नए परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं?

shashishekhar@chauthiduniya.com

राज्यसभा में जब श्रम और रोज़गार राज्यमंत्री हरीश रावत से सवाल किया जाता है कि देश में बेरोज़गारों की मौज़ूदा संख्या कितनी है तो वह एकबारगी कुछ बोल नहीं पाते.

प्रधानमंत्री नहीं जानते, देश में कितने बेरोज़गार!

रूबी अरुण

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार रोज़गार के नाम पर देश के नौजवानों के साथ धोखा कर रही है. रोज़गार के नाम पर नई–नई योजनाओं का मजमा लगाए बैठी यूपीए सरकार को यह पता ही नहीं कि देश में बेरोज़गारों की संख्या कितनी है. महंगाई रोक पाने में बुरी तरह विफल सरकार नहीं चाहती कि देश के युवाओं को रोज़गार मिले, देश से बेरोज़गारी की महामारी ख़त्म हो. सरकार की नीयत ही नहीं है कि हर नौजवान को काम मिले और देश से भूख और ग़रीबी का ख़ात्मा हो. रोज़गार के अवसर पैदा करने के नाम पर सरकार आंकड़ों का घालमेल करके पूरे देश की आंखों में धूल झोंक रही है. दरअसल सरकार ऐसा चाहती भी नहीं कि वह इस बात की जानकारी हासिल करे या फिर इसका रिकॉर्ड रखे, क्योंकि अगर सरकार ने ऐसा किया तो उसके रोज़गार संबंधी दावों की पोल खुल जाएगी. सरकार के उस झूठ की कलई उतर जाएगी, जिसके तहत वह यह दावा करते नहीं अघाती कि देश में रोज़गार का ज़्यादा से ज़्यादा सृजन करना ही उसकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना है. कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी भले ही देश के युवाओं को रिझाने–बहलाने की हर जुगत करें, बड़े–बड़े लुभावने वादे और दावे करें, रोज़गार गारंटी योजना की शान में कसीदे पढ़ें, पर उनकी ही सरकार उनके तमाम दावों में पलीता लगा रही है.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

राज्यसभा में जब श्रम और रोज़गार राज्यमंत्री हरीश रावत से सवाल किया जाता है कि देश में बेरोज़गारों की मौज़ूदा संख्या कितनी है तो वह एकबारगी कुछ बोल नहीं पाते. बाद में उनका लिखित जवाब आता है, जिसमें कहा जाता है कि सरकार के पास बेरोज़गारों के ताज़े आंकड़े हैं ही नहीं, जो जानकारी दी जाती है, वह वर्ष 2004–05 की होती है. उसके मुताबिक़, 2004–05 में देश में 10.84 करोड़ बेरोज़गार थे. जाहिर है, जिस तेज़ी से आबादी और महंगाई बढ़ी है और मंदी का विकट दौर गुजरा है, उसमें देश में बेरोज़गारों की तादाद दोगुनी से भी ज़्यादा हो चुकी है. मनमोहन सिंह सरकार की कथनी और करनी का फ़र्क़ देखिए कि दूसरी तरफ़ वह यह बयान भी देती है कि देश में रोज़गार तलाशने वालों की संख्या पिछले दस सालों में औसतन 56.67 लाख प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है. वर्ष 2009 में 56.69 लाख बेरोज़गारों ने रोज़गार कार्यालयों में पंजीकरण कराया है, पर सरकार ने कितने बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिया, इसकी फेहरिस्त सरकार के पास मौज़ूद नहीं. दिखावे के तौर पर सरकार ने यह ज़रूर किया कि हर हाथ को रोज़गार देने के नाम पर तमाम योजनाओं का शुभारंभ कर दिया, ताकि लोग–बाग इस भ्रम में जीते रहें कि सरकार उनकी रोज़ी–रोटी के लिए हर चंद कोशिशें कर रही है. और, इस मुगालते की आड़ में कांग्रेस का वोट बैंक बरक़रार रहे. वैसे काग़ज़ी तौर पर सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के रूप में सामान्य विकास प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं, पुरुषों और महिलाओं के लिए विभिन्न रोज़–गार कार्यक्रमों को लागू करके दैनिक आधार बनाकर 5 करोड़ 80 लाख रोज़गार अवसरों के सृजन का मक़सद रखा. इसे पूरा करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार गारंटी योजना और प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम भी शुरू किए गए, पर देश के बेरोज़गारों के प्रति सरकार की बदनीयती ने इन सारी योजनाओं का सत्यानाश कर दिया है.

वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी भी हैरान हैं. उन्हें यक़ीन नहीं हो रहा है कि देश के बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए बड़े ज़ोर–शोर से शुरू की गई स्वर्ण जयंती योजना का हाल इतना बुरा है कि वह युवाओं को रोज़गार देने की बजाय लूट–खसोट का ज़रिया बन गई है. सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार और लूट–खसोट के चलते धूल में मिल रही है और इसकी ख़बर तक हमारे वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी को नहीं. हाल में जब प्रणब मुखर्जी के पास इस सिलसिले में बेशुमार शिकायतें आईं, तब उन्होंने इस पूरी योजना के क्रियान्वयन और नतीज़ों की समीक्षा की, तो वह भी भौंचक रह गए. उनकी जुबान से बेसाख्ता यह निकला कि यह पूरा मामला वाकई बहुत गड़बड़ है और योजना अपने लक्ष्य से बिल्कुल ही भटक चुकी है. प्रणब मुखर्जी ने माना कि स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार गारंटी योजना यानी एसजीएसवाई को लेकर बैंकों एवं अन्य सरकारी एजेंसियों में समन्वय का घोर अभाव है और इस योजना को लागू करने के लिए सरकार द्वारा बैंकों को दी जा रही सब्सिडी का भी ग़लत इस्तेमाल हो रहा है. इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मक़सद था कि गांवों के ग़रीब सामूहिक रूप से क़र्ज़ लेकर ख़ुद का व्यवसाय खड़ा करेंगे. बैंक उन्हें कम ब्याज दरों पर क़र्ज़ देंगे और संबंधित व्यवसाय का प्रशिक्षण भी. अव्वल तो अशिक्षा की वज़ह से ग्रामीणों को क़र्ज़ ही नहीं मिले. बैंकों ने सरकारी लक्ष्य के मुताबिक़ क़र्ज़ ही नहीं दिया. और, अगर दिया भी तो वहां सरकारी लालफीताशाही पूरी तरह हावी रही. जैसे–तैसे बैंकों ने ग़रीबों को क़र्ज़ तो दे दिया, पर उन्हें प्रशिक्षित करने की दिशा में कोई क़दम उठाना ज़रूरी नहीं समझा. लिहाज़ा जिन लोगों ने क़र्ज़ लिया, उन्होंने मदद न मिलने की स्थिति में अपना व्यवसाय ही बदल दिया. इस बात के गवाह सरकारी आंकड़े भी हैं. एसजीएसवाई के तहत वित्तीय मदद के लिए जितने भी प्रस्ताव पास किए जाते हैं, उनमें से अधिकतर पर कोई कार्रवाई ही नहीं की जाती. स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार गारंटी योजना के तहत गांवों में कुछ व्यक्तियों को मिलाकर एक स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है. फिर इन समूहों को छोटा–मोटा रोज़गार करने के लिए बैंकों या गैर सरकारी संगठनों से वित्तीय मदद दी जाती है. इसमें जितना ख़र्च आता है, उसका 30 फ़ीसदी बतौर सब्सिडी केंद्र सरकार देती है. वर्ष 2008–09 में एसजीएसवाई के लिए सरकारी और निजी बैंकों को 1922 करोड़ रुपये देने का लक्ष्य रखा गया था, पर वितरित हुए केवल 1282.73 करोड़ रुपये. सरकारी आंकड़ों पर अगर नज़र दौड़ाएं तो वर्ष 2009–10 में बैंकों ने कुल 35 हज़ार 878 समूहों को क़र्ज़ देने के प्रस्ताव स्वीकृत किए, लेकिन 28 हज़ार 408 समूहों ने बाद में पैसा लिया ही नहीं. 2008–09 में 25 हज़ार 507 समूहों को मंज़ूरी मिली, लेकिन सिर्फ़ 14 हज़ार 370 समूहों ने ही क़र्ज़ की राशि ली. बाकी रक़म का इस्तेमाल कहां हुआ, वह सरकार के खाते में वापस आई या फिर घोटालों की नई इबारत लिख दी गई, इसकी जानकारी भी सरकार के पास मौज़ूद नहीं है. जाहिर है, सरकार लगातार झूठ बोल रही है. ग़लत आंकड़ों के आधार पर भारत के विकसित होने का ढोल पीट रही है. सरकार जिस पंचवर्षीय योजना की डफली बार–बार बजाती है, उसके आंकड़ों में भी बाज़ीगरी दिखाई गई है. इसमें जिस 5 करोड़ 80 लाख रोज़गार के पैदा करने की बात कही गई है, उसकी गणना अगर छह साल पुराने बेरोज़गारी के आंकड़ों से की जाए तो भी एक आदमी को पांच दिन से कुछ घंटे ज़्यादा ही रोज़गार मिलेगा, जबकि सरकार यह दावा करती है कि वह साल में 100 दिन रोज़गार दे रही है. जितनी भी रोज़गारपरक योजनाएं सरकार के बस्ते में हैं, उन सभी में कम से कम 100 दिन रोज़गार देने का नियम रखा गया है. छह साल पहले के बेरोज़गारी के आंकड़ों को ध्यान में रखें तो भी 100 दिन के हिसाब से 11 मिलियन बेरोज़गारों के लिए 1100 मिलियन रोज़गार तो न्यूनतम तौर पर भी होना ही चाहिए. पर सरकार छह सालों के बाद भी लक्ष्य रख रही है सिर्फ़ 58 मिलियन रोज़गार के अवसरों का. अब कांग्रेस नीत सरकार की धोखाधड़ी समझने के लिए इससे बड़ा उदाहरण तो हो ही नहीं सकता. देश के नौजवानों के दुर्भाग्य की यह कहानी तब है, जबकि देश के प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री दोनों ही मूर्धन्य अर्थशास्त्री हैं. और, देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जाने वाले राहुल गांधी यह कहते नहीं थकते कि उनकी सरकार की प्राथमिकता ही है सत्ता और समाज में ग़रीबों की न्यायपूर्ण भागीदारी. पर हक़ीकत यह है कि सत्ता में हिस्सेदारी–भागीदारी की बात तो बहुत दूर, यहां ग़रीबों के निवाले तक से सियासत की जा रही है. तो ऐसी सरकार से भला देश के विकास की क्या उम्मीद की जाए, जिसकी अवधारणा ही झूठ की नींव पर खड़ी हो.

ruby@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 12,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 40,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम–भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार–राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा

www.chauthiduniya.tv

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301

पिछले दिनों एक कार्यक्रम में प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस गजेंद्र नारायण रे ने टिप्पणी की थी कि आज की पत्रकारिता वेश्यावृत्ति में बदल गई है.

राजा, टाटा, अंबानी और नीरा राडिया

त्रिदीब रमण

लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में झारखंड के गोड्डा के एक युवा सांसद निशिकांत दुबे ने आम बजट परिचर्चा में भाग लेते हुए सरकार की ओर ज्वलंत सवालों के कई गोले दनादन एक साथ दाग दिए तो एकबारगी पूरा सत्तापक्ष भी सन्न रह गया था. भाजपा के इस युवा सांसद ने सरकार से पूछा कि एक टेप आया है, एक पीआर एजेंसी के बारे में. इस टेप में देश के बड़े उद्योगपतियों से लेकर सरकार तक का ज़िक्र है कि कैसे केंद्र सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, अपितु बाहर के लॉबिस्ट तय कर रहे हैं. दुबे स्पष्ट करते हैं कि इसी टेप को आधार बनाकर जब डायरेक्टर इंवेस्टीगेशन दिल्ली को गोपनीय काग़ज़ात भेजे जाते हैं तो वे लीक हो जाते हैं और आनन–फानन में सरकार डायेक्टर इंवेस्टीगेशन को बदल देती है तथा यह तय करती है कि अब इस मामले को एसेसमेंट अफसर नहीं, अपितु सेटलमेंट कमीशन तय करेगा. और, सबको मालूम है कि सेटलमेंट कमीशन में सरकार के कृपापात्र सेवानिवृत्त अफसरों की बहाली होती है.

दरअसल यह पूरा मसला देश में पीआर और लॉबिंग की सिरमौर नीरा राडिया से जुड़ा है. यह वही राडिया हैं, जब एनडीए शासनकाल में अनंत कुमार शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे तो मैडम राडिया उनकी सबसे करीबियों में शुमार होती थीं. बाद में नीरा राडिया एक एयरलाइंस शुरू करना चाहती थीं. पर चूंकि फंड की पारदर्शिता नहीं थी, समझा जाता है कि शायद इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें अपना एयरलाइंस शुरू करने की इजाज़त नहीं दी. बाद के दिनों में राडिया मुकेश अंबानी और रतन टाटा सरीखे देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ जुड़ गईं. जब मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो रतन टाटा झारखंड सरकार के साथ अपने खनन लीज अनुबंध को आगे बढ़ाना चाहते थे और इस कार्य को पूरा करने के लिए टाटा ने राडिया का चुनाव किया. और, समझा जाता है कि टाटा ने राडिया के मार्फ़त मधु कोड़ा को तब 180 करोड़ रुपये का भुगतान किया और इस पूरे कार्य में राडिया की फीस क्या थी, इसका अभी ख़ुलासा नहीं हो पाया है. पर हां, टाटा ने इस कार्य में जुटी राडिया की पीआर कंपनी से जुड़े सहकर्मियों को एक करोड़ रुपये का पारितोषिक ज़रूर दिया था. आईबी ने ऐसा इस टेप को आधार बनाकर ख़ुलासा किया. पर इस मामले में कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं के नाम सामने आने पर केंद्र सरकार मधु कोड़ा को बचाने में जुट गई है.

सूत्रों के अनुसार, भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसी आईबी ने गृह मंत्रालय की इजाज़त पर नीरा राडिया और उनके सहकर्मियों की टेलीफोन लाइनों पर लगातार नज़र रखी. ज़ाहिरा तौर पर नीरा राडिया देश के कई बड़े उद्योगपतियों का राजनैतिक प्रबंधन देखती हैं. राडिया अपने कॉरपोरेट क्लांइट्स के व्यवसायिक हितों के लिए सरकारी महकमों में उच्च स्तर पर नीतियों में मनमाफिक फेरबदल करवाने के साथ–साथ मंत्रियों की नियुक्तियों में भी हस्तक्षेप करती हैं. नीरा अपना साम्राज्य सुनियोजित तरीके से अपनी चार कंसल्टिंग कंपनियों द्वारा चलाती हैं. वैष्णवी कॉरपोरेट मुख्यत: टाटा समूह, यूनिटेक एवं स्टार टीवी के साथ–साथ अन्य उद्योगपतियों के मीडिया और सरकारी महकमों से जुड़े कामकाज देखती हैं. नीरा ने नियोकॉम कंसल्टिंग की शुरुआत नवंबर 2008 में मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह का राजनैतिक प्रबंधन देखने के लिए की, जबकि नियोसिस की शुरुआत का उद्देश्य आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त नौकरशाहों द्वारा टेलीकॉम, ऊर्जा, उड्डयन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य देखना बताया जाता है. नियोसिस पर भी पूरा नियंत्रण मैडम राडिया का ही है. तथ्यों के अनुसार, टाटा समूह का सिंगूर प्रोजेक्ट जब फेल हो गया था तो नीरा और उनके सहकर्मियों ने नैनो प्रोजेक्ट को अपने तंत्र की मदद से गुजरात में स्थानांतरित करवाया था. इसके लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण माकपा नेताओं को मैनेज किया था. कहा जाता है कि नीरा के लेफ्ट और सीटू के कई नेताओं से बेहद घनिष्ठ संबंध हैं.

एक प्रमुख उद्योगपति घराने को एक न्यूज़ चैनल पर पूर्ण नियंत्रण पाना था. इसके लिए नीरा राडिया और जहांगीर पोचा ने एक दैनिक हिंदी अ़खबार नई दुनिया के मालिक अभय छजलानी से बातचीत की और इस काम को पूरा किया गया. मीडिया प्रबंधन में नीरा और उनके सहकर्मियों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है. वे पत्रकारों को ख़ुश करने के लिए उन्हें सपरिवार विदेश घूमाते हैं, महंगे उपहार देते हैं. इस रिपोर्ट में यह भी ख़ुलासा हुआ है कि एक अंग्रेज़ी दैनिक के पूर्व संपादक और एक अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल की वरिष्ठ पत्रकार को महंगी कारें भेंट की गईं. बातचीत से उजागर हुए तथ्यों के अनुसार, मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के व्यवसायिक विवादों ख़ासकर केजी बेसिन झगड़े में श्रीमती राडिया मुकेश की ओर से ज़ोरदार लॉबिंग कर रही हैं. ख़ुफ़िया सूत्रों के अनुसार, मुकेश अंबानी के सहयोगी मनोज मोदी और परिमल नैथाणी द्वारा नीरा के सहकर्मियों के साथ हुई बातचीत में यह उजागर हुआ कि कुछ एनजीओ द्वारा दायर की पीआईएल को वापस लेने के लिए स्टिंग ऑपरेशन भी करवा कर दबाव डाला गया. मुकेश अंबानी हल्दिया पैट्रो केमिकल्स को अपने प्रभुत्व में लेना चाहते हैं, लेकिन हल्दिया पेट्रोकैम के चेयरमैन सरकार द्वारा मनोनीत फिक्की चीफ तरुण दास हैं. अंबानी के इस हित को पूरा करने के लिए नीरा राडिया तरुण दास के संपर्क में रहीं. सूत्र बताते हैं कि इसके लिए तरुण दास ने माकपा नेता निरूपम सेन को राजी किया तथा निरूपम ने प्रकाश करात से राडिया की मुलाकात भी करवाई. प्रकाश करात और निरूपम सेन यह पूरा प्रोजेक्ट मुकेश अंबानी को दिलाने के लिए तत्पर हैं, पर उन्हें भय था कि माकपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता इसमें उलझनें पैदा कर सकते हैं. सो इस नेता को मैनेज करने की जिम्मेदारी मुकेश अंबानी पर छोड़ी गई.

सेवानिवृत्त नौकरशाह प्रदीप बैजल, जो नीरा के लिए काम करते हैं, पाइप लाइन रेगुलेटरी एजेंसी और रिलायंस के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं. तथ्यों के अनुसार, वित्त मंत्रालय के साथ लॉबिंग की जा रही है कि रिलायंस गैस को खनिज तेल के अनुसंधान के रूप में सात वर्ष तक करमुक्त किया जाए. इसके अलावा रिलायंस ने वी के सिब्बल जो हाइड्रोकार्बंस के महानिदेशक हैं, को आलीशान घर ख़रीद कर दिया है. आरकॉम के चार अफसरों के ख़िलाफ़ सीवीसी द्वारा जांच चल रही है. जांच 53,000 करोड़ रुपये के घपले से जुड़ी है. एक दूसरे प्रकरण में नीरा राडिया द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के उच्चाधिकारियों को रिलायंस के लिए बैंक गारंटी के लिए मैनेज किया गया. यह गारंटी रिजर्व बैंक द्वारा उक्त सूचना के ख़िलाफ़ दी गई, जिसमें कंपनी की वित्तीय गड़बड़ियों का ज़िक्र था.

भारती एयरटेल कंपनी के मालिक सुनील मित्तल ने भी नीरा की सेवाएं अपनी कंपनी के लिए अनौपचारिक तौर पर लीं. मित्तल ने नीरा की सेवाएं टेलीकॉम में तीन कारणों के लिए लीं. पहला टेलीकॉम मंत्रालय का स्पैक्ट्रम मामले में सीडीएमए लॉबी के प्रति रुझान देखते हुए जीएसएम लॉबी के लिए लॉबिंग कराना. दूसरा मित्तल ने नीरा द्वारा दयानिधि मारन को मंत्री बनवाने के लिए लॉबिंग करवाई. सूत्रों के अनुसार, सुनील मित्तल को नीरा से सुहेल सेठ ने मिलवाया था. नीरा राडिया ने मित्तल को अपनी सेवाएं देते समय इस बात का ध्यान रखा कि उनके इस कार्य से कहीं भी टाटा के व्यवसायिक हितों का अहित न हो. नीरा एवं रतन टाटा के बीच टेप हुई बातचीत में तथ्य और उजागर हुआ कि टाटा दयानिधि मारन को टेलीकॉम मंत्री किसी भी हालत में बनने देने के पक्ष में नहीं थे. सूत्रों के अनुसार, नीरा के संबंध ए राजा से काफी नज़दीकी हैं. और, अपने इन्हीं संबंधों के कारण नीरा ने टेलीकॉम मंत्री द्वारा अपने क्लाइंट्स स्वान टेलीकॉम, एयरसेल, यूनीटेक वायरलेस और डाटाकॉम को लाइसेंस दिलवाए. ग़ौरतलब है कि डाटाकॉम में रिलायंस समूह के कर्मचारी मनोज मोदी का पैसा लगा है.

राजनैतिक प्रबंधन के साथ–साथ श्रीमती राडिया विदेशों से भी धन उगाहने के काम में लिप्त हैं. उन्होंने अपने क्लाइंट यूनीटेक के मुंबई प्रोजेक्ट में लेहमैन ब्रदर्स से तीन क़िस्तों में पैसा निवेश करवाया था. पहली क़िस्त लगभग 740 करोड़ रुपये की, शिवालिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, जो यूनिटेक की होल्डिंग है और रोहन डेवलपर्स मुंबई को दी गई. शिवालिक में यूनिटेक के पचास फ़ीसदी शेयर हैं. बकाया राशि दो क़िस्तों में लगभग 550 मिलियन डॉलर के रूप में दी गई. आईबी की इस रिपोर्ट में और भी कई महत्वपूर्ण ख़ुलासे हैं, पर नीरा के ऊंचे सियासी रसूख को देखते हुए लगता है कि ऐसे मामलों से उनका कुछ भी बाल बांका नहीं हो पाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

बड़े पत्रकार, बड़े दलाल

पद्मश्री बरखा दत्त और वीर सांघवी. दो ऐसे नाम, जिन्होंने अंग्रेज़ी पत्रकारिता की दुनिया पर सालों से मठाधीशों की तरह क़ब्ज़ा कर रखा है. आज वे दोनों सत्ता के दलालों के तौर पर भी जाने जा रहे हैं. बरखा दत्त और वीर सांघवी की ओछी कारगुज़ारियों के ज़रिए पत्रकारिता, सत्ता, नौकरशाह एवं कॉरपोरेट जगत का एक ख़तरनाक और घिनौना गठजोड़ सामने आया है. देश की जनता हैरान है कि एनडीटीवी की ग्रुप एडिटर एवं एंकर बरखा दत्त और हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक, मौज़ूदा संपादकीय सलाहकार एवं स्तंभकार वीर सांघवी ने पत्रकार होने के अपने रुतबे और साख को दौलत की अंधी चमक से कलंकित कर दिया. एक सवाल और भी है, जो लोगों को परेशान कर रहा है कि दलाली में इतने बड़े दो नाम एक साथ भला कैसे हो सकते हैं. वैसे मीडिया के लोगों को कमोबेश इस बात की जानकारी है कि वीर सांघवी और बरखा दत्त के बीच क्या कनेक्शन है. पर आम लोगों को शायद ही पता हो कि वीर और बरखा, दोनों ही बेहद घनिष्ठ मित्र हैं. जब वीर सांघवी को न्यूज़ एक्स से इस्तीफ़ा देना पड़ा था, तब कहा गया था कि इसकी वज़ह भी बरखा ही बनी थी. शायद इसलिए दलाली में भी दोनों ने साथ ही हाथ काले किए.

बरखा दत्त

वीर सांघवी

जनवरी 2006 में जब ए राजा पर्यावरण मंत्री थे, तब होटल ताज मानसिंह में बरखा दत्त, वीर सांघवी और नीरा राडिया की एक लंबी मुलाकात हुई थी. नीरा की राजा से यह पहली मुलाकात थी. यह कमरा नीरा राडिया के नाम से बुक था. इसके बाद उनके मिलने का सिलसिला चल निकला. सीबीआई सूत्र बताते हैं कि बात भले ही चार कंपनियों की की जा रही है, पर कंपनियों की कुल संख्या नौ है. कुल तीन सौ दिनों तक नीरा की बातें टेप की गई हैं. जो बातें निकल कर सामने आई हैं, उसकी बिना पर कल यह ख़ुलासा भी हो सकता है कि इन नौ कंपनियों में बरखा और वीर की भी हिस्सेदारी हो.

पिछले दिनों एक कार्यक्रम में प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस गजेंद्र नारायण रे ने टिप्पणी की थी कि आज की पत्रकारिता वेश्यावृत्ति में बदल गई है. बरखा दत्त और वीर सांघवी ने अपने कुकृत्य से उनकी बात पर मुहर भी लगा दी है. पत्रकारिता के पेशे की आड़ में काली कमाई कर रहे इन दोनों नामचीन पत्रकारों के नाम आयकर विभाग और सीबीआई की सूची में बतौर दलाल दर्ज हो चुके हैं. आयकर विभाग और सीबीआई के पास इन दोनों के ख़िलाफ़ सबूतों की लंबी फ़ेहरिस्त है. सीबीआई और आयकर महानिदेशालय के पास मौज़ूद टेपों में इन दोनों दिग्गज पत्रकारों को दलाली की भाषा बोलते हुए साफ़ सुना जा सकता है. सीबीआई की एंटी करप्शन शाखा ने जब टेलीकॉम घोटाले के सिलसिले में नीरा राडिया के ख़िलाफ़ 21 अक्टूबर 2009 को मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू की, तब पाया कि नीरा राडिया अपनी चार कंपनियों के ज़रिए टेलीकॉम, एविएशन, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कॉरपोरेट सेक्टरों के फ़ायदे के लिए बिचौलिए का काम करती हैं. नीरा अपने काम को पूरा कराने के लिए देश के नामचीन पत्रकारों को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जिसकी भरपूर क़ीमत भी नीरा इन पत्रकारों को देती हैं. सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो के डीआईजी विनीत अग्रवाल को जब इस बात के प्रमाण मिले तो उन्होंने आयकर महानिदेशालय के इंवेस्टीगेशन आईआरएस मिलाप जैन से नीरा राडिया से जुड़ी जानकारी मांगी. आयकर महानिदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर आशीष एबराल द्वारा सीबीआई को भेजे गए सरकारी पत्र में जवाब आया कि नीरा राडिया पहले से ही संदिग्ध हैं और इस बिना पर गृह सचिव से अनुमति लेकर नीरा और उनके सहयोगियों का फोन टेप किया जा रहा था. इस दरम्यान ही यह कड़वी हक़ीक़त सामने आई कि वैष्णवी कॉरपोरेट कंसल्टेंट, नोएसिस कंसल्टिंग, विटकॉम और न्यूकॉम कंसल्टिंग कंपनियों के माध्यम से टाटा, अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की ख़ातिर नीरा राडिया बरखा दत्त और वीर सांघवी जैसे रसूखदार पत्रकारों का इस्तेमाल करती हैं. बरखा और वीर सांघवी नीरा राडिया जैसी बिचौलिया के ज़रख़रीद बन सियासी गलियारों में तोल–मोल का खेल रचते हैं. पत्रकारिता के बूते बने अपने संपर्कों का उपयोग वे मंत्रिमंडलीय जोड़–तोड़ में करते हैं. अपने मतलब के कॉरपोरेट घरानों की सहूलियत के मुताबिक़ मंत्रियों को विभाग दिलवाते हैं और बदले में भारी–भरकम दलाली खाते हैं. सबूत कहते हैं कि दलालीगिरी का खेल ये दोनों बहुत पहले से करते आ रहे हैं, पर इनका भांडा फूटा ए राजा को संचार मंत्री बनवाने के बाद. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी नहीं चाहते थे कि आरोपों से घिरे ए राजा को संचार मंत्री बनाया जाए. मनमोहन सिंह ने ए राजा के नाम पर ग़ौर करने तक से मना कर दिया था. मनमोहन सिंह चाहते थे कि देश को अत्याधुनिक सूचना क्रांति से जोड़ कर समाज को समृद्ध बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाने वाला संचार मंत्रालय ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए, जो कॉरपोरेट घरानों की कठपुतली न हो. उसकी छवि बेदाग़ हो. पर नीरा राडिया के हाथों बिक चुके बरखा दत्त और वीर सांघवी ने कांग्रेस के पावर कॉरिडोर में ऐसी ज़बरदस्त घेराबंदी की कि प्रधानमंत्री तो बेबस हो ही गए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी एक न चली. सीबीआई और आयकर विभाग की फाइलों और टेलीफोन टेपों में बरखा और वीर सांघवी के ख़िलाफ़ दर्ज़ साक्ष्य उनकी दलाली की हौलनाक कहानी कहते हैं कि देश के नामचीन पत्रकार होने का इन दोनों ने किस क़दर ओछा लाभ उठाया. नीरा राडिया के हाथों की कठपुतली बन कर दोनों ने ही टाटा और अंबानी जैसे देश के टॉप कॉरपोरेट घरानों को व्यवसायिक फ़ायदा पहुंचाने की गरज़ से लगातार पैरवी कर सरकार के कई नीतिगत फ़ैसलों को बदलवाया. एयरटेल के मालिक सुनील भारती मित्तल के ज़बरदस्त विरोध के बावज़ूद दयानिधि मारन की बजाय ए राजा संचार मंत्री बने तो इसी कारण कि बरखा दत्त और वीर सांघवी जैसे सफ़ेदपोश बड़े पत्रकार राजा की पैरवी कर रहे थे. जांच से यह बात भी सामने आई है कि नीरा राडिया, बरखा दत्त और वीर सांघवी की तिकड़ी पुरानी है. नीरा राडिया की चारों कंपनियों में बतौर अधिकारी तमाम रिटायर्ड नौकरशाहों की भरमार है. इन सभी को वीर सांघवी और बरखा की तैयार की गई सूची के आधार पर ही रखा गया हैं. ये वे अधिकारी हैं, जिन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में ऊंचे पदों पर काम किया है और जिन्हें मंत्रालयों के अंदरूनी कामकाज की बख़ूबी जानकारी है. इन्हें पता है कि मुनाफ़े के फेर में किस तरह सरकार को करोड़ों–अरबों का चूना लगाया जा सकता है. किस तरह विदेशी पूंजी निवेश क़ानून की धज्जियां उड़ा कर अरबों के वारे–न्यारे किए जाते हैं.

बहरहाल, फ़िलहाल तफ्तीश चल रही है. सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच के जिस डीआईजी विनीत अग्रवाल की जांच पर नीरा, बरखा और वीर की दलाली के खेल का पर्दाफ़ाश हुआ है, उनका ट्रांसफर किया जा चुका है. अपनी गिरफ्तारी की आशंका से नीरा राडिया पहले ही देश छोड़कर भाग चुकी हैं. हर ख़बर पर बावेला मचाने वाला मीडिया इस मसले पर चुप है. तो क्या उम्मीद की जाए कि इतने बड़े घोटाले और महान पत्रकारों की दलाली का सच सामने आ पाएगा? अभी एक नाम आना और बाकी है. एक बड़े न्यूज़ चैनल के प्रबंध संपादक का नाम, जो इस तिकड़ी को दलाल चौकड़ी बना देगा. बस कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए.

रूबी अरुण
ruby@chauthiduniya.com

केंद्र की सरकार में शामिल होकर भी ममता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है. वह जानती हैं कि जब भी केंद्र की सत्ता में सांप्रदायिकता का तथाकथित ख़तरा आएगा, कांग्रेस एवं वामदल एक साथ आ जाएंगे.

कांग्रेस और तृणमूल

टूट गया गठबंधन

बिमल राय

कोलकाता नगर निगम चुनावों में महज़ 10 सीटों को लेकर तृणमूल और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूट गया है. इसके साथ ही बाक़ी 80 नगर पालिकाओं पर भी तिकोनी–चौकोनी लड़ाई तय है. आगामी विधानसभा चुनावों की हवा बनाने के लिए इन चुनावों के परिणाम काफी अहम होंगे. पुरानी कहावत है कि नाव वहां डूबी, जहां पानी कम था. 33 सालों से अंगद के पांव की तरह जमे वाममोर्चा को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस और तृणमूल साथ–साथ चल रहे थे, कामयाब भी हो रहे थे, पर जब 2011 के विधानसभा चुनावों से पहले ट्रायल का एक बड़ा मौक़ा आया, तो दोनों ने अलग–अलग राह पकड़ ली. अब वे चुनाव प्रचार के दौरान आपस में ही भिड़ रहे हैं. कोलकाता नगर निगम और 80 नगर पालिकाओं के चुनावों में कामयाबी पाकर वाममोर्चा को हवा का रुख़ पलटने का मौक़ा हाथ लगा है.

इस तरह 30 मई को बंगाल में होने वाले चुनावों ने विपक्ष के दोनों दलों के बीच की ज़ोर आज़माइश को एक निर्णायक लड़ाई में बदल दिया है. इन दलों ने अलग–अलग राह अपना कर जनादेश की परवाह नहीं की और अधिक से अधिक राजनीतिक ज़मीन हथियाने के चक्कर में गठबंधन तोड़ दिया. सीटों पर तालमेल के लिए एक महीने से चल रही कवायद एक मई को कांग्रेस के कोलकाता नगर निगम चुनावों के लिए 88 उम्मीदवारों की सूची जारी करने के साथ ही बेकार हो गई. खिसियाई ममता ने कोलकाता नगर निगम ही नहीं, बाक़ी 80 स्थानीय निकाय चुनाव भी अपने बूते पर लड़ने का फरमान जारी कर दिया है.

वाममोर्चा गदगद है, क्योंकि एक बार वही फ़ार्मूला बन रहा है, जिसके बूते पर उसे पिछले 33 सालों से राज़ करने में सुविधा हुई है. 2008 के पंचायती चुनावों से लेकर पिछले लोकसभा चुनावों तक में जनता ने विपक्ष को अपना संकेत दे दिया, पर बंगाल को ऐसा अभागा विपक्ष मिला है, जिसे घर आई लक्ष्मी को संभाल कर रखना नहीं आ रहा. जनादेश के घोड़े पर सवार दोनों दलों ने लगाम की एक–एक रस्सी पकड़ ली है और उसे किसी आत्मघाती खाई की तरफ़ ले जाने में लगे हैं. मौजूदा चुनाव यह तय करने वाले हैं कि 2011 में बंगाल पर राज किसका होगा? मालूम हो कि 2005 के कोलकाता नगर निगम चुनावों में तत्कालीन मेयर सुब्रत मुखर्जी ने स्व. गनी ख़ान चौधरी एवं प्रणब मुखर्जी को विश्वास में लेकर एक महा गठबंधन बनाने की कोशिश की थी. उस समय सुब्रत ने उन्नयन मंच के बैनर तले चुनाव लड़ा था और कांग्रेस से गठबंधन किया था. इस मंच को सिर्फ़ पांच सीटें मिलीं थीं, जबकि कांग्रेस 15 का आंकड़ा बहाल रखने में कामयाब रही थी. पिछली बार ही अगर गठबंधन हुआ होता तो कोलकाता में वाममोर्चा का बोर्ड नहीं बनता. 2005 के चुनाव में तृणमूल और भाजपा गठबंधन ने 45 सीटें जीतीं, जो 2000 में हुए चुनावों से 16 कम थीं. जबकि वाममोर्चा ने 75 वार्डों यानी 2000 की तुलना में 15 ज़्यादा वार्डों पर क़ब्ज़ा जमाया. कांग्रेस 20 वार्डों में जीती और एक सीट निर्दलीय के खाते में गई. वाममोर्चा के घटक दलों में अकेले माकपा को 58, आरएसपी को 6, सीपीआई और फारवर्ड ब्लॉक को 4–4, विद्रोही बांग्ला कांग्रेस, मार्क्सवादी फारवर्ड ब्लॉक और आरजेडी को एक–एक सीटों पर जीत हासिल हुई थी. इस बार भी घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे में कोई हो–हल्ला नहीं हुआ. मालूम हो कि 2005 के नगर निगम चुनाव में वाममोर्चा को 52 प्रतिशत, तृणमूल कांग्रेस को 25 प्रतिशत और कांग्रेस को 16 प्रतिशत मत हासिल हुए थे. इस तरह तिकोनी लड़ाई में वाममोर्चा बाज़ी मार ले गया था. पर तयशुदा जीत भांपकर भी तृणमूल और कांग्रेस ने कोलकाता को लड़ाई का मैदान बना दिया है.

अब यह तय हो गया है कि तृणमूल और कांग्रेस में कोई गठबंधन नहीं होगा और इस तरह कोलकाता नगर निगम सहित राज्य की 81 नगर पालिकाओं का चुनाव परिणाम बंगाल की राजनीति में एक बड़े उलटफेर का संकेत दे सकता है. पिछला लोकसभा चुनाव दोनों दलों ने मिलकर लड़ा था और 42 में से 25 सीटों पर क़ब्ज़ा जमाया था, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं और अगर अंतिम क्षणों में कुछ नहीं हुआ तो तिकोनी–चौकोनी लड़ाई तय है.

यह कहने को तो स्थानीय चुनाव है, पर इसमें केंद्रीय स्तर पर सोनिया गांधी, बंगाल के प्रभारी केशव राव, प्रणब मुखर्जी और ममता के बीच पिछले एक पखवाड़े से बातचीत हो रही थी. 22 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद केशव और ममता के बीच सीटों के बंटवारे पर बैठक हुई, पर कोई नतीजा नहीं निकला. 28 अप्रैल को तृणमूल ने अपने 116 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी. उसके अगले ही दिन कांग्रेस ने 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया. कांग्रेस ने 2005 में जीती गईं 21 सीटें और 30 वैसी सीटें मांगी, जिन पर उसके प्रत्याशी वाम उम्मीदवारों से पराजित हुए. ममता सिर्फ़ चार सीट आगे बढ़ीं. सोनिया गांधी और केशव राव के बीच हुई बातचीत के बाद कांग्रेस ने और 10 सीटों पर मामला रफा–दफा करना चाहा. यानी कुल 35 सीटें. ममता को इतना भी मंज़ूर नहीं हुआ. दिल्ली के कांग्रेसी सूत्रों के मुताबिक़, ममता का अड़ियल रवैया देखकर सोनिया ने ही हरी झंडी दे दी और कांग्रेस ने 88 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया.

कोलकाता में कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि तृणमूल को दी जा रही 25 सीटें वैसी थीं, जहां विपक्ष के प्रत्याशी 9 हज़ार से 19 हज़ार के बीच वोटों के अंतर से हारे थे. यह देखकर कोलकाता के कांग्रेसियों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया. नाराज़ कार्यकर्ताओं का कहना था कि किसी भी चुनाव में ममता कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रही हैं. 24 अप्रैल को ही सीटों पर सहमति बनाने के लिए बड़ा बाज़ार ज़िला कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष पाठक, निगम में पार्टी के नेता प्रदीप घोष, प्रणब राय एवं निर्वेद राय दिल्ली गए और उन्होंने केंद्रीय नेताओं को ज़मीनी हक़ीक़त बताई. वैसे ममता के इरादे भांपना कोई कठिन नहीं है. पिछले लोकसभा चुनावों में उन्होंने कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल की एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी, ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता हताश होकर तृणमूल की शरण में आ जाएं. कांग्रेस इसी वजह से महानगर में अपना जनाधार बचाए रखना चाहती है. कांग्रेस का गणित है कि तालमेल न होने के कारण अगर वाममोर्चा फिर सत्ता में आ जाता है तो उसे राज्य के लोगों से यह कहने में सुविधा होगी कि ममता ने महज़ 10 सीटों के लिए गठबंधन तोड़ दिया. इससे कांग्रेस अगले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी मोलतोल की क्षमता और मज़बूत कर सकेगी. हालांकि ख़तरा यह है कि इसके उलट अगर लोगों ने तृणमूल को मुख्य विपक्ष मानकर उसे बहुमत में ला दिया तो कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी. तब ममता वैसा ही खेल खेल सकती हैं, जैसा उड़ीसा में बीजू पटनायक ने भाजपा के साथ खेला था.

केंद्र की सरकार में शामिल होकर भी ममता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है. वह जानती हैं कि जब भी केंद्र की सत्ता में सांप्रदायिकता का तथाकथित ख़तरा आएगा, कांग्रेस एवं वामदल एक साथ आ जाएंगे. वैसे कोलकाता पर बात चल रही थी और बाहर की कई नगर पालिकाओं पर तृणमूल और कांग्रेस के बीच तालमेल भी हो गया था. कूचबिहार की सभी चार, शांतिपुर की एक और हावड़ा की तीन नगर पालिकाओं पर पूरा तालमेल हो चुका था. इसी तरह हुगली, उत्तर व दक्षिण 24 परगना, नदिया और मुर्शिदाबाद ज़िलों में भी विपक्षी गठबंधन बनने की कगार पर था, पर अब सब कुछ स्वाहा सा लग रहा है. राज्य में नक्सल आंदोलन से निपटने में विफलता, बुनियादी सुविधाओं का चरमराता ढांचा, बरसात में तालाब बन रहे महानगर, पार्क स्ट्रीट का स्टीफन कोर्ट अग्निकांड और महंगाई जैसे मुद्दों से नाराज़ लोगों में अब भी वाममोर्चा के प्रति गुस्सा है, पर विपक्ष के दोनों दल अपनी ताक़त बढ़ाने के चक्कर में जनता का समर्थन गंवाने की कगार पर आ गए हैं. वाममोर्चा ने एक पखवाड़े पहले ही अपनी सूची जारी कर दी और उसके प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं. माकपा ने साफ–सुथरी छवि वाले नेता एवं पूर्व सांसद सुधांशु सील को अघोषित रूप में मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है. फिर भी हवा का रुख़ अब तक वामदलों के ख़िलाफ़ ही है. 2008 के पंचायती चुनावों के बाद से 2009 के लोकसभा चुनावों में वाममोर्चा केवल 42 में से 15 सीटें ही जीत पाया. उसे 43.3 यानी 2004 के चुनावों की तुलना में 7.5 प्रतिशत कम वोट मिले. केवल माकपा के ही वोटों में 2004 की तुलना में 5.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज़ की गई. माकपा ने ख़ुद जांच कराई तो पता चला कि राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 195 पर वह पिछड़ गई है, जबकि 2006 के विधानसभा चुनावों में वामदलों ने 235 सीटें जीती थीं. बाद में हालात तब और ख़राब हो गए, जब वाममोर्चा 28 जून 2009 को हुए चुनावों में 16 में से केवल 3 नगर पालिकाओं पर ही अपना क़ब्ज़ा बरक़रार रख सका. पांच साल पहले वाममोर्चा ने इनमें से 10 पर क़ब्ज़ा किया था.

फोकस में आए कोलकाता नगर निगम इलाक़े में पिछले चुनावों का कैसा असर रहा, इसका विश्लेषण करने से पता चला कि 141 वार्डों में एक 121 पर विपक्ष को बढ़त मिली. अगर विपक्ष के मतों में कुछ गिरावट भी आई हो तो सामान्य बहुमत पाना कोई मुश्किल नहीं है. वर्तमान में वाममोर्चा के 75 और विपक्ष के 66 पार्षद हैं. लेकिन, सबसे सही वर्तमान तो यही है कि तृणमूल और कांग्रेस के बीच तालमेल टूट गया है. यही नहीं, दोनों दलों के बीच झड़पें भी शुरू हो गई हैं. एक मई की रात हावड़ा के शिवपुर में कांग्रेस और तृणमूल समर्थकों के बीच झड़पें हुईं और इलाक़े में रैफ को तैनात करना पड़ा. जिन अन्य 80 स्थानीय निकायों के चुनाव 30 मई को होने हैं, उनमें 54 पर वाममोर्चा, 17 पर कांग्रेस और 14 पर तृणमूल का क़ब्ज़ा है. अगर तालमेल होता तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती. मिसाल के तौर पर उत्तर 24 परगना के औद्योगिक इलाक़े की 20 नगर पालिकाओं में से 19 माकपा के क़ब्ज़े में हैं, जबकि पिछले लोकसभा चुनावों में उसने इस इलाक़े में आने वाली सभी पांच संसदीय सीटें गंवा दीं.

वर्तमान चुनावों के लिए भी माकपा ने एक आंतरिक सर्वे कराया है, जिसमें आशंका जताई गई है कि पार्टी या घटक दल सभी 54 निकायों पर क़ब्ज़ा बरक़रार नहीं रख पाएंगे. माकपा की 15 ज़िला कमेटियों की रिपोर्ट के मुताबिक़, 81 में से 38 नगर पालिकाएं उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मिदनापुर और हुगली में हैं, जहां अभी भी तृणमूल का जोर दिख रहा है. उत्तर बंगाल की सात में से तीन पर वाममोर्चा और बाक़ी पर कांग्रेस का क़ब्ज़ा है. 4 मई को जब मुंबई में रेलवे मोटरमैनों की हड़ताल को लेकर संसद में हंगामा हो रहा था, ममता कोलकाता में बैठकर निगम चुनावों का हिसाब लगा रही थीं. वह दिन उनके लिए काफी अहम भी था. उसी दिन पूर्व मेयर एवं प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुब्रत मुखर्जी ने एक बार फिर कांग्रेस छोड़कर दीदी का दामन थामा तो कोलकाता प्रेस क्लब में बुद्धिजीवियों के एक समूह ने ऐलान किया कि ममता ही राज्य में बदलाव ला सकती हैं. संसद में तृणमूल के मुख्य सचेतक सुदीप बंदोपाध्याय ने ममता के ग़ैर हाज़िर होने का बचाव किया और माकपा नेताओं पर बिफर पड़े तो इसके पीछे तृणमूल का राजनीतिक संकट ही था. वैसे सुब्रत को अपने पाले में लेकर ममता ने कांग्रेस को करारा झटका दिया है. सुब्रत ने दलबदल की हैट्रिक लगाई है, क्योंकि 2000 में वह तृणमूल में थे और फिर 2005 में कांग्रेस में आ गए. इस बार फिर वह तृणमूल में यह कहकर शामिल हुए हैं कि कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया. वैसे तृणमूल के लिए सुकून की बात यह है कि वह चुनाव में खड़े नहीं हुए हैं और सिर्फ़ प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे. वैसे उनकी हिंदीभाषी विरोधी छवि के कारण तृणमूल को नुक़सान उठाना पड़ सकता है. मालूम हो कि सुब्रत ने कहा था कि बिहार के लोगों के कारण ही कोलकाता में गंदगी बढ़ रही है. हिंदीभाषी इस अपमान को भूले नहीं हैं. कलाकार शुभप्रसन्ना की अगुवाई में इन कलम–कूची धारियों ने गठबंधन तोड़ने के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया. यहां बताना ज़रूरी है कि इनमें से ज़्यादातर बुद्धिजीवी दीदी की कृपा से रेलवे की कई कमेटियों में शामिल होकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं. इन सबके बावजूद वाममोर्चा के पास ख़ुश होने की सबसे बड़ी वजह विपक्ष की फूट है, जो उसे अगला विधानसभा चुनाव जीतने की ताक़त देगी. वह लोगों से कह सकेगा कि आप जिन्हें सत्ता सौंपना चाहते हैं, उन्हें मिल–जुलकर रहना भी नहीं आता. जी हां, कांग्रेस और तृणमूल के बीच सत्ता की सगाई टूट गई है. बंगाल की राजनीति में विपक्ष के इन दो दलों के बीच शादी जैसा गठबंधन कभी हुआ ही नहीं. इसे सगाई या लिव–इन–रिलेशनशिप ही कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा. अगर जोड़ मज़बूत होता तो 10 वार्डों के मामूली पैकेज को लेकर यह गठबंधन नहीं टूटता. इससे भले ही केंद्र की सत्ता पर अभी असर न पड़े, पर अगर कोलकाता नगर निगम वाममोर्चा के हाथ में वापस आया तो ममता के मूड को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... कसाब की सज़ा ...धीर

हरिद्वार स्थित मालवीय द्वीप में बैठक कर मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने गंगा एवं पर्यावरण को बचाने की अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दिया.

निशंक सरकार और गंगा प्रेम का पाखंड

तमाम अव्यवस्थाओं के बीच महाकुंभ किसी तरह निबट गया. सूबे की सरकार ने बाक़ायदा इसका जश्न भी मना लिया, गंगा तीरे बैठक करके अपना प्रेम भी बघार लिया, लेकिन वह इस दौरान विभिन्न हादसों में मारे गए तीर्थयात्रियों को श्रद्धासुमन अर्पित करना भूल गई.

राजकुमार शर्मा

महाकुंभ 2010 के सकुशल संपन्न होने के बाद उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्रियों के साथ हरिद्वार स्थित मालवीय द्वीप में बैठक कर मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने गंगा एवं पर्यावरण को बचाने की अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दिया. लेकिन, उन्होंने महाकुंभ में बड़े पैमाने पर हुए सरकारी धन के दुरुपयोग के सवाल को आज भी अनुत्तरित छोड़ दिया. इस कुंभ में पांच सौ करोड़ रुपये ख़र्च किए गए. नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत एवं सांसद हरीश रावत ने सरकार पर सौ करोड़ रुपये से अधिक धन का गोलमाल करने का आरोप लगाया है.

मुख्यमंत्री निशंक ने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों सहित गंगा में डुबकी लगाई और विधिवत गंगा पूजन भी किया. इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे. महाकुंभ की सफलता पर जहां पूरी सरकार इतरा रही थी, वहीं पार्टी के अंदर और बाहर के निशंक विरोधी उन्हें घेरने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ रहे थे. प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि निशंक ने गंगा में गोता लगाकर अपने पाप धोने का जो प्रयास किया, वह तो ठीक है, लेकिन यह कुंभ घोटालों के महाकुंभ के रूप में जाना जाएगा. सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी भी निशंक की पीठ थपथपाने से बचते दिखे. सूत्रों का मानना है कि खंडूरी को गंगा एवं कुंभ के नाम पर सरकारी धन की लूटखसोट बिल्कुल पसंद नहीं आई. पूरे महाकुंभ के दौरान इसी अपयश से बचने के लिए वह निशंक के साथ कहीं खड़े होने से कतराते रहे और किसी मंच अथवा अवसर पर साथ नहीं गए.

गंगा के ऊपर बनने वाले बांधों को साधु-संतों की मांग पर यूपीए सरकार द्वारा निरस्त करने के फ़ैसले पर बिफरने वाले मुख्यमंत्री निशंक का गंगा प्रेम जगज़ाहिर हो चुका है. उत्तराखंड की जनता के हित की बात करके गंगा पर बांध बनाने का समर्थन करने वाले निशंक ने जिस तरह अपने मिशन 2012 को लक्ष्य करके ठेकेदारों एवं स्थानीय लोगों के मध्य धाक जमाने की कोशिश की, उससे साधु-संतों में उनके प्रति ख़ासी नाराज़गी फैली.

गंगा का राह बदलना ख़तरे की घंटी

वैज्ञानिकों ने गंगा के मार्ग भटकने की घटना को एक अपशकुन मानते हुए इसे गंभीरता से लिया है और ख़तरे की घंटी बताया है. उपग्रह से प्राप्त चित्रों के अध्ययन के बाद उत्तराखंड अंतरिक्ष केंद्र ने इस बात का खुलासा किया है. उपग्रह के 2003 और 2006 के चित्रों का मिलान करने पर पता चला कि हरिद्वार शहर से आगे जगजीतपुर से गंगा ने रास्ता बदलना शुरू कर दिया. 40 वर्ष के नक्शों को देखने से इस तथ्य का खुलासा होता है कि गंगा क़रीब 500 मीटर तक अपना मार्ग बदल चुकी है. केंद्र के निदेशक का मानना है कि गंगा ने पूर्व और पश्चिम दोनों में अपना रुख़ किया है. स्थलाकृति के आधार पर दावा किया जा रहा है कि वह यह क्रम उत्तर प्रदेश के भू-भाग में भी जारी रख सकती है. इससे जनसंख्या को ख़तरा उत्पन्न हो सकता है. खेती योग्य ज़मीन भी इसकी चपेट में आ सकती है. उपग्रह से प्राप्त चित्रों से 17 तरह की जानकारियां मिली हैं और उन्हीं के आधार पर 17 बहुविषयक मानचित्रों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया गया है. यह डाटाबेस हरिद्वार के नियोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. चित्रों से हरिद्वार ज़िले के सतही जल, भू-जल, वनस्पति, कृषि योग्य भूमि, वनसंपदा एवं फ़सल चक्र सहित अनेक जानकारियां प्राप्त की जा सकेंगी. गंगा ने वैसे तो ऋषिकेश स्थित त्रिवेणी घाट पर भी अपना रास्ता बदल लिया था, जिससे परेशान प्रशासन ने महाकुंभ में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एक धारा घाट के किनारे से ले जाने का प्रयास किया. घाटों को छोड़ने की बात इलाहाबाद के आगे विंध्याचल के मध्य चुनार तक भी देखने को मिल रही है, जो कि अध्ययन का विषय है. गंगा के प्रति बरती जा रही उपेक्षा किसी भी क्षण मानव के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकती है. गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर इसे बचाने एवं सहेजने की आवश्यकता है.

लोगों का मानना है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के इशारे पर ही यह बैठक आयोजित की गई, ताकि साधु-संतों की नाराज़गी कम की जा सके. गंगा को पहले से ही राष्ट्रीय नदी घोषित कर चुकी मनमोहन सरकार गंगा के सवाल पर कोई कोर कसर बाक़ी नहीं रखना चाहती. उसका मक़सद है कि गंगा के सवाल पर देश के हिंदुओं को एक ज़बरदस्त संदेश दिया जाए और भाजपा से यह मुद्दा छीन लिया जाए.

पिछले आम चुनाव में सूबे की पांचों सीटों पर अपना परचम लहरा चुकी कांग्रेस अब गंगा के मामले में भी भाजपा को पीछे धकेलने की रणनीति में लगी हुई है. खंडूरी सरकार की कार्यप्रणाली के चलते लोकसभा चुनाव में नुक़सान उठा चुकी भाजपा भी निशंक को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही उत्तराखंड को एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित करना चाहती है. इसीलिए आडवाणी, गडकरी, सुषमा स्वराज एवं राजनाथ जैसे वरिष्ठतम नेता निशंक सरकार के ज़रिए भाजपा का ग्राफ बढ़ाने की कोशिश करते नज़र आए.

निशंक सरकार ने गंगा के मामले में जो आत्मघाती क़दम उठाया, उससे वह पूरी तरह बेनक़ाब हो चुकी है. बांधों के सवाल पर बुरी तरह फंसी सरकार की स्थिति माया में दोऊ गए, माया मिली न राम वाली होती नज़र आ रही है. उत्तरकाशी से लेकर हरिद्वार तक गंदे नाले जिस तरह गंगा को मैला कर रहे हैं, उससे सरकार की नियति का अंदाज़ा लग जाता है. एक ओर सरकार पूरी दुनिया को अपने गंगा प्रेम का संदेश देने के लिए गंगा के किनारे कैबिनेट की बैठक करती है, दूसरी ओर शहर के गंदे नालों को रोकने और गंगाजल को पावन बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती. इस दोहरे मापदंड को अब जनता भी समझ रही है. सूबे की सरकार को भी समझना चाहिए कि यह पब्लिक है, सब जानती है. इसे गंगा में एक तरफ़ मैला और दूसरी ओर दूध चढ़ाकर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता. फ़िलहाल निशंक सरकार ने कुंभ की बहती गंगा में हाथ धोने के बाद अपनी सेहत सुधारने के लिए गंगा के घाट पर बैठक करके जनता को जो संदेश देने की कोशिश की, उसमें उसे कितनी सफलता मिलेगी, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता. लेकिन, गंगा तव दर्शनात मुक्ति के वाक्य का अनुपालन कर सरकार ने अपनी मुक्ति का मार्ग खोजने की कोशिश ज़रूर की है. कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि महाकुंभ ने सूबे के भाजपा नेताओं की माली हालत सुधार दी है. महाकुंभ में जिस तरह लूटखसोट के आरोप के साथ निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, उनसे सरकार का बचना कठिन है. एक तरफ़ पूरी सरकार हरिद्वार में जश्न मना रही थी, उसी क्षण कांग्रेस के कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रबंधन की कमी के कारण आधा दर्ज़न से अधिक तीर्थयात्रियों की मौत का शोक मना रहे थे. उस हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित किए बिना सरकार का गंगा में गोता लगाना एक अमानवीय कृत्य है.

feedback@chauthiduniya.com

अब दिल्ली में भी उपलब्ध
जेट इको
LYCOT AUSTRALIA
RIB VEST
100% NATURAL COTTON
E-mail : info@jetknit.com
Web. : www.jetknit.com
बिजनेस पूछताछ : 09311086850

1932–34 के दौरान जब इलाक़े में सांप्रदायिक भावनाएं पूरे शबाब पर थीं, तभी अलवर के मियो किसान हिंसक विद्रोह पर उतर आए.

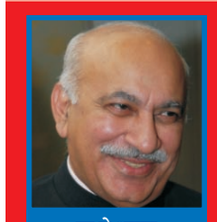

एम जे अकबर

जासूस, जिसने भारत को डरा दिया

माता हारी होने के लिए ख़ूबसूरत होना पहली शर्त नहीं है, आपको बस उपलब्ध होना चाहिए. नीदरलैंड में पैदा हुई और पेरिस में पली-बढ़ी मार्गरेट जेले पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की एक एजेंट थी, जिसने जासूसी को जिस्मानी रिश्तों के परिप्रेक्ष्य में नई पहचान दी. लेकिन जेले वास्तव में बेडौल शरीर की मलिका थी, जिसे ख़ूबसूरत न होने के कारण एक डांसिंग ग्रुप में जगह नहीं मिली थी और मजबूरी में उसे एक सर्कस में काम करना पड़ा था.

किसी ने कहा है कि जेले अपने जिस्म पर कपड़ों के साथ भी उतनी ही अच्छी दिखती थी, जितनी उसके बिना. अब यह उसकी प्रशंसा है या कुछ और, यह तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि जेले को अपने जिस्म की नुमाइश के लिए मजबूर होना पड़ा था. वह अपने पति को छोड़ चुकी थी, जो नीदरलैंड की शाही सेना में अधिकारी था और इंडोनेशिया में तैनात था, लेकिन वह अव्वल दर्जे का शराबी था और शराब के नशे में अक्सर अपनी पत्नी की जमकर पिटाई किया करता था. लेकिन जेले के पास एक अद्‌भुत प्रतिभा थी, हक़ीक़त के साथ सपनों की दुनिया को जोड़ने की. जावा में रहते हुए उसने भारतीय कामकला के रहस्यपूर्ण गूढ़ार्थों को समझा (तभी उसे माता हारी का नाम मिला) और उसके इस नए अवतार का जादू लोगों के दिलोदिमाग़ पर छा गया. सत्य कहें तो वह कोई बहुत बड़ी जासूस नहीं थी, जासूसी से ज़्यादा वह सुख-सुविधाओं की शौक़ीन थी और इसके लिए उसे पैसे चाहिए थे. उसकी इस कमज़ोरी को जर्मन अधिकारियों ने भांप लिया और 1917 में एक फ्रांसीसी दस्ते ने उसे गोलियों से भून डाला.

दोहरा व्यक्तित्व किसी जासूस के लिए पहली शर्त नहीं है, लेकिन यह उपयोगी ज़रूर है. विफलता की हालत में यह दोहरा व्यक्तित्व उसके काम आता है. साथ ही, सपनों की ऊंची उड़ान वास्तविक जीवन में उसे अपने कर्तव्य बोध और नैतिकता से भी दूर ले जाती है. माता हारी के साथ इस तुलना में एक बड़ा अंतर है. माधुरी गुप्ता के हनीट्रैप की इस कहानी में फंसाने का काम मुदस्सर राणा ने किया, हालांकि कामकला में राणा की योग्यता के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन इस मामले में लिंग से कुछ ख़ास फ़र्क़ नहीं पड़ता. अहं और कामलिप्सा के कपटजाल में मर्दों को फंसाना ज़्यादा आसान होता है. 1980 के दशक में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब कराची में पदस्थापित एक शीर्ष भारतीय सैन्य अधिकारी पाकिस्तानी ख़ुफ़िया तंत्र से जुड़ी एक महिला के मोहजाल में फंस गया, लेकिन एक जासूस की मानसिकता नहीं बदल सकती. चूंकि किसी भी हालत में अपने देश के साथ गद्दारी का कोई वाजिब कारण नहीं हो सकता

और लोभ, चाहे वह पैसे का हो या सेक्स का, को सही ठहराने के लिए कारणों की ज़रूरत होती है, तो जासूस अपने तर्कों को वास्तविकता की चादर से ढंकने और उसे सत्य साबित करने की कोशिश करता है. इसके अलावा पेशेवर लोगों के लिए पचास की उम्र बड़ी ख़तरनाक होती है. यह उम्र का वह पड़ाव होता है, जहां करियर उम्मीदों और निराशाओं की दहलीज पर खड़ा होता है. माधुरी इस उम्र में विदेश सेवा में ग्रेड बी स्तर की अधिकारी थी, जबकि विदेश सेवा में उसके हमउम्र अधिकारी अब तक राजदूत बन चुके होते. इस्लामाबाद के भारतीय दूतावास का माहौल ऐसा होता है, जिसने उसकी असंतुष्टियों और सपनों की ऊंची उड़ान को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया होगा. गिरफ़्तारी के बाद उसकी पहली प्रतिक्रिया भी यही बताती है कि वह वास्तविकता से कोसों दूर जा चुकी थी. उसने पुलिस अधिकारियों से पहला सवाल यही किया कि उन्हें इसकी भनक लगने में इतनी देर कैसे लग गई. उसे इसका थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि संस्थाएं ख़ुद अपने ही अधिकारियों को कठघरे में खड़ा करने से बचती हैं. ख़ासकर इसलिए भी कि माधुरी को इस्लामाबाद भेजने का फ़ैसला ख़ुद उसका नहीं था, इसके लिए मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ज़िम्मेदार थे.

अब इस कांड के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराना मूर्खता से ज़्यादा कुछ नहीं है. ख़ुद से परेशान और जीवन से असंतुष्ट एक 54 वर्षीय अधिकारी को वहां भेजना आईएसआई एवं उसके प्रशिक्षित गुर्गों के लिए एक खुला आमंत्रण था. उम्मीदों के मुताबिक़ ही आईएसआई ने इस मामले में सोच-समझ कर क़दम उठाए. राणा माधुरी का हमउम्र था और उसने माधुरी की मानसिक अवस्था को पहचानते हुए उसे ऐसे अंदाज़ में मोड़ा कि वह पाकिस्तानी ख़ुफ़िया तंत्र के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराने का ज़रिया बनने को तैयार हो गई. दिल्ली पुलिस द्वारा माधुरी गुप्ता से पूछताछ तो ज़रूरी है ही, इसके साथ-साथ विदेश मंत्रालय के बंद दरवाज़ों के अंदर भी गहन जांच-पड़ताल की जानी चाहिए. गुप्ता को पाकिस्तान भेजने का फ़ैसला किसने लिया? उसकी मनोदशा को देखते हुए एक साधारण सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी यह बता देता कि इस्लामाबाद जैसी जगह, जहां अधिकारियों के प्रलोभन में फंसने की आशंका ज़्यादा होती है, में नियुक्ति के लिए वह उपयुक्त नहीं थी. ऐसा हो सकता है कि शीर्ष अधिकारियों को लगा हो कि उर्दू बोलने वाले किसी भारतीय मुस्लिम की अपेक्षा माधुरी के किसी प्रलोभन में आने की आशंका कम है और इसी आधार पर उसे इस्लामाबाद भेजने का फ़ैसला लिया गया हो. यह दिल्ली की सत्ता के ख़िलाफ़ कोई आरोप नहीं है, लेकिन यह सही है कि इस तरह की सोच अभी भी मौजूद है. जबकि वास्तविकता यह है कि भारत को शत्रु मानने वाले पाकिस्तानी ख़ुफ़िया अधिकारियों के लिए भारतीय मुसलमानों को फांसना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि भारतीय मुसलमान द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को ही सिरे से नकार देते हैं.

माधुरी गुप्ता के मामले में पाकिस्तान को आंशिक सफलता ही मिली, क्योंकि मामले पर मचे शोरशराबे के विपरीत उसके पास ज़्यादा जानकारियां ही नहीं थीं. यह भी संभव है कि भारतीय अधिकारियों की निगाहों में आने के बाद वह अंजाने में ही ग़लत सूचनाएं पहुंचाने का एक माध्यम बनकर रह गई हो, लेकिन भारत के लिहाज़ से यह एक बड़ी विफलता है. इस तरह के जाल में फंसने वाले मूर्ख होते हैं, जो अपनी जड़ें ख़ुद ही खोद डालते हैं. लेकिन, यहां तो एक भारतीय अधिकारी जो एक महत्वपूर्ण मिशन का हिस्सा थी, ही इस जाल में फंस गई और धीरे-धीरे उसमें डूबती चली गई.

feedback@chauthiduniya.com

मियो किसानों का विद्रोह और तबलीगी जमात

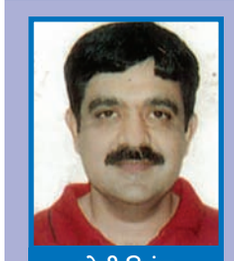

योगी सिकंद

वर्ष 1910 के अंत तक मेवात के मियो बहुल ग्रामीण इलाक़ों में कृषकों की समस्याएं अपने चरम पर पहुंच चुकी थीं. इसके साथ-साथ मियो समुदाय के अंदर शिक्षित लोगों का एक नया तबका भी तैयार हो चुका था, जो खेतिहर मज़दूरों की समस्याओं को आवाज़ दे सकता था. उसने 1932-34 के दौरान मेवात क्षेत्र में किसानों के कई आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की. ख़ास बात यह थी कि इन आंदोलनों में मियो किसानों की आर्थिक मांगों को अखिल भारतीय स्तर पर विस्तृत मुस्लिम समाज की समस्याओं से जोड़कर देखा गया. इस प्रक्रिया का नतीजा यह हुआ कि मियो समुदाय की पहचान इस्लाम धर्म के साथ और गहरी हो गई. इन आंदोलनों को समझे बिना मेवात में तबलीगी जमात के उदय को ठीक से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि 1930 के दशक में इस क्षेत्र में तबलीगी गतिविधियों में अचानक उछाल आया, तो उससे ठीक पहले इन आंदोलनों का भी उदय हुआ था. उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान अलवर और भरतपुर क्षेत्र में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ शासक वर्ग का शत्रुतापूर्ण रवैया अक्सर सतह पर देखने को मिलता है. हालांकि इस दरम्यान कई बार मुस्लिमों ने प्रशासकीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वाह किया, लेकिन बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में इस शत्रुतापूर्ण रवैये में और तल्खी आ गई. (मेहता एवं मेहता 1985:399) अलवर के शासक महाराजा जय सिंह (1892-1937) ने कई ऐसी नीतियों की शुरुआत की, जो स्पष्ट रूप से मुस्लिम आबादी के ख़िलाफ़ थी. इसके साथ-साथ अलवर में शासन व्यवस्था को हिंदूवादी रंग देने की प्रक्रिया भी जारी थी. राजा जय सिंह खुले तौर पर अपने हिंदूवादी रवैये का प्रदर्शन करने लगे और हिंदू महासभा एवं आर्य समाज जैसे हिंदूवादी संगठनों के नेताओं से उनकी नज़दीकियां भी बढ़ने लगीं. मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ इन संगठनों का उग्र रवैया किसी से छुपा नहीं था. संयुक्त प्रांत में मलकाना समुदाय के बीच शुद्धिकरण अभियान शुरू करने के बाद आर्य समाज ने राजपूताना क्षेत्र में भी अपनी इन गतिविधियों का प्रसार करना शुरू कर दिया. इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय राजपूत, जाट, गुर्जर और मियो समुदाय के ऐसे लोगों को दोबारा हिंदू बनाना था, जो धर्मांतरण कर इस्लाम को अपना चुके थे. रोचक तथ्य यह है कि आर्य समाज के इस अभियान को स्थानीय शासकों का भी पूरा सहयोग मिल रहा था. (मायाराम 1991:10-12)

अलवर प्रशासन को हिंदूवादी रंग में रंगने और उसे मुस्लिम विरोधी चेहरा देने की इस कवायद का धर्म से उतना लेना-देना नहीं था, जितना कि शासक के तानाशाही रवैये और कृषि कार्यों पर ज़्यादा कर लगाने के ख़िलाफ़ आम जनता के असंतोष से. राजा के ख़िलाफ़ उभार ले रहे इस असंतोष में मुस्लिमों के साथ-साथ हिंदू भी शामिल थे. 1920 के दशक के मध्य तक किसानों के उक्त आंदोलन राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैल चुके थे. 1925 में निमूचाना गांव में ऐसे ही एक विद्रोह ने गंभीर रूप धारण कर लिया और अलवर सेना ने जवाबी कार्रवाई में बड़ी संख्या में हिंदू राजपूतों को गोलियों से छलनी कर दिया. उक्त किसान भू-राजस्व की दर में अचानक पचास प्रतिशत बढ़ोत्तरी का विरोध कर रहे थे. इन विद्रोहों में मियो के अलावा हिंदू किसान भी शामिल थे. अपने ख़िलाफ़ लगातार बढ़ते विरोध को देखते हुए राजा को लगा कि हिंदू समर्थक छवि बनाने से हिंदू समुदाय उसके पक्ष में लामबंद हो जाएगा और प्रशासन के लोकतंत्रीकरण की मांग कमज़ोर पड़ जाएगी. उसे लगा कि मुस्लिमों को शत्रु के रूप में प्रचारित कर और हिंदू-मुस्लिम अंतर्विरोध की भावना को भड़का कर हिंदू जनता का ध्यान शासकीय दमन से भटकाया जा सकता है.

1932-34 के दौरान जब इलाक़े में सांप्रदायिक भावनाएं पूरे शबाब पर थीं, तभी अलवर के मियो किसान हिंसक विद्रोह पर उतर आए. ऐसा लगता है कि शासन की दमनकारी नीतियों ने उनके विद्रोह को हवा दी थी. किसानों की व्यथा का चित्रण करते हुए एक मियो इतिहासकार ने लिखा है, अलवर और भरतपुर मियो बहुल इलाक़े शासकों के उग्र दमन और तानाशाही रवैये के शिकार थे. सरकारी अधिकारी बिना घूस लिए कोई काम नहीं करते थे. किसानों पर टैक्स का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था. वन विभाग और टैक्स अधिकारी शिकारी कुत्तों की तरह उनके पीछे लगे रहते थे और उनकी उस आय को भी छीन ले जाते थे, जो उनके ख़ून-पसीने की कमाई होती थी. जनता के अधिकारों को खुलेआम दबाया जा रहा था. मेवाती जनता की हालत

भेड़-बकरियों जैसी होकर रह गई थी. जनता पहले से ही भारी-भरकम टैक्स के बोझ तले दबी थी. इसके बावजूद अलवर के महाराजा ने 1932 में राजस्व दर में अचानक चार गुना वृद्धि की घोषणा कर दी. इस आदेश ने किसानों के सब्र का बांध तोड़ दिया और उन्होंने कर न देने का फैसला कर लिया. इसके ठीक बाद मियो नेताओं के एक संगठन ऑल इंडिया मियो पंचायत के प्रतिनिधियों ने यासिन ख़ान से संपर्क साधा. यासिन ख़ान वकालत छोड़कर राजनीति के मैदान में उतरे थे. उन्होंने इस विद्रोह के लिए समर्थन जुटाना शुरू किया, ताकि इसे राज्य में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए एक व्यवस्थित संघर्ष के रूप में संगठित किया जा सके. धीरे-धीरे यह आंदोलन विद्रोह में परिवर्तित होने लगा और मेवात के अधिकांश इलाक़ों में फैल गया. यहां तक कि ब्रिटिश प्रभाव वाले मियो बहुल क्षेत्रों में भी मियो किसानों ने साहूकारों का क़र्ज़ चुकाने से इंकार कर दिया. अलवर के महाराज ने विद्रोह को कुचलने में अपनी सारी ताक़त लगा दी. जनवरी 1933 में अपना विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में किसान गोविंदगढ़ गांव में एकत्र हुए थे, तभी सैनिकों ने उन पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी और सैकड़ों किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

अब पूरा मेवात विद्रोह की आग में झुलस रहा था. रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ एवं तिजारा की मियो बहुल रियासतों में मार्शल लॉ लगा दिया गया और मियो किसानों के साथ हिंदुओं के टकराव की ख़बरें पूरे राज्य से आने लगीं. मियो किसानों द्वारा हिंदू साहूकारों की दुकानों पर हमला कर लूटपाट करने की वारदातें भी हुईं. चारों ओर फैली हिंसा का असल कारण आर्थिक था. किसान साहूकारों और अलवर प्रशासन की दमनकारी नीतियों से परेशान थे, लेकिन इसने जल्द ही धार्मिक रंग ले लिया. हिंदुओं के मंदिरों पर हमले होने लगे और हिंदू महासभा के उकसावे में आकर आतंकित जनता ने अलवर के राजा से मदद की गुहार लगाई. हिंदुओं ने राजा से मियो राक्षसों से बचाने की अपील की. तथ्य यह भी बताते हैं कि मियो बहुल इलाक़ों में राजा की सत्ता का कोई असर नहीं रह गया था. मियो किसानों ने इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था. अलवर के उत्तरी हिस्से में कुछ सप्ताहों में ही हालत ऐसी हो गई कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा. जनवरी 1933 में ब्रिटिश सैनिक अलवर में घुस आए और मई आते-आते सरकार ने अलवर के महाराजा को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया. उन्हें अज्ञातवास में विदेश जाना पड़ा. राज्य का प्रशासन एक ब्रिटिश अधिकारी के हाथों में सौंप दिया गया, किसानों की कई मांगें मान ली गईं और धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा.

विद्रोह के दौरान मियो किसानों का संपर्क पहली बार मेवात के बाहर के मुस्लिम नेताओं और संगठनों से हुआ. विस्तृत भारतीय मुस्लिम समाज के साथ बने इस नए संबंध ने बाद के दिनों में तबलीगी जमात के प्रयासों के माध्यम से मियो किसानों के बीच इस्लामी विचारधारा के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई. अलवर के महाराजा के ख़िलाफ़ संघर्ष और उसकी दमनकारी नीतियों के ख़िलाफ़ उभरे विद्रोह का नेतृत्व इन्हीं नेताओं ने किया था. इनमें कुछ तो स्थानीय थे, लेकिन अधिकतर मेवात से बाहर के थे. मियो जनता के असंतोष को देश की जनता और ब्रिटिश अधिकारियों के सामने लाने में कई मुस्लिम संगठनों ने उनकी मदद की थी. इनमें ऑल इंडिया अलवर कांफ्रेंस, दिल्ली और बंबई के अंजुमने अहरार, बदायूं के जमायतुल-उलेमा-ए-इस्लाम और अजमेर के राजपूताना मुस्लिम लीग का नाम लिया जा सकता है. दिल्ली और लाहौर के कई उर्दू अख़बारों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई. (मायाराम 1991:40-41) ग़ौरतलब है कि मियो किसानों के संघर्ष को हिंदुओं से कोई समर्थन नहीं मिला, संकट की इस घड़ी में मुस्लिम समाज ही उनकी मदद के लिए आगे आया.

मेवात से बाहर के इन मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने मियो किसानों के विद्रोह की शुरुआत नहीं की थी, लेकिन यह उनके प्रयासों का ही नतीजा था कि किसानों की मांगों का बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ. (मायाराम 1991:40)

विद्रोह की शुरुआत के बाद शेष उत्तर भारतीय मुस्लिम समाज के साथ इसका संपर्क बना था, इसलिए विद्रोह के लिए उन्हें ज़िम्मेदार ठहराना ग़लत होगा. इसी तरह मेवात क्षेत्र के अंदरूनी इलाक़ों में तबलीगी जमात की गतिविधियां भी विद्रोह की शुरुआत के बाद ही बढ़ी थीं. फिर भी, तबलीगी जमात की धार्मिक विचारधाराओं का प्रचार करने वाले समूह इस समय तक ब्रिटिश अधिकार वाले मेवात क्षेत्र तक ही सीमित थे. अलवर या भरतपुर के राज्यों में उनकी उपस्थिति नहीं के बराबर थी. (मायाराम 1997:35) इस नज़रिए से देखें तो मेवात क्षेत्र में तबलीगी जमात की अचानक बढ़ी लोकप्रियता मियो किसानों के असंतोष का कारण नहीं थी, बल्कि इसका परिणाम था. मायाराम भी यही कहते हैं कि तबलीगी जमात के माध्यम से मियो किसानों के बीच इस्लामीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसानों के विद्रोह के बाद हुई थी. वास्तव में यह सरकार की दमनकारी नीतियों और इसके ख़िलाफ़ किसानों के असंतोष का ही एक नतीजा था. इसे किसी बाहरी धार्मिक विचारधारा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसकी जड़ें तत्कालीन मेवाती सामाजिक परिस्थितियों में गहरी जमी हुई थीं. (मायाराम 1991:8)

मायाराम का मानना है कि मियो किसानों के विद्रोह को अलवर राज्य और हिंदू संगठनों द्वारा एक इस्लामिक विद्रोह के रूप में प्रचारित करने के पीछे असली मंशा इसके वास्तविक चरित्र को छुपाना था. वे किसानों को धार्मिक आधार पर बांटना चाहते थे, ताकि हिंदू किसानों का ध्यान राजा के अलोकतांत्रिक रवैये से दूर मियो समुदाय के ख़िलाफ़ भटकाया जा सके. लेकिन, इस नीति का एक दूसरा पक्ष भी था. इसने मियो किसानों को उनकी मुस्लिम पहचान के प्रति और भी उग्र रवैया अपनाने को मजबूर कर दिया. 1933 में पड़ोस के भरतपुर राज्य में भी ऐसा ही हुआ, जहां मियो किसानों ने जाट शासक किशन सिंह की दमनकारी नीतियों के ख़िलाफ़ विद्रोह का बिगुल बजा दिया. इस तरह से देखा जाए तो मेवात क्षेत्र में तबलीगी जमात की लोकप्रियता के पीछे कई कारण थे. मियो समुदाय के बीच एक शिक्षित तबके का उदय, अलवर-भरतपुर में किसानों का विद्रोह एवं निर्मम दमन और विद्रोह के दौरान मेवात से बाहर के मुस्लिम नेताओं एवं संगठनों के साथ किसानों के जुड़ाव आदि ने इसके लिए पृष्ठभूमि तैयार की थी.

feedback@chauthiduniya.com

राजनीति, सिनेमा और क्रिकेट

चौथी दुनिया यहां बहुत देर से मिलता है. हम इसे तब तक पढ़ते रहते हैं, जब तक अगला अंक नहीं मिल जाता. 5-11 अप्रैल का अंक मिला तो हम लोगों ने शुरू से आख़िर तक पढ़ा. जिन्हें राजनीति, सिनेमा और क्रिकेट पसंद नहीं, उन्होंने भी इन विषयों पर आधारित

सारे लेख पढ़े. वास्तव में इन तीनों ने जनजीवन में ऐसा ज़हर घोल दिया है, जिसने आम आदमी का सुख-चैन सब छीन लिया है. सिर्फ़ मुट्ठी भर लोग राजनीति, सिनेमा और क्रिकेट पर इस तरह छा गए हैं कि वे अपनी तिजोरियां भरते जा रहे हैं और आम जनता महंगाई, बेकारी एवं भ्रष्टाचार के बोझ तले दबकर सांस नहीं ले पा रही है. उम्मीद है, चौथी दुनिया इसी तरह निडरता से सच सामने लाकर जनता को जागरूक करने का काम जारी रखेगा.

-कैलाशी देवी शर्मा, *हुगली, पश्चिम बंगाल.*

आईपीएल का सच

03-09 मई के अंक में प्रकाशित आईपीएल की कहानी ने झकझोर कर रख दिया. हमने फिक्सिंग के खेल में फंसे खिलाड़ियों, राजनीतिज्ञों और फिल्मी सितारों के बारे में जाना. कहीं यह चिंगारी शाहरुख़ ख़ान को न जला दे, लेख भी बढ़िया लगा. ललित मोदी के कारनामे पढ़कर अचरज हुआ. आईपीएल का काला चिट्ठा जनता के सामने पहली बार किसी अख़बार ने खोलकर रखा. बधाई का पात्र है चौथी दुनिया.

-अर्जुन सिंह, *पटना, बिहार.*

सूचना का अधिकार

हमारी दुनिया पृष्ठ पर छपा लेख-सरकारी दस्तावेज़ देखना आपका अधिकार है, ज्ञानवर्द्धक है. अमूमन जनसामान्य को यह पता ही नहीं होता कि वह कौन सी जानकारी पा सकता है, कौन सी नहीं. अगर पा सकता है तो कैसे. आरटीआई की यह सीरीज़ पाठकों को निस्संदेह लाभांवित करेगी, ऐसा विश्वास है.

-मोहनलाल जायसवाल, *रायबरेली, उत्तर प्रदेश.*

पाकिस्तानी मंत्री और मुंबई

03-09 मई के तोप मुक़ाबिल कॉलम के तहत पाकिस्तान की मंत्री डॉ. फिरदौस के मुंबई दौरे के बारे में पढ़ा. उन्होंने सही कहा कि न हम जीत सकते हैं और न ही पाकिस्तान. समस्या का हल जब केवल बातचीत से ही निकल सकता है तो इसमें देर आख़िर क्यों की जाए. उनका यह कहना भी सही है कि दहशतगर्दों की न कोई कौम होती है, न मजहब और न मुल्क. स्तंभ में आपने जो सुरक्षा व्यवस्था में कमी संबंधी इशारा किया, वह वाकई काफी गंभीर है. सरकार को इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए.

-अचला सक्सेना, *ग्वालियर, मध्य प्रदेश.*

ज्ञानवर्द्धक आलेख

योगी सिकंद का आलेख-मियो समुदाय और तबलीगी जमात (03-09 मई) एक वर्ग-आंदोलन विशेष पर बारीकी से प्रकाश डालता है. लेखक अपने उद्देश्य में सफल है. इस तरह की जानकारियां हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं. आशा है कि ऐसे आलेख आगे भी पढ़ने को मिलते रहेंगे.

-त्रिलोक कुमार झा, *द्वारका, नई दिल्ली.*

आम जनता का क्या होगा

03-09 मई के अंक में बाटला हाउस मुठभेड़ कांड पर छपा आलेख अच्छा लगा. केंद्र सरकार द्वारा उच्चस्तरीय जांच की मांग को ठुकराने का मतलब क्या है, यह समझ से परे है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद सरकारी रवैये पर उंगली उठना भी लाज़िमी है. आतंकवाद के नाम पर अल्पसंख्यक वर्ग को निशाना बनाने का यह खेल देश में गंभीर रूप धारण करता जा रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं देना चाहती. पुलिस और सुरक्षाबल सरकार के इस रवैये का फ़ायदा उठाकर लगातार निरंकुश होते जा रहे हैं. मुठभेड़ के बहाने आम लोगों को सरेआम गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है और सरकार सुरक्षातंत्र का मनोबल कमज़ोर होने का बहाना करके उस पर कार्रवाई से इंकार कर देती है. सवाल यह है कि इस देश में आम जनता के लिए सोचने वाला कौन है?

-पारुल सिंह, *आरके पुरम, नई दिल्ली*

आतंकवाद का सबसे वीभत्स रूप है साइबर आतंकवाद

साइबर आतंकवाद पर जस्टिस राजेश टंडन का आलेख रुचिकर लगा. तकनीकी विकास के इस आधुनिक दौर में जबकि हमारा जीवन अधिकाधिक रूप से कंप्यूटर और मोबाइल पर निर्भर होता जा रहा है, साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या लगातार चिंता का कारण बनती जा रही है. साइबर अपराधों का सबसे ख़तरनाक पहलू यह है कि इसे कहीं से भी अंजाम दिया जा सकता है और हमें ख़बर भी नहीं होती. आतंकवाद के इस सबसे वीभत्स स्वरूप से निपटने के लिए लोगों के बीच इस संबंध में जागरूकता पैदा करना सबसे ज़रूरी काम है. इस लिहाज़ से चौथी दुनिया का यह प्रयास वास्तव में एक सराहनीय क़दम है. उम्मीद है, आप आगे भी ऐसे तथ्यों को अपने अख़बार में जगह देते रहेंगे.

-नरेंद्र तोमर, *गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश.*

चौथी दुनिया को सलाम

मेरे विचार से चौथी दुनिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को मज़बूती प्रदान करेगा. यह दिनोंदिन अपने विचारों में नयापन और खबरों में ताजगी लाएगा. यह अख़बार हर ऐसे मुद्दे को उठाएगा, जो जनता से सीधे जुड़ा है. चौथी दुनिया परिवार को मेरा सलाम.

-रविदत्त, *ई-मेल से.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें.
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

हिटलर और मुसोलिनी की राह पर मत चलिए

हमारे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बहुत बहादुर और दूरदर्शी हैं. उन्हें माओवादियों से लड़ने और उनकी बात किसी के पास न पहुंचे, इसका एक नायाब तरीक़ा मिल गया है. इन्होंने एक आदेश जारी कर कहा है कि देश का कोई भी सोचने-समझने वाला माओवादियों द्वारा उठाए गए सवालों पर बातचीत नहीं करेगा. सभ्य समाज में सोचने-समझने वाले लोगों को बुद्धिजीवी कहा जाता है. गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ माओवादी नेता कुछ ग़ैर सरकारी संगठनों और बुद्धिजीवियों से सीधे संपर्क कर रहे हैं, ताकि अपनी विचारधारा का प्रचार कर सकें. जो भी व्यक्ति इस तरह के आतंकवादी संगठन का समर्थन करने का अपराध करेगा और इस तरह के समूहों की गतिविधियों को विस्तार देने का इरादा रखेगा, उसे ग़ैर क़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) क़ानून 1967 की धारा 39 के तहत अधिकतम 10 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं. इस लंबे बयान में आगे कहा गया है कि आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि वह माकपा (माओवादी) के दुष्प्रचार के प्रति सतर्क रहे और इसका अनजाने में शिकार न बने. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) और उसके सभी घटक तथा मुखौटा संगठन आतंकवादी संगठन हैं, जिनका एक ही मक़सद है-भारत सरकार को हथियार के बल पर उखाड़ फेंकना. उनके लिए भारत के संसदीय लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है. आम जनता को ज्ञात होना चाहिए कि अवैध गतिविधियां अधिनियम 1967 के खंड 39 के अधीन कोई भी व्यक्ति, जो इस प्रकार के आतंकवादी संगठन को समर्थन देने का अपराध करता है, उसे दस साल की जेल या जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं. बयान में कहा गया है कि भाकपा (माओवादी) लगातार आदिवासियों सहित बेकसूर नागरिकों की हत्या कर रही है और सड़कों, पुलों, स्कूली इमारतों एवं ग्राम पंचायत भवनों जैसी अहम संरचना को नुक़सान पहुंचा रही है, ताकि अल्प विकसित क्षेत्रों में विकास होने से रोका जा सके.

हमारी जनप्रिय सरकार कितनी चिंतित है कि आदिवासी क्षेत्रों में तेज़ी से विकास हो, पर माओवादी उसे रोक रहे हैं. महाश्वेता देवी जैसी वरिष्ठ साहित्यकार इन क्षेत्रों में विकास क्यों नहीं देख पातीं. पत्रकार जाते हैं तो क्यों उन्हें भूखे-नंगे लोग, बिना साधनों के जानवरों सी ज़िंदगी जीते लोग दिखाई देते हैं. बुद्धिजीवियों की आंखें ख़राब हो गई हैं, इसीलिए उन्हें दंतेवाड़ा, लालगढ़, उड़ीसा, आंध्र में विकास की बहती गंगा नहीं दिखाई पड़ती. इनके इलाज की सचमुच ज़रूरत है.

प्रधानमंत्री और उनका गृह मंत्रालय आईपीएल के वाटरगेट को दबाने में शरद पवार और ललित मोदी के साथ कामयाब हो गया. लाखों करोड़ रुपया आईपीएल के घोटाले में विदेशों में चला गया. इस देश के आम आदमी को जमकर बेवकूफ बनाया गया. वह समझ रहा था कि वह सचमुच क्रिकेट देख रहा है, लेकिन वह तो बंदर का तमाशा था. इस बंदर के तमाशे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक को शामिल कर लिया गया. दोनों को पता ही नहीं चला कि वे कब आईपीएल के अपराधियों के साथ खड़े हो गए. पैसा मॉरीशस के ज़रिए किसका आया, कभी पता नहीं चलेगा. क्या दाऊद इब्राहिम का पैसा है? प्रणव मुखर्जी ने पूरी जांच की बात कह दी, लेकिन एक तिहाई भी जांच नहीं हो पाएगी. नरेगा या मनरेगा का सारा पैसा प्रभुत्व वाले लोगों और अधिकारियों के बीच बंट रहा है. जहां भी सोशल ऑडिट हो रही है, कहीं कुछ नहीं मिलता. ग़रीब वहीं का वहीं है, उसकी रोटी भी पैसे वालों के पास जा रही है.

इस तंत्र ने गांव स्तर पर भ्रष्टाचार फैला दिया है. भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा यह है कि कुछ जगहों पर तो अफसर गिड़गिड़ाते हैं कि कुछ काम तो कर लो, कम से कम फ्लैश लैट्रिन ही बना लो. राहुल गांधी के पिता ने कहा था कि ग़रीब के पास केवल पंद्रह पैसे ही पहुंच पाते हैं और राहुल गांधी का मानना है कि अब यह स्तर आठ पैसे पर पहुंच गया है. वर्गों की बात करें तो दलित, मुसलमान, आदिवासी और गांवों की बात करें तो लगभग सारा हिंदुस्तान इस आठ पैसे के विकास के इर्द-गिर्द घूम रहा है.

हमारी जनप्रिय सरकार कितनी चिंतित है कि आदिवासी क्षेत्रों में तेज़ी से विकास हो, पर माओवादी उसे रोक रहे हैं. महाश्वेता देवी जैसी वरिष्ठ साहित्यकार इन क्षेत्रों में विकास क्यों नहीं देख पातीं. पत्रकार जाते हैं तो क्यों उन्हें भूखे-नंगे लोग, बिना साधनों के जानवरों सी ज़िंदगी जीते लोग दिखाई देते हैं. बुद्धिजीवियों की आंखें ख़राब हो गई हैं, इसीलिए उन्हें दंतेवाड़ा, लालगढ़, उड़ीसा, आंध्र में विकास की बहती गंगा नहीं दिखाई पड़ती. इनके इलाज की सचमुच ज़रूरत है.

पर यह इतना बड़ा मसला कहां है, जो सरकार ध्यान देगी. टेलीकॉम स्कैंडल सामने आता है, ए राजा को हटाना तो दूर, पूछताछ करने की हिम्मत प्रधानमंत्री नहीं जुटा पाते, क्योंकि करुणानिधि धमका कर जा चुके हैं. सरकार का कहीं ज़ोर नहीं चलता, चलता है तो निरीह बुद्धिजीवियों पर, जो सिर्फ़ आपस में ग़रीबी, बेकारी, भुखमरी, ग़ैर बराबरी, महंगाई और मौत पर बात कर सकते हैं. न इनमें कुछ करने की ताक़त है और न हिम्मत. पर सरकार को बात करने का अधिकार भी गंवारा नहीं. वह अपनी नामर्द बहादुरी बुद्धिजीवियों और ग़रीबों पर दिखाना चाहती है.

इसका परिणाम होगा कि एनजीओ के रूप में काम करने वाले लोग, दलितों-अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग तथा अख़बारों में कॉलम लिखने वाले बहुत से लोग किसी दारोगा के कभी भी शिकार बन जाएंगे, क्योंकि उसे गृह मंत्रालय ने यह अधिकार दे दिया है. यह आदेश कहता है कि आदिवासी क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों में चलने वाला माओवादी आंदोलन सरकार के ख़िलाफ़ हथियारबंद युद्ध है. इससे बड़ा दिमाग़ी दिवालियापन क्या होगा कि भारत सरकार राज्यों की ज़िम्मेदारी अपने सिर ओढ़ रही है. जिन आठ राज्यों में नक्सलवादी समस्या प्रमुखता से है, उनमें केवल एक में कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, बाक़ी में ग़ैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं. चिदंबरम साहब ने सारी राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी अपने सिर ले ली है.

विडंबना इस देश की है कि इस देश में ऐसे लोग फ़ैसले कर रहे हैं, जिन्हें देश में रहने वालों की तकलीफ नहीं दिखाई देती, उसके कारण नज़र नहीं आते. वे ऐसे बददिमाग़ पागल डॉक्टर की तरह हैं, जो एपेंडिक्स के दर्द से चिल्लाते मरीज़ को डांटता है, क्योंकि उसके चिल्लाने से उसकी नींद में खलल पड़ रही है. विपक्ष को भी क्या कहें, जिसे वही नज़र आता है जो सरकार उसे दिखाती है. अख़बार न हों तो उसके पास लोकसभा व विधानसभा में उठाने वाले विषय ही न हों. और पत्रकारों का क्या कहें. बड़े पत्रकारों के रिश्ते आईपीएल से जगज़ाहिर हैं. वीर संघवी और बरखा दत्त जैसों के नाम बड़े दलालों की तरह लिए जा रहे हैं. लोगों की समस्याओं पर नज़र डालना तो दूर, जो नज़र जा रही है उसे दबाने का काम पत्रकारों का एक तबका जोर-शोर से कर रहा है.

केंद्र सरकार को इसलिए चेतना चाहिए, क्योंकि इतिहास भी एक वास्तविकता है. हम जब भी हिटलर, मुसोलिनी का नाम लेते हैं घृणा से लेते हैं. मनमोहन सिंह और गृहमंत्री चिदंबरम को आने वाले वक़्त में इतिहास लोकतंत्र समर्थक के रूप में याद करे, लोकतंत्र बरबाद करने वालों में नहीं. इतनी अपेक्षा और आशा तो हम कर ही सकते हैं. उसी तरह विपक्षी दलों और पत्रकारों से कहना चाहते हैं कि अपने को बेबस, बेसहारा, ग़ैर जानकार या ख़रीदे हुए लोगों की तरह मत इतिहास में दर्ज होने दीजिए.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मुशर्रफ़ की सुरक्षा पर प्रतिदिन 25 हज़ार पौंड का ख़र्च!

एक निजी टेलीविज़न की रिपोर्ट के अनुसार, बेनज़ीर भुट्टो हत्याकांड पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट सामने आने के बाद पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ से सरकारी प्रोटोकॉल और सुरक्षा वापस ले ली गई है. ब्रिटिश सरकार ने रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद परवेज़ मुशर्रफ़ की सुरक्षा में लगे जवानों की वीज़ा अवधि बढ़ाने से भी इंकार कर दिया. साथ ही स्कार्टलैंड यार्ड की ओर से दी गई बुलेटप्रूफ़ कार भी वापस ले ली गई. इधर पाकिस्तान के गृहमंत्री ने उक्त ख़बर को झूठा बताते हुए कहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल उनका अधिकार है और सरकार की ज़िम्मेदारियों में शामिल है. इसलिए पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ की सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल को ख़त्म नहीं किया गया और न ही इसका कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया.

अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक तीसरी ख़बर से परिचित कराना आवश्यक समझता हूं. पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के ख़िलाफ़ संविधान के अनुच्छेद छह के अंतर्गत गद्दारी का मुक़दमा दर्ज करवाने के लिए न्यायालय में दायर याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया गया है. याचिका में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने जो क़दम उठाए थे, उन्हें न्यायाधीशों द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है. इसलिए

परवेज़ मुशर्रफ़ की भलाई इसी में है कि वह सियासत में आने की सोचें भी नहीं. देश की जनता और संसद अब भी मुशर्रफ़ को नापसंद करती है. वह अब भूतकाल का हिस्सा बन चुके हैं. मुशर्रफ़ के सत्ता पर क़ब्ज़ा करने से पहले फौज लोमड़ी की तरह चालाकी से सरकार पर क़ब्ज़ा कर लेती थी. मुशर्रफ़ ने एक हाथी की तरह देश, सत्ता, राजनीति और लोकतंत्र को रौंद कर रख दिया.

उनके ख़िलाफ़ ग़द्दारी का मुक़दमा क़ायम किया जाए. लाहौर उच्चतम न्यायालय ने याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. मेरे हिसाब से जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ का प्रोटोकॉल और सुरक्षा का सूरज ढल चुका है. पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था पर ब्रिटिश सरकार को प्रतिदिन 25 हज़ार पौंड ख़र्च करना पड़ रहा है (या था). इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त वाजिद शम्सी अलहसनी ने कुछ समय पहले दी न्यूज़ को दिए गए अपने साक्षात्कार में बताया था कि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग लंदन को निर्देश जारी किए हैं कि पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को संपूर्ण प्रोटोकॉल उपलब्ध कराया जाए. हम इस्लामाबाद से प्राप्त होने वाले निर्देशों पर अमल के लिए प्रतिबद्ध हैं. लिहाज़ा हम संपूर्ण प्रोटोकॉल उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें सुरक्षा में तैनात फौज के सात जवान भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्व तानाशाह ने अपने दौर में भी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया था और अब रिटायर्ड होने के बाद भी अपने साथ रख लिया है. पूर्व राष्ट्रपति के साथ एक फौजी अफसर कर्नल इलियास तैनात हैं, जो तीन साल पूर्व गृह मंत्रालय में डेपूटेशन पर चले गए थे. कर्नल इलियास के अलावा सुरक्षा के इस अमले में पाकिस्तानी फौज के 12 अधिकारी शामिल हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति द्वारा दक्षिणी लंदन में ख़रीदे गए फ्लैट पर सुरक्षा सेवा प्रदान करते हैं. उच्चायोग ने परवेज़ मुशर्रफ़ की लंदन रवानगी के समय एक बुलेटप्रूफ़ कार प्रोटोकॉल अधिकारी के साथ भेजी है. साथ ही उच्चायोग उनके लिए वीआईपी व्यवस्था भी कराता है. लंदन में परवेज़ मुशर्रफ़ की सुरक्षा के लिए 12 नियमित अधिकारी तैनात किए गए हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय कोष से वेतन भी ब्रिटिश समाज के अनुसार दी जा रही है. इस 12 सदस्यीय टीम में कर्नल मेजर, नायक, हवलदार और सिपाही रैंक के जवान शामिल हैं. यह टीम सुरक्षा के अलावा पूर्व राष्ट्रपति को प्रतिदिन की सेवाएं भी प्रदान करती है. जबकि मेरी जानकारी के अनुसार, पाक फौज के मौजूदा नियमों के तहत किसी भूतपूर्व आर्मी चीफ को ऐसे प्रोटोकॉल की अनुमति नहीं है.

भूतपूर्व आर्मी चीफ मिर्ज़ा असलम बेग ने एक इंटरव्यू में फौज की परंपराओं के बारे में बातचीत करते हुए बताया था कि भूतपूर्व आर्मी चीफ को रिटायरमेंट के बाद एक बीटमैन, एक पर्सनल सेक्रेटरी, एक ड्राइवर और आर्मी टेलीफोन प्रदान करने के नियम होते हैं. फिर भी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दूसरे शासनकाल में उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को निर्देश दिए थे कि मुझसे सुविधाएं वापस ले ली जाएं. बेनज़ीर के आदेश से लागू हुआ यह नियम आज भी मौजूद है. मेरे हिसाब से पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व जनरल के लिए पाकिस्तानी राजनीति में अब कोई अवसर नहीं है. जनरल अय्यूब ख़ान हों या अस्कंदर मिर्ज़ा या कोई और तानाशाह, इनकी देश वापसी असंभव होती है. यही कारण है कि परवेज़ मुशर्रफ़ ख़ुद भी अक्सर यह बात मीडिया से कहते रहते हैं कि विदेशों में उनकी व्यस्तता अधिक हो गई है, इसलिए वह पाकिस्तान आने-जाने के बजाय बाहर ही रहना चाहते हैं. वह कहते हैं कि उन्होंने जिस क़ानून के तहत इस्तीफ़ा दिया था, उसके अनुसार वह छह महीने बाद ही चुनाव लड़ने योग्य हो जाते हैं, मगर ऐसा उनका इरादा नहीं है. वह विदेशों में लोकतंत्र पर व्याख्यान देकर संतुष्ट हैं. प्रधानमंत्री युसूफ़ रज़ा गिलानी ने भी गत दिनों परवेज़ मुशर्रफ़ को कुछ इसी तरह का संदेश दिया था. उन्होंने तुर्की के एक दैनिक अख़बार को साक्षात्कार देते हुए कहा था कि मुशर्रफ़ के ख़िलाफ़ उस वक़्त तक कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि वह राजनीति से दूर रहते हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ़ की भलाई इसी में है कि वह सियासत में आने की सोचें भी नहीं. देश की जनता और संसद अब भी मुशर्रफ़ को नापसंद करती है. वह अब भूतकाल का हिस्सा बन चुके हैं. मुशर्रफ़ के सत्ता पर क़ब्ज़ा करने से पहले फौज लोमड़ी की तरह चालाकी से सरकार पर क़ब्ज़ा कर लेती थी. मुशर्रफ़ ने एक हाथी की तरह देश, सत्ता, राजनीति और लोकतंत्र को रौंद कर रख दिया. अंधों, नशे के आदी लोगों और मुस्लिम लीगियों के अलावा सब जान चुके हैं कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फौज को सियासत से दूर, बहुत दूर रखना होगा. परवेज़ मुशर्रफ़ हों या कियानी या कोई भी जनरल हो, फौजियों से लोकतंत्र की तमन्ना रखना सूरज से पानी निकालने के बराबर है.

एम्सटर्डम से असद मुफ्ती

(लेखक उर्दू के मशहूर स्तंभकार हैं)

feedback@chauthiduniya.com

कोई नई शुरूआत होने का संकेत है. दोस्त एवं परिवार के यहां कोई आयोजन आपको शांति और ख़ुशी देगा.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार
जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

आख़िर तीसरा पक्ष क्या है ?

अब तक हमने आपको सूचना क़ानून से जुड़े ज़्यादातर पहलुओं से परिचित करा दिया है. विभिन्न विषयक आरटीआई आवेदनों के बारे में बताया और उन्हें प्रकाशित भी किया. लेकिन, अभी तक सूचना क़ानून के एक महत्वपूर्ण भाग की चर्चा नहीं हो सकी थी. कई बार जब आप किसी सरकारी विभाग में आरटीआई आवेदन देते हैं तो जवाब में आपको बताया जाता है कि फलां सूचना तीसरे पक्ष से जुड़ी है, इसलिए आपको नहीं दी जा सकती या मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए सूचना का प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता या फिर अमुक सूचना को सार्वजनिक करना देशहित में नहीं है या सूचना को सार्वजनिक करने से देश की आंतरिक सुरक्षा को ख़तरा हो सकता है. हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना न देने के लिए बहानेबाज़ी कर रहा है. कई बार सचमुच ऐसा होता भी है. इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास आरटीआई क़ानून की ऐसी धाराओं की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, जो सूचना को सार्वजनिक किए जाने से रोकती हैं. इससे फ़ायदा यह होगा कि हम आसानी से तय कर सकेंगे कि लोक सूचना अधिकारी कहीं उन धाराओं का ग़लत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है. इस अंक से हम आपको आरटीआई क़ानून की धारा 8, 11, न्यायालय की अवमानना, संसदीय विशेषाधिकार और तीसरे पक्ष के बारे में उदाहरण सहित बताएंगे, जो आवेदक को सूचना हासिल करने से रोकते हैं. इस अंक में फ़िलहाल हम तीसरे पक्ष की बात कर रहे हैं. उम्मीद है कि यह आपके काम आएगा. इसके अलावा आरटीआई क़ानून का इस्तेमाल करते रहिए. अगर आपको कोई समस्या या परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपके साथ हैं. सूचना के अधिकार क़ानून के तहत जो व्यक्ति सूचना मांगता है, वह प्रथम पक्षकार होता है. जिस विभाग या लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांगी जाती है, वह द्वितीय पक्षकार होता है. इस तरह की सूचनाओं में आमतौर पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती. लेकिन, यदि आवेदक द्वारा मांगी जा रही सूचना आवेदक से सीधे-सीधे संबंधित न होकर किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित हो तो वह अन्य व्यक्ति तृतीय पक्ष कहलाता है. तीसरे पक्ष से संबंधित व्यक्ति की सूचना को तृतीय पक्ष की सूचना कहा जाता है. सूचना के अधिकार क़ानून में तृतीय पक्ष की गोपनीयता को संरक्षित करने का प्रावधान है. क़ानून की धारा 11 के अनुसार, ऐसी सूचनाएं, जो किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधित होती हैं, उन्हें आवेदक को दिए जाने से पूर्व तीसरे पक्षकार से इजाज़त लेनी पड़ती है. ऐसे मामलों में लोक सूचना अधिकारी की ज़िम्मेदारी होती है कि वह आवेदन प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर तीसरे पक्षकार को इस आशय की सूचना देगा और अगले 10 दिनों के भीतर सूचना जारी करने की सहमति या असहमति प्राप्त करेगा. लेकिन, क़ानून में यह भी

स्पष्ट किया गया है कि ऐसी सूचना, जिससे सामाजिक हित सधता हो या तीसरे पक्ष की सूचना को जारी करने से होने वाली संभावित क्षति लोक हित से ज़्यादा बड़ी न हो तो उस दशा में मांगी गई सूचना जारी की जा सकती है. क़ानून में यह एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी को है कि वह मांगी गई सूचना तृतीय पक्षकार एवं लोक हित को अच्छी तरह समझ-बूझकर जारी करे, लेकिन कई मामलों में देखने में आया है कि लोक सूचना अधिकारी व्यक्तिगत स्वार्थ या विभागीय दबाव के चलते सूचनाओं को जारी करने से रोकने में तृतीय पक्ष से संबंधित धारा 11 का ग़लत इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में सूचना आयुक्तों की ज़िम्मेदारी काफी बढ़ जाती है कि वे तृतीय पक्ष से संबंधित सूचनाओं को जारी करने में लोक हित का विशेष ख्याल रखें, जिससे क़ानून की मूल भावना, पारदर्शिता और जवाबदेही बची रहे.

तीसरे पक्ष से संबंधित कुछ अहम फ़ैसले

एक करदाता द्वारा जमा किए गए आयकर रिटर्न की सूचना भी तृतीय पक्ष से संबंधित मानी गई है. सूचना आयोग ने एक मामले की सुनवाई के दौरान आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि नहीं दिलवाई. आयोग का मानना था कि करदाता द्वारा यह सूचना विभाग को एक विश्वास के तहत दी जाती है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. लेकिन, एक दूसरे मामले में आयोग ने आयकर निर्धारण की जानकारी सार्वजनिक करने में कोई आपत्ति नहीं जताई. इससे समझा जा सकता है कि सूचना दी जाए या नहीं, इसका सारा दारोमदार सूचना आयुक्त पर ही है. एक दंपत्ति ने सूचना के अधिकार क़ानून के तहत एक डॉक्टर के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि मांगी, जिसे मेडिकल संस्थान ने देने से मना कर दिया. संस्थान का मानना था कि यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना है जिसे दिए जाने से उसकी निजता का हनन होता है. आयोग में सुनवाई के दौरान दंपत्ति ने यह सूचना लोकहित में जारी करने की दलील दी. उनका कहना था कि जिस डॉक्टर के शैक्षणिक दस्तावेज़ मांगे गए हैं, उसने उनके पुत्र का इलाज किया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी. उन्हें संदेह था कि डॉक्टर के दस्तावेज़ फ़र्ज़ी हैं. आयोग ने भी इस दलील पर सहमति जताई और उसने जनहित में यह सूचना जारी करने के आदेश दे दिए.

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश
पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

पढ़ते ही डिलीट हो जाएगा एसएमएस

अब आपको एसएमएस पढ़ने के बाद उसे डिलीट करने के लिए उंगलियों को कष्ट नहीं देना पड़ेगा. अब मोबाइल का इनबॉक्स भी खाली रहेगा. मैसेज को लोगों से छुपाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बस मैसेज पढ़कर टेंशन फ्री हो जाइए. लंदन की एक कंपनी ने ऐसी सेवा विकसित की है, जिससे मैसेज पढ़े जाने के बाद वो ख़ुद-बख़ुद डिलीट हो जाएगा. यह ख़बर उनके लिए राहत भरी हो सकती है, जो मुसीबत झेल चुके हैं. कई प्रसिद्ध हस्तियां इस पचड़े में फंसकर बदनामी झेल चुकी हैं. लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा. इस सेवा का नाम सेफ टेक्स्ट रखा गया है.

एक स्थानीय समाचारपत्र टेलीग्राफ के अनुसार, यह सेवा ऑगिल्वी एडवरटाइज़िंग ने विकसित की है. लोगों की परेशानी देखते हुए कंपनी ने यह अनोखा क़दम उठाया. इससे लोगों को काफी फ़ायदा होगा. होता यह है कि कई बार हम मैसेज डिलीट नहीं कर पाते, जिससे परेशानी में पड़ जाते हैं और उसके बाद मैसेज एवं मोबाइल को कोसते रहते हैं. अब इससे राहत मिलेगी. कंपनी का दावा है कि एक दिन हर शख़्स सेफ टेक्स्ट सेवा का इस्तेमाल करेगा. वैसे कंपनी यह चेतावनी भी दे रही है कि उपयोगकर्ता अगर यह सुविधा लेता है तो उसे एसएमएस पढ़ने का सिर्फ़ एक मौक़ा मिलेगा, इसलिए हो सकता है कि उपयोगकर्ता को परेशानियों का भी सामना करना पड़े.

प्रिंटर से सेहत को ख़तरा!

कंप्यूटर आज लोगों की ज़रूरत बन गया है. इसके बिना ऐसा लगता है, जैसे कुछ खो गया है. आज अमन हर घर में कंप्यूटर है और साथ में प्रिंटर भी. आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि इसमें आख़िर नई बात कौन सी है? नई बात है जनाब! प्रिंटर हमारी सेहत के लिए घातक है. लेजर प्रिंटर तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है. इसमें स्याही की जगह महीन पाउडर वाला एक कार्टिज लगता है. आमतौर पर कार्टिज वाले पाउडर को टोनर कहते हैं. टोनर के कण इतने महीन होते हैं कि कार्टिज से बाहर वे बड़ी देर तक हवा में तैर सकते हैं. यही महीन कण सांस के रास्ते हमारे फेफड़ों तक पहुंच कर हमें बीमार कर सकते हैं.

जर्मनी में फ्राइबुर्ग विश्वविद्यालय के पर्यावरण चिकित्सा एवं अस्पताल स्वच्छता संस्थान की एक शोध टीम ने इसी को अपनी खोज का विषय बनाया. वह जानना चाहती थी कि टोनर से उड़ने वाले अत्यंत महीन कण जब हमारे फेफड़ों में पहुंचते हैं तो फेफड़ों पर उनका क्या असर पड़ता है? शोधकर्ताओं ने टोनर की धूल का फेफड़े की कोशिकाओं के कल्चर यानी संवर्ध से संपर्क कराया. नतीजा बहुत चौंकाने वाला रहा. संस्थान के निदेशक प्रो. फोल्करमेर्स सुंदरमान का कहना है कि फेफड़े की कोशिकाओं को टोनर की धूल के संपर्क में लाने से उनके जीनों को काफी नुक़सान पहुंचा.यह नुक़सान इतना व्यापक और गहरा था कि हमें कहना पड़ेगा कि इससे कोशिकाओं के जीनों में म्यूटेशन पैदा होता है. म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन. यह परिवर्तन आकस्मिक होता है और हानिकारक भी. हो सकता है कि कोशिका अपनी मरम्मत ख़ुद कर ले, लेकिन यह भी हो सकता है कि कुछ कोशिकाएं मर जाएं और मवाद पैदा हो जाए. स्थिति तब और भी चिंताजनक हो सकती है, जब कोई क्षतिग्रस्त कोशिका कैंसर की कोशिका में बदल जाए और फेफड़े का कैंसर पैदा करने लगे. सुंदरमान कहते हैं कि यह एक आशंका है, जिसे गंभीरता से लेना होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 17 मई–23 मई 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
दिल से जुड़े मामले में आपको शांति और खुशियां मिलेंगी. आप किसी बेहतरीन जगह पर शिफ्ट होने की योजना बनाएंगे. व्यवसायिक क्षेत्र में तरक्की के अवसर बने हुए हैं. वित्तीय फ़ायदे का योग है. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह आप कई तरह के प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहेंगे. व्यवसायिक तौर पर समय आपके लिए अच्छा रहेगा. यात्रा आपको सफलता दिलाएगी. इसके अलावा आपको कई जगहों से फ़ायदा मिलेगा. स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार आएगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
अगर आप कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो बचें, क्योंकि वह आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी. कोई उम्रदराज़ व्यक्ति आपके लिए तनाव का कारण बनेगा. ख़र्चे तेज़ी से बढ़ेंगे. परिवार से जुड़े मामलों में धैर्य से काम लेना होगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
रचनात्मक दिशा में किया जा रहा प्रयास सफल होगा. इस सप्ताह आप कहीं भी निवेश करेंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा. इस समय आपको स्वास्थ्य पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है. अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग बने हुए हैं.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे. आपको कई जगह से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा. व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़ी ख़बरें आपको रिलैक्स कर देंगी. इस सप्ताह आपको अपने प्रोजेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
वित्तीय मामलों के प्रति सावधानी बरतें, तभी आप अपने काम में सफलता पा सकेंगे. यात्रा करने से बचें. अगर जाना ज़रूरी हो तो किसी भी तरह के विवाद से बचने की कोशिश करें. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह आप वित्त से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे. निवेश पर विशेष ध्यान देंगे. टीम के साथ चलकर काम करना आपके लिए आसान रहेगा. इस समय धैर्य और ईमानदारी बनाए रखना ज़रूरी है. पेट संबंधी शिक़ायत हो सकती है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
आपका परिवार कई तरह से आपको सहयोग करेगा. इस सप्ताह आप पूरी तरह परिवार एवं घर के कामों पर ध्यान देंगे. काफी समय से अधूरे पड़े कार्य पूरे होंगे. स्वास्थ्य को लेकर आप सजग रहेंगे और उसमें कई तरह से सुधार आएगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
व्यवसायिक विलंब आपको परेशान करेगा. तनाव ख़त्म करने के लिए योग एवं मेडिटेशन पर ध्यान दें. किसी बुजुर्ग व्यक्ति का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बनेगा. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
कोई नई शुरूआत होने का संकेत है. दोस्तों एवं परिवार के यहां कोई आयोजन आपको शांति और ख़ुशी देगा. व्यवसायिक तौर पर कोई नया प्रोजेक्ट फ़ायदे से भरपूर रहेगा. आर्थिक क्षेत्र में आपको पिता समान किसी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
मांगलिक कार्यों की दिशा में किया जा रहा प्रयास सफल होगा. आय के क्षेत्र में नए रास्ते बनेंगे. मेडिटेशन और दूसरों के सहयोग से कई ऐसे काम निपटाना आसान हो जाएगा, जो पहले ख़ासे कठिन साबित हो रहे थे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
व्यवसायिक बदलाव होंगे, लेकिन आपकी उम्मीदों से कम रहेंगे. किसी बच्चे का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है. ख़र्च करते समय सावधानी बरतें. आय और व्यय में संतुलन बनाए रखें. कठिन स्थितियों में धैर्य से काम लें.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

सार्क विश्व जनसंख्या के छठे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अपने उद्देश्यों को हासिल करने में बुरी तरह विफल रहा है.

एक क़दम ही सही आगे तो बढ़े हम

वाशिंगटन में परमाणु शिखर सम्मेलन के ठीक बाद 16वें सार्क सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाक़ात की संभावना बनी तो यह उम्मीद ज़ोर पकड़ने लगी थी कि इसका कुछ न कुछ अच्छा परिणाम निकलेगा. यह आशा जगने लगी थी कि भूटान की राजधानी थिंपू में दोनों पड़ोसी देश बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए कोई नया रास्ता ज़रूर निकालेंगे. युसूफ़ रज़ा गिलानी और मनमोहन सिंह के मिलने से पहले ही आशावादिता का यह माहौल बन चुका था. हालांकि मुलाक़ात के बाद भारत की विदेश सचिव निरुपमा राव मीडिया से बातचीत के दौरान दोतरफा शब्द के इस्तेमाल से बचती रहीं, लेकिन यह हर लिहाज़ से दोनों देशों के बीच दोतरफ़ा बातचीत की दोबारा शुरुआत ही है.

भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुले तौर पर कहा कि आगे बढ़ने के लिए दोनों देशों के पास बातचीत के सिवा और कोई विकल्प नहीं है तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया को बताया कि जम्मू एवं कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर बातचीत होगी. हालांकि इसके लिए अभी कोई तारीख़ नहीं तय की गई है, क्योंकि दोनों देश इसके प्रारूप पर विचार-विमर्श कर रहे हैं. दोनों नेताओं की मुलाक़ात के बाद कोई संयुक्त बयान भले न जारी किया गया हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि बंद रास्ते फिर से खुल चुके हैं, गतिरोध समाप्त हो चुका है. पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए भारत के पास कश्मीर से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है. हम पाकिस्तान की सरज़मीं का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे, प्रधानमंत्री गिलानी का यह बयान भी भारत को संतुष्ट नहीं कर सकता. नई दिल्ली लश्करे तैयबा और हाफ़िज़ सईद के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई चाहती है. इसी तरह मनमोहन सिंह का यह बयान कि भारत पाकिस्तान को अस्थिर नहीं करना चाहता, भी दोनों देशों के बीच अविश्वास के माहौल को कम नहीं कर सकता.

सार्क विश्व जनसंख्या के छठे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अपने उद्देश्यों को हासिल करने में बुरी तरह विफल रहा है. इसके चार्टर के मुताबिक़, द्विपक्षीय मामले सार्क में नहीं उठाए जा सकते. कोई भी क्षेत्रीय संगठन तब तक आर्थिक विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक कि उसके सदस्य राजनीतिक मुद्दों पर एकमत न हों. और, सार्क इसका अपवाद नहीं है. भारत और पाकिस्तान की संयुक्त आबादी 120 करोड़ से भी ज़्यादा है और इसमें से अधिकांश आबादी ग़रीबी में जीवन जीने को अभिशप्त है. लेकिन, दोनों देशों के बीच के रिश्ते इतने ख़राब रहे हैं कि बेमतलब के प्रस्तावों और ऊंचे आदर्शों की शिक्षा देने के सिवा सार्क कुछ ख़ास करने में नाकाम रहा. इस साल के आख़िर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से पहले थिंपू घोषणापत्र के माध्यम से सार्क देश जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर एक समान रवैया अपनाने को सहमत हुए हैं. अब यह बात और है कि पिछले साल कोपेनहेगन में हुए सम्मेलन में भारत ने कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को मानने से इंकार कर दिया.

व्यापार एक अन्य ऐसा क्षेत्र है, जिसमें सार्क देश आपसी सहयोग बढ़ाने में विफल रहे हैं. साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (साफ्टा) पर हस्ताक्षर करने के बावजूद सदस्य देश अंतरक्षेत्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने में नाकाम रहे हैं. इस क्षेत्र की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होने के चलते भारत और पाकिस्तान इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते थे, जो इन दोनों देशों के अलावा पूरे सार्क क्षेत्र के लिए फ़ायदेमंद हो सकता था. अकेले भारत ही दक्षिण एशिया की कुल राष्ट्रीय आय के 80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है. इस लिहाज़ से क्षेत्र में व्यापार और विदेशी निवेश को प्रोत्सहित करके आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी भी उसी की है. 2008 में भारत और पाकिस्तान के बीच का कुल सालाना व्यापार दो बिलियन डॉलर का था. भारत के कुल विदेश व्यापार में पाकिस्तान का हिस्सा 0.5 प्रतिशत था, जबकि भारत पाकिस्तान के कुल व्यापार में एक प्रतिशत योगदान देता था. वाशिंगटन स्थित पैटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक अध्ययन के मुताबिक़, दोनों देशों के बीच व्यापार इसका बीस गुना तक हो सकता है. 2008 के आंकड़ों को आधार मानें तो इसका मतलब यह है कि भारत-पाकिस्तान के बीच कुल विदेशी व्यापार 2.1 बिलियन डॉलर से 42 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, लेकिन इस रास्ते में कई राजनीतिक और नीतिगत बाधाएं हैं. बड़ी आर्थिक शक्ति होने के बावजूद भारत ने उन चीजों पर कर का स्तर ऊंचा रखा है, जिनमें पाकिस्तान की रुचि है. दूसरी ओर पाकिस्तान भी भारत को अब तक मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा देने से इंकार करता रहा है. इसका नतीजा यह है कि कुल क़रीब 1400 चीजें ही ऐसी हैं, जो भारत पाकिस्तान को निर्यात कर सकता है.

आम धारणा यही है कि व्यापार को बढ़ावा, वीज़ा क़ानूनों में ढील, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन एवं बैंकिंग क्षेत्र में उदारीकरण को बढ़ावा देने से भारत और पाकिस्तान न केवल अपने द्विपक्षीय व्यापार को नए स्तर पर ले जा सकते हैं, बल्कि इससे शांति प्रक्रिया को भी गति मिलेगी. इसका दूसरा पक्ष यह है कि पिछले 62 सालों में दोनों देशों के बीच के रिश्ते को विषाक्त बनाने वाले कश्मीर मुद्दे का कोई सकारात्मक हल जब तक नहीं निकलता, तब तक बेहतर आर्थिक संबंधों का सपना मृग मरीचिका ही साबित हो सकता है. संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आपस में चार लड़ाइयां लड़ने के अलावा भारत और पाकिस्तान ने सभी विकल्प आज़माए हैं. पिछले दरवाजे से कूटनीतिक प्रयासों के साथ-साथ दोनों देशों की जनता के बीच आपसी मेल-मिलाप एवं सुनियोजित बातचीत जैसे सभी प्रयास दोनों परंपरागत शत्रुओं को किसी स्थायी करार के क़रीब लाने में भी सफल नहीं रहे हैं. पूर्व प्रधानमंत्रियों नवाज़ शरीफ़ एवं अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाहौर वार्ता के ठीक बाद तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ़ के कारगिल प्रयोग ने कश्मीर मुद्दे को हमेशा के लिए और भी उलझा दिया. बाद में राष्ट्रपति बनने पर मुशर्रफ़ ने शांतिदूत बनने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध उनकी व्यक्तिगत छवि से अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं. कारगिल के बाद से भारत कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वहां की जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार से ज़्यादा एक आतंकवादी मुद्दे के रूप में प्रचारित करने में कामयाब रहा है. नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत की संभावना को सिरे से ख़ारिज करता रहा है. उसकी मांग है कि पाकिस्तान पहले इसे अंजाम देने वालों, ख़ासकर लश्करे तैयबा के सदस्यों को पकड़े और उन्हें भारत के हवाले करे. जहां तक कश्मीर मुद्दे का सवाल है, द्विपक्षीय बातचीत से पाकिस्तान के मुक़ाबले भारत को ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है.

हाल के सालों में कश्मीर मसले पर पिछले दरवाज़े से कूटनीति का ख़ूब इस्तेमाल हुआ है. पूर्व विदेश मंत्री ख़ुर्शीद कसूरी ने तो यहां तक दावा किया कि मुशर्रफ़ के कार्यकाल में कश्मीर का मुद्दा सुलझने की कगार पर पहुंच चुका था. कसूरी के मुताबिक़, सीमा के दोनों ओर की कश्मीरी जनता को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों में स्वतंत्रता के लिए एक संयुक्त व्यवस्था के साथ पानी के बंटवारे को लेकर भी सहमति बन चुकी थी और समझौते पर हस्ताक्षर होने ही वाले थे, लेकिन पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के माहौल ने सारे किए-धरे पर पानी फेर दिया. कसूरी की आशावादिता अब इतिहास बन चुकी है, क्योंकि सरकारी तंत्र से दूर हुए उन्हें अर्सा हो चुका है. पहली बात तो पाकिस्तान अब मुशर्रफ़ के दौर से आगे निकल चुका है. 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश की संसदीय व्यवस्था को मज़बूती मिली है और राजनीतिक दलों के बीच भारत के साथ संबंधों को सुधारने पर आम सहमति बन रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना का नज़रिया राजनीतिक दलों से अलग है. समस्या यह है कि पाकिस्तान में कोई भी लोकतांत्रिक सरकार सेना के नज़रिये की अनदेखी नहीं कर सकती.

> भारत के नज़रिये से देखें तो पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों के तार आतंकवाद से जुड़े हैं. इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि किसी भी अन्य राष्ट्र से ज़्यादा ख़ुद पाकिस्तान ही इस समस्या से मुक़ाबला करने को मजबूर है.

भारत के नज़रिये से देखें तो पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों के तार आतंकवाद से जुड़े हैं. इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि किसी भी अन्य राष्ट्र से ज़्यादा ख़ुद पाकिस्तान ही इस समस्या से मुक़ाबला करने को मजबूर है. इस्लामाबाद भारत पर सिंधु जल समझौते के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाता रहा है. पाकिस्तान का दावा है कि भारत उसके हिस्से का पानी भी हड़प लेता है. आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि पाकिस्तान ने इस मामले में भारत के ख़िलाफ़ अब तक न तो औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और न ही तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की मांग की है. कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि पाकिस्तान इस मामले में अपनी कमज़ोरी समझता है और पानी के बंटवारे को लेकर सारे हंगामे का मक़सद केवल कश्मीर और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना है? या फिर यह सरकारी तंत्र के लचर रवैये का एक और उदाहरण तो नहीं है?

दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच युद्ध की वक़ालत कोई सिरफिरा ही कर सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कश्मीर मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए भारत किसी जल्दबाजी में नहीं है. अपने घरेलू राजनीतिक माहौल और आर्थिक दुश्वारियों से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत भी इससे ख़ास अलग नहीं है.

निजामी ए.
feedback@chauthiduniya.com

दाढ़ी और बुर्क़ा आतंक की निशानी नहीं

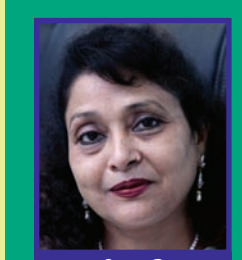

वसीम राशिद

गंगा-जमनी तहज़ीब से सजा यह मेरा चमन हिंदुस्तान है, जहां धर्म और जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन जैसे-जैसे आतंकवाद का काला साया दुनिया के सभी देशों में फैलता जा रहा है, वैसे-वैसे हिंदुस्तान जैसे धर्म निरपेक्ष देश में भी मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है. दो चीज़ें जो मुसलमानों की विशेष पहचान हैं, दाढ़ी और बुर्क़ा, को ही आतंकवाद का लक्षण समझ लिया गया है. ख़बर है कि कोलकाता हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट की फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करके उतार लिया गया. ऐसा इसलिए कि बुर्क़ा पहने एक रूसी महिला और उसके साथी मुसाफिर पर आतंकवादी होने का संदेह था. जहाज़ के पायलट को इस महिला के लंबे- चौड़े व्यक्तित्व के कारण ऐसा लगा कि वह महिला नहीं, पुरुष है. जहाज़ के अमले ने महिला से बुर्क़ा उठाने के लिए कहा. उसने जब इंकार किया तो पायलट ने कोलकाता के हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करने की इच्छा ज़ाहिर की. बस फिर क्या था, इस सनसनीख़ेज़ ख़बर से कोलकाता हवाई अड्डे पर हंगामा मच गया कि दुबई से ढाका जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में दो संदिग्ध आतंकवादी मौजूद हैं. यही नहीं, कोलकाता हवाई अड्डे पर आपातकालीन स्थिति की घोषणा भी कर दी गई. आतंकवाद निरोधक संबंधी दस्ते, पुलिस बल, बम स्क्वायड और फायर ब्रिगेड समेत सभी लोग इस तरह खड़े हो गए, जैसे बाहर आने वाले निश्चित तौर पर आतंकवादी ही होंगे.

सीआईएसएफ के जवानों और पुलिस ने फ्लाइट को घेर लिया और पूरी तरह उन दोनों की तलाशी ली गई. यहां यह बताना बेहद ज़रूरी है कि रूसी महिला या उसके साथी के पास से कोई भी ग़ैर क़ानूनी वस्तु बरामद नहीं हुई. फिर भी बेहद सख्त ज़ुबान में उनसे बातचीत की गई. यह कोई साधारण ख़बर नहीं है, जिसे पढ़कर सरसरी रूप से गुज़रा जा सके. इस ख़बर की मुस्लिम समुदाय में सख्त निंदा की जा रही है और लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर यही रवैया हर फ्लाइट में हर पायलट और साथी अमले ने अपनाया तो हर बुर्क़ा पहनने वाली महिला को हवाई सफर करने में परेशानियों और अपमान का सामना करना पड़ सकता है. यह इस ख़बर का एक भाग था. अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि जहाज़ पर सवार होने से पहले चाहे वह स्थानीय हो या अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट, कई जगह चेकिंग के दौर से गुज़रना पड़ता है. एक तो गेट पर ही सुरक्षा अधिकारी होता है, वह आपका टिकट और पहचान पत्र चेक करके ही अंदर जाने देता है. यह सुनी-सुनाई बात नहीं है. ख़ुद मुझे भी इस तरह की परिस्थितियों से कई बार गुज़रना पड़ा है और जब सुरक्षागार्ड अंदर भेज देता है, तो बोर्डिंग पर भी पहचान पत्र की चेकिंग होती है और तब बोर्डिंग कार्ड मिलता है. फिर चेक इन काउंटरों पर लड़कियां होती हैं, जो आपको पर्दे के पीछे ले जाकर तलाशी लेती हैं और तभी उनकी मुहर आपके बोर्डिंग कार्ड पर लगती है. इसके अलावा सुरक्षा चेकिंग के लिए मुसाफिर जाते हैं तो वहां भी महिला सुरक्षागार्ड तैनात होती हैं, जो सफ़र करने वाली महिलाओं के बुर्क़े उतरवा कर जांच करती हैं. मान भी लिया कि कोई आतंकवादी महिला फ्लाइट तक पहुंच भी जाती है, जहाज़ में सवार भी हो जाती है और अपनी धार्मिक आस्था के कारण वह बुर्क़ा उतारने या चेहरा दिखाने से मना कर देती है तो उसके साथी मर्द को नरम रवैये से समझा कर किसी भी तरह राज़ी किया जा सकता था. मुसलमान कोई ऐसी अड़ियल कौम नहीं है, जिसे समझाया न जा सके. जान हर किसी को प्यारी होती है. अगर सीधी तरह से उन्हें सभी बातें और आज के हालात से अवगत कराया जाता तो निश्चित ही इमरजेंसी लैंडिंग कराने की नौबत ही न आती. मगर देखा यह गया है कि बुर्क़ा ओढ़ने वाली महिलाओं और दाढ़ी वाले मर्दों से एयर होस्टेस और जहाज़ का अमला कड़े रवैये से ही पेश आता है और जहाज़ में सवार होते ही उनकी नज़र इन्हीं लोगों पर रहती है. ख़ैर, यहां बहस यह नहीं है. असल बात यह है कि भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक मुहिम सी छिड़ गई है. एक तरफ़ जहां जहाज़ उतरवा कर महिलाओं पर संदेह करके उन्हें अपमानित किया जाता है, वहीं उस दिन की दूसरी ख़बर भी हमारे सामने है, जहां इटली में बुर्क़ा ओढ़ने पर मुस्लिम महिलाओं पर 500 यूरो का जुर्माना जड़ दिया जाता है. बेल्जियम में तो पहले से ही बुर्क़े पर पाबंदी है. वहां चेहरा ढक कर चलने पर 25 यूरो का जुर्माना और न देने पर 7 दिन की जेल की सज़ा का प्रावधान है. रूस में भी यह क़ानून बन गया ह. ख़ैर, यह उन देशों की अपनी नीति है और वह अपने देश में जैसे चाहें नियम बनाएं, जैसे चाहें क़ानून पास करें, हमें उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. इन उदाहरणों का मतलब यही था कि यह स्पष्ट कर दिया जाए कि मुसलमानों को तो पूरी दुनिया में परेशान किया जाता रहा है, मगर हम अपने देश की धर्म निरपेक्ष भूमिका पर जान देते हैं. यह वह देश है, जहां आज भी बहुत से राज्यों, शहरों, गांवों एवं क़स्बों में हिंदू महिलाएं भी चेहरा ढक कर चलती हैं. यह वह देश है, जहां आज भी नई नवेली दुल्हन चाहे वह मुसलमान हो, हिंदू, सिक्ख हो या ईसाई, अपना चेहरा ढक कर ही घर के बड़ों से आशीर्वाद लेती है. ऐसे सभ्य देश में मुसलमानों से कुछ अलग बर्ताव किया जा रहा है. हर जगह दाढ़ी वालों पर शक किया जाता है, बुर्क़ा ओढ़ने वाली महिलाओं को संदेह भरी निगाहों से देखा जाता है. हमारे इस धर्म निरपेक्ष देश में हर धर्म के लोगों को पूजा-पाठ की पूरी आज़ादी है. वह जिस तरह चाहें, अपने धर्म के हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं और अपने धर्म के हिसाब से जो निशानियां आवश्यक समझी गई हैं, उन्हें अपना सकते हैं. उसी तरह मुसलमानों को भी दाढ़ी रखने या ऊंचा शरअई पाजामा पहनने और औरतों के बुर्क़े में रहने पर भी आज़ादी दी गई है. ठीक उसी तरह जैसे हिंदुओं में जनेऊ पहनने पर कोई आपत्ति नहीं है. मगर जब मुसलमान इस धर्म के अधिकार का प्रयोग करते हैं तो क्यों उन्हें हर तरफ़ से ज़लील किया जाता है. मुस्लिम नौजवान अगर संगठित होकर कहीं घूमने-फिरने भी जाते हैं तो पुलिस उनकी गाड़ी रोक कर उनसे अनेक सवाल कर लेती है. यहां तक कि नाम पूछते ही पुलिस अलर्ट हो जाती है और हज़ारों लिंक ढूंढ-ढूंढ कर निकाल लेती है. मगर वह यह भूल जाती है कि आज जब क़साब को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो यही मुसलमान अपने देश के इस दुश्मन को नफरत से देखते हैं, फांसी की सज़ा का स्वागत करते हैं और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद देते हैं. क्यों मुसलमानों को ही हमेशा अपने वतन से मुहब्बत का सबूत पेश करना पड़ता है. जब मुसलमान चारों तरफ़ से हार गया है तो उसका दर्द उसे यह कहने पर मजबूर कर रहा है, कोई चारासाज़ होता, कोई ग़मगुसार होता.

feedback@chauthiduniya.com

श्रद्धांजलि

शाह शाद शाफ़ी
(16-09-1972 से 24-04-2010)

बड़े दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे एक सहयोगी शाह शाद शाफ़ी अब हमारे बीच नहीं रहे. चौथी दुनिया में सीनियर मैनेजर, सर्कुलेशन के पद पर रहे शाद शाफ़ी का 38 साल की अल्पायु में विगत 24 अप्रैल को अचानक हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया. हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं. साथ ही उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं.

चौथी दुनिया परिवार

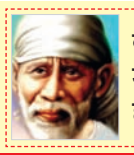

बाबा अपने आप में जितने सरल सहज और प्यारे थे, उनका जीवन, उनकी बातें उतनी ही गहरी और रहस्यमयी थीं. बाबा के ग्यारह वचन हर आत्मा को विश्वास दिलाते हैं तुम्हारे साथ हूं.

कौन हैं साई

शिरडी के साई बाबा दु:ख–दर्द से तड़पती दुनिया को प्रेम का मलहम लगाने आए थे. महालसापति ने पहली बार एक ख़ूबसूरत नौजवान को अंजाने में कह दिया कि आओ साई बैठो, तो यह एक ऐसा सच बन गया, जिसे आज सारा संसार स्वीकार कर रहा है. आज हम उस ख़ूबसूरत नौजवान को साई बाबा के नाम से जानते हैं. साई यानी पवित्र आत्मा. नानक को भी साई कहा जाता है. दरअसल, साई शब्द साई के समय में ईज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि यह पहले से चला आ रहा है. लेकिन, बाबा से जुड़ते ही यह नाम भी अमर हो गया. शिरडी के साई बाबा के रूप में मशहूर यह फ़क़ीर परमात्मा का बंदा था. वह पवित्र आत्मा थी, जो कल, आज और कल का सारा भेद जानती थी. वह सभी प्राणियों को परमात्मा का संदेश देती थी कि सबका मालिक एक है. बाद में यही वाक्य उनका प्रिय वाक्य बन गया. साई बाबा लोगों के ज़ख्मों पर मलहम लगाने आए थे, चाहे वे ज़ख्म तन के हों, या मन के. बाबा का स्वभाव जितना सरल और सहज था, उनकी ज़िंदगी और उनके द्वारा कही गई बातें उतनी ही गहरी और रहस्यमयी थीं. बाबा ने ग्यारह वचन कहे. वह हमेशा सभी को विश्वास दिलाते रहे कि कष्ट होने पर उन्हें पुकारा जाए, वह ज़रूर आएंगे. बाबा अपना वादा आज भी पूरा करते हैं. हर भक्त की पुकार पर वह दौड़े चले आते हैं. कभी–कभी शायद हम ही नहीं जान पाते कि बाबा से हमें क्या कहना है. बाबा से जुड़ी एक कथा में ज़िक्र मिलता है. एक पवित्र आत्मा श्री विष्णु से मिली. उसने भगवान विष्णु से कहा कि भगवन, तुम्हारे बच्चे नीचे रो रहे हैं. जवाब में विष्णु ने कहा, सब अपने ही स्वार्थ का भुगतान कर रहे हैं. जिसने जो कर्म किए हैं, उसे ज़रूर भुगतना पड़ता है. पर आत्मा बोली कि भगवन, आप अपने भक्तों को इस तरह तड़पता हुआ कैसे छोड़ सकते हैं. तब श्री विष्णु बोले, तुम धरती पर जाकर अवतार लो. वहां जाकर लोगों का कल्याण करो. मैं तुम्हारी हर वाणी और इच्छा पूरी करूंगा. साथ ही विष्णु ने कहा कि तुम शिरडी में जाकर रहो. इस पर आत्मा बोली, शिरडी क्यों? विष्णु ने कहा, क्योंकि वह तुम्हारा गुरुस्थान है. 8000 साल पहले तुमने वहां पूजा की थी. एक बार फिर उस स्थान को पवित्र बनाओ. आत्मा ने पूछा, वहां आएगा कौन? विष्णु बोले, तुम शिरडी जाओ, वहां आज भी चार दीये जल रहे हैं. तुम्हारे पहुंचने पर वहां भक्तों की भीड़ लगेगी. दुनिया भर के लोग शांति, प्रेम और खुशी मांगने तुम्हारे दर पर आएंगे. जो तुम्हें जिस रूप में भजेगा, तुम उसी रूप में मिलोगे. अब तुम जाओ और अपना काम करो. आज सर्वविदित है कि वह आत्मा साई बाबा की थी. बाबा का शरीर शांत होने के बाद भी उस आत्मा का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ. अभी उसे एक छत्र के नीचे सारे लोगों को एकत्रित कर परमात्मा का संदेश देना बाकी है. मैं तो सिर्फ़ संदेशवाहक हूं, वह मालिक मेरा पिता है और आप सबका भी. उस मालिक, परवरदिगार साई को पहचानो, उसे याद करो. आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे. दो शब्द श्रद्धा और सबूरी सुनने में बड़े आसान लगते हैं, लेकिन यही दो शब्द सही और श्रेष्ठ जीवन का मार्गदर्शन करते हैं. श्रद्धा का मतलब परमात्मा और खुद में विश्वास है, जबकि सबूरी का मतलब धैर्य. यानी जो मांगा है, जो कहा है, वह ज़रूर पूरा होगा. बाबा अपने जीवनकाल के दौरान एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर गए, जो आज भी लोगों के जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब देता है. साई सच्चरित्र आज भी बाबा से जुड़े लाखों लोगों को उनके सवालों के जवाब देता है. बाबा ने जाना कि लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए पहले उन्हें दु:ख से बाहर निकालना ज़रूरी है. दर्द में डूबा आदमी परमात्मा को भी पहचान नहीं पाएगा और न ही सच की राह चल पाएगा. बाबा का हर चमत्कार दु:खी आत्मा का हौसला बढ़ाता है, उसे बल देता है कि वह उसके साथ है. उसके बाद बाबा देखते हैं कि उनका साथ उस दु:खी आदमी को सही रास्ते पर ले जा रहा है या फिर उसे सदैव सहारा मांगने की आदत पड़ गई है. इसलिए जब भी बाबा का साथ मिले, आप खुद को सच्चाई के मार्ग पर ले जाएं. स्वयं को पवित्र विचारों और संकल्पों वाला बनाएं. अगर आपका रास्ता सच का होगा, श्रद्धा और सबूरी का होगा तो आप पाएंगे कि बाबा हर पल आपके साथ हैं.

ओम साई राम.

ऑसिम खेत्रपाल
feedback@chauthiduniya.com

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

सद्गुण और अवगुण

मनुष्य को अच्छाइयों और बुराइयों का पुतला कहा जाता है. ऐसा मनुष्य किस काम का, जो औरों में केवल बुराइयां ही देखे. ऐसे बुरे आदमी के लिए कहा गया है, *बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय.* दूसरों में सदैव बुराइयां देखने वाले स्वयं बहुत बुरे होते हैं. मनुष्य के दो कानों और दो आंखों के समान समाज में अच्छाइयां देखने वाले लोग भी होते हैं. दानी, ज्ञानी, धार्मिक, परोपकारी एवं सेवा करने वालों के लिए बड़े-बड़े समारोहों में प्रशंसा गीत गाए जाते हैं. इससे सद्गुणों का व्यापक प्रचार-प्रसार होता है. ऐसे लोग सद्गुणी और प्रशंसनीय माने जाते हैं.

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj Sai Hills

Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious Studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Fumished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

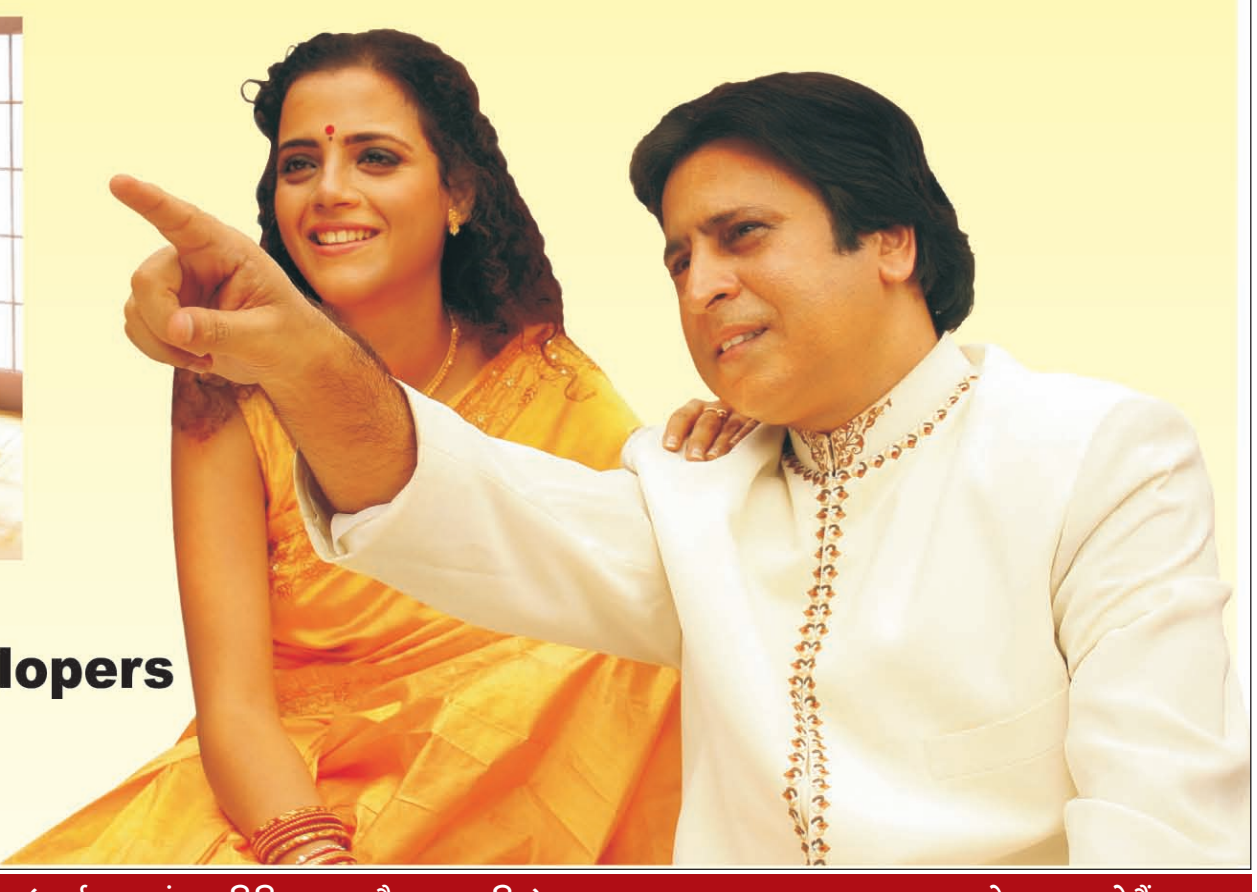

AUM Infrastructure & Developers

Aum Infrastructure & Developers
Tel: 011-46594226 / 46594227
www.girirajsaihills.in

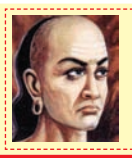

जब बात जीवन प्रबंधन की हो तो इंसान के लिए कई मोर्चों पर सजगता के साथ काम करना आवश्यक हो जाता है.

दलित, अल्पसंख्यक सशक्तीकरण का दस्तावेज़

अनंत विजय

एक जमाने में पत्रकारिता समाज के उन लोगों के साथ खड़ी होती थी, जो वंचित और शोषित कहे जाते थे और पत्रकार उनके हक़ के लिए खड़े हो जाते थे. पिछड़ों और दलितों को न्याय दिलाने की पत्रकारिता अब समाचार माध्यमों से विलुप्त होती दिख रही है. टेलीविज़न ने इस तरह की पत्रकारिता का बड़ा नुक़सान किया. चूंकि टीवी दृश्य माध्यम है, इसलिए यहां प्रोफाइल पर बहुत ध्यान दिया जाता है. झुग्गियों में अगर कोई बलात्कार होता है तो वह ख़बर टीवी न्यूज़ पर सुर्ख़ियां नहीं बनती. न्यूज़ चैनलों को ग्लैमर चाहिए और इसी ग्लैमर एवं चमक-दमक की चाहत में ख़बरिया चैनलों से ग़रीब-गुरबा ग़ायब होते चले गए. कुछ न्यूज़ चैनलों में यह साहस अब भी है कि वे बुंदेलखंड, विदर्भ या फिर बिहार के सुदूर इलाक़ों के ग़रीबों पर कार्यक्रम बनाते हैं. कमोबेश यही हालत अख़बारों और पत्रिकाओं की भी हो गई है. अगर कोई सेक्स सर्वे आ गया तो उसे प्रमुखता से कवर स्टोरी बना दिया जाता है, क्या आपको याद है कि खुद के राष्ट्रीय पत्रिका होने का दावा करने वाली किसी भी पत्रिका के कवर पेज पर समाज के निचले पायदान पर जीवन बसर करने वालों के चित्र प्रकाशित होते हैं? लेकिन, हमारे ही देश में ग़रीबों और दलितों के हक़ों के लिए पत्रकारिता की एक लंबी परंपरा रही है.

पिछले दिनों मैं रविवार पत्रिका के पुराने अंक पलट रहा था तो मुझे दलितों और उनकी समस्याओं पर वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय के लिखे कई लेख मिले. इस क्रम में मैं सिर्फ़ दो लेखों का उल्लेख करना चाहूंगा, जो मार्च और अगस्त उन्नीस सौ चौरासी में छपे थे. पहला लेख था- श्रीपति जी, ग़रीब हरिजन की ज़मीन तो लौटा दीजिए. यह लेख उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र के उनके अपने गांव में एक दलित जोखई की ज़मीन क़ब्ज़ाने के बारे में विस्तार से लिखा गया था. श्रीपति मिश्र के परिवार पर एक हरिजन की ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने की कहानी छपने के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के सियासी हलकों में हड़कंप मच गया और चार महीने बीतते ही श्रीपति मिश्र को इंदिरा गांधी ने चलता कर दिया. यह एक रिपोर्ट की ताक़त थी, एक पत्रकार की ताक़त थी और एक पत्रकार का समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी, जहां वह समाज के सबसे निचले तबके को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश के सबसे ताक़तवर आदमी को भी नहीं बख्शता है. इस तरह की रिपोर्टिंग से आम जनता के मन में पत्रकारिता को लेकर एक विश्वास पैदा होता है.

संतोष भारतीय ने पत्रकारिता के अपने लंबे करियर में दलितों एवं अल्पसंख्यकों की बेहतरी के सवाल को अपने लेखों में ज़ोरदार तरीक़े से उठाया और इसका असर भी हुआ. अभी हाल ही में संतोष भारतीय के संपादन में दलित, अल्पसंख्यक सशक्तीकरण नामक लगभग पांच सौ पन्नों की

किताब आई है. इस किताब में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्रियों-विश्वनाथ प्रताप सिंह और इंद्र कुमार गुजराल समेत कई विद्वानों के लेख संकलित किए गए हैं. डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने लेख में बेहद ही साफगोई और साहस के साथ यह स्वीकार किया है कि मेरा मानना है कि साठ वर्षों के संवैधानिक एवं क़ानूनी संरक्षण और राज्य सहायता के बावजूद देश के कई हिस्सों में दलितों के ख़िलाफ़ सामाजिक भेदभाव अब भी मौजूद है. आज़ादी के साठ सालों बाद भी अगर एक लोकतांत्रिक देश के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव होता है, तो यह न केवल एक बेहद गंभीर बात है, बल्कि एक सभ्य समाज का दावा करने वाले देश के सामने एक बड़ा सवाल भी है, जिसका निराकरण ढूंढे जाने की ज़रूरत है. पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अपने लेख में दलित अल्पसंख्यक महाशक्ति की यात्रा, उसके संघर्षों और पीड़ा को शिद्दत के साथ चिन्हित किया है. साथ ही दलितों और अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए समाज के सभी वर्गों के आगे आने की वकालत की है.

ऐसा नहीं है कि इस किताब में सिर्फ़ राजनेताओं के ही लेख हैं. इस भारी-भरकम ग्रंथनुमा किताब में पांच खंड हैं, जिनमें देश के प्रमुख विचारकों एवं दलित चिंतकों के लेख हैं. इनमें असगर अली इंजीनियर, पी एस कृष्णन, प्रो. मुशीरुल हसन, डॉ. सतीनाथ चौधरी एवं इम्तियाज़ अहमद आदि प्रमुख हैं. इस पुस्तक के दूसरे खंड में पत्रकार कुरबान अली ने अपने लंबे शोधपरक आलेख में भारत में मुस्लिम समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव को रेखांकित किया है. बेहद श्रमपूर्वक लिखे गए इस लेख में कुरबान अली ने भारत के मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन की असलियत और उसके कारणों के अलावा सांप्रदायिक हिंसा को आंकड़ों के आधार पर विश्लेषित किया है. कुरबान अली के लेख को पढ़ते हुए मुझे पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल से सुना एक संस्मरण याद हो आया. गुजराल साहब जब सूचना और प्रसारण मंत्री बने तो वह ज़ाकिर हुसैन साहब से मिलने गए और बातों-बातों में मंत्रालय में मुसलमान चपरासियों के बारे में बात निकली तो गुजराल साहब ने कहा कि वह अपने मंत्रालय में मुसलमान चपरासियों की संख्या पता करेंगे. यह सुनकर ज़ाकिर साहब ने कहा कि इस मुल्क में मुसलमान का राष्ट्रपति बनना तो आसान है, लेकिन चपरासी बनना बेहद मुश्किल. ज़ाकिर हुसैन साहब की यह बात हमारे समाज और मुल्क की एक ऐसी हक़ीक़त है, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता है. इसके बाद गुजराल साहब ने अपने मंत्रालय में पता किया तो एक भी मुसलमान चपरासी नहीं मिला और जब सारे मंत्रालयों के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई तो आंकड़े ज़ाकिर साहब के बयान की तस्दीक कर रहे थे. यह वाकया तीन-चार दशक पहले का है, लेकिन अब भी हालात में कोई सुधार हुआ हो, ऐसा लगता नहीं है. नौकरी की बात तो दूर, इस देश में अब भी मुसलमानों को ग़ैर मुस्लिम इलाक़े में किराए का मकान ढूंढने में नाको चने चबाने पड़ते हैं.

संतोष भारतीय द्वारा संपादित इस किताब में कई ऐसे लेख हैं, जो अब के समाज में दलितों और अल्पसंख्यकों की स्थिति का आईना दिखाते हैं. यह किताब इस लिहाज़ से भी अहम बन गई है कि इसमें एक ही मंच पर दलितों एवं अल्पसंख्यकों के बारे में विद्वानों, विचारकों और देश के नीति नियंताओं के विचार खुलकर सामने आए हैं. और, मुझे लगता है कि हिंदी में इस तरह की कोई किताब आज तक उपलब्ध नहीं है. इस वजह से इस किताब का एक स्थायी महत्व है और भविष्य में इसका उपयोग एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में होगा. यह किताब हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई है.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश

मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

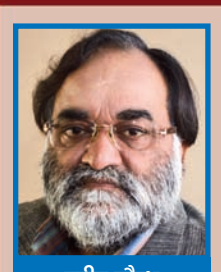

प्रदीप सौरभ

मियां मिर्ची गुटखा मुंह में घोटे जा रहे थे, लेकिन कुछ बोलने के लिए उनके पेट में बल पड़ रहे थे. वह कुछ राज की बात बताना चाहते थे. उन्होंने चलती गाड़ी में दरवाज़ा खोला और पीक बाहर थूक दी. उन्होंने आनंद भारती की ओर देखा. उन्हें लगा कि बात शुरू की जा सकती है.

साहब, आपको पता है.

क्या? आनंद भारती बोले.

राहत शिविरों में रहने वाली लड़कियां रात भर ग़ायब रहने लगी हैं.

क्या मतलब?

साहब, जिस्मफरोशी कर रही हैं. यही नहीं, दंगों में जो औरतें बेसहारा हो गई हैं और शिविरों में नहीं रहती हैं, वे भी इस धंधे में लग गई हैं. शिविर में ही उनके दलाल भी पैदा हो गए हैं.

तुम्हें किसने बताया?

अरसद बता रहा था. अरसद की पत्नी-बच्चे भी दंगों की भेंट चढ़ चुके हैं. उसका हाथ भी दंगाइयों ने काट दिया था. उसी ने मेरे से एक दिन पूछा था कि कोई कस्टमर हो तो बताना.

कहां जाती हैं ये लड़कियां? आनंद भारती की जिज्ञासा बढ़ गई थी.

सेटेलाइट, नवरंगपुरा, इलीस ब्रिज, वेजलपुर के बड़े-बड़े फ्लैटों में जाती हैं. अच्छी कमाई होती है.

कौन लोग हैं, जो लड़कियां बुलाते हैं? सवाल दोबारा उभरा.

अधिकांश हिंदू आबादी में रहने वाले ठेकेदार और पैसे वाले लोग हैं.

मियां मिर्ची की बात सुनकर आनंद भारती हतप्रभ रह गए. सोचने लगे कि शारीरिक सुख भोगने में सांप्रदायिकता आड़े क्यों नहीं आती. बिस्तर साझा करते वक़्त उनका हिंदुत्व कहां चला जाता है.

अगला पड़ाव अजमेर था. वहां रुककर ख्वाजा साहब की दरगाह पर मत्था टेकने का कार्यक्रम था. शरीफ ख़ान पठान के जानने वाले, खादिम हैं यहां. उन्होंने अहमदाबाद से खादिम को फोन कर दिया था. ख्वाजा साहब के दरवाज़े पर जब आनंद भारती पहुंचे तो मियां मिर्ची खादिम को ढूंढ लाए. उन्होंने चादर और फल दिलवाए. आनंद भारती ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िर थे. उन्होंने चादर चढ़ाई. हाथ जोड़कर शुक्रिया किया: मोदी की दंगाई

धरती से ज़िंदा बचकर आने के लिए आपका सिजदा करता हूं.

दरगाह से निकलने के बाद आनंद भारती के चेहरे पर एक ख़ास तरह का सुकूं झलक रहा था. गाड़ी फिर बढ़ने लगी. शाम के चार बज रहे थे. दिल्ली की सीमा में रात दस बजे पहुंचने का टारगेट था. रास्ते में चायपान करके आनंद भारती समय को बर्बाद नहीं करना चाहते थे. उन्हें दिल्ली पहुंचने की धुन थी. अपने एक दोस्त के घर मालवीय नगर उनको रुकना था. वैसे उनका अपना फ्लैट भी गाजियाबाद के वसुंधरा में था. कई साल पहले जब वह

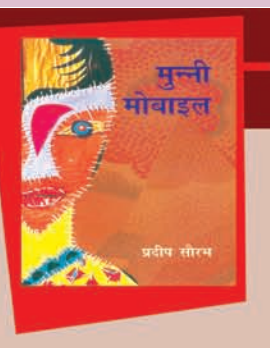

चंडीगढ़ में थे, तभी वह पत्रकारपुरम ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के सदस्य बन गए थे. मकान तैयार थे. लेकिन रहने लायक़ नहीं थे. रहने लायक़ बनाने के लिए छोटे-छोटे काम कराने थे. बिजली कनेक्शन से लेकर वुडवर्क तक सब बाक़ी था. इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें समय लगना था. अपने रहने के लिए कम से कम एक माह कहीं बतौर पेइंग गेस्ट का इंतज़ाम करना था. बहुत से काम करने थे. कामों की सूची बनाते हुए वह पूरी रणनीति को अंजाम दे रहे थे कि बिजली से रोशन शहर दिखा.

दिल्ली की सीमा पर बसा गुड़गांव था. फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी. साइबर सिटी की शक्ल ले रहा है गुड़गांव. मालवीय नगर पहुंचने के लिए बस एक घंटे की बात और थी. आख़िर वह एक घंटा भी ख़त्म हो गया. वह अपने मित्र के घर के बाहर खड़े थे. घंटी बजाई तो उन्होंने दरवाज़ा खोलकर उन्हें गले से लगा लिया, वेलकम दिल्ली.

अगले अंक में जारी...

जीवन प्रबंधन और चाणक्य

जो विचार चाणक्य ने सूत्र के रूप में सदियों पहले दिए थे, वे आज भी जीवन प्रबंधन के मामले में बेहद प्रभावी हैं. इस मामले में संदेह करने वाले इसे आज़मा कर देख सकते हैं. आज हालत यह है कि जीवन प्रबंधन की राह बताने वाले तथाकथित आधुनिक मैनेजमेंट गुरु लोगों से मोटी रकम वसूल रहे हैं. इसके बावजूद लोगों का जीवन सही दिशा में नहीं जा रहा है और उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, ऐसी हालत में किसी पश्चिमी विचार पर आधारित आधुनिक गुरुओं के विचारों पर अमल करने के बजाय भारतीय महापुरुषों के विचारों पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय समस्याओं का समाधान तो देसी तरीक़े से ही होगा.

जब बात जीवन प्रबंधन की हो तो इंसान को कई मोर्चों पर सजगता के साथ काम करना आवश्यक हो जाता है. हर क्षेत्र में कार्य करने के दौरान हर किसी को अलग-अलग तरह के कई लोगों से मिलना होता है. ऐसे में जिस इंसान के पास सही व्यक्ति को पहचानने की क्षमता रहती है, वह उतना ही आगे बढ़ जाता है. पर अहम सवाल यह है कि सही व्यक्ति की पहचान आख़िर कैसे की जाए? इस सवाल का जवाब चाणक्य अपने कई सूत्रों के ज़रिए देते हैं. उन्हीं में से एक है-ज्ञानानुमानैश्च परीक्षा कर्तव्या. इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान और अनुमान के आधार पर परीक्षा ली जानी चाहिए. किसी व्यक्ति का चयन अगर किसी काम के लिए करना है, तो सबसे पहले उसके ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए. उसे जो काम दिया जा रहा है, उसे वह जानता भी है या नहीं. उस विषय के बारे में वह कितना जानता है. इसके अलावा उसके पहले के कार्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि उसे जो काम दिया जा रहा है, वह उसे कर पाने में सक्षम है भी या नहीं. अगर किसी व्यक्ति को न तो विषय की जानकारी हो और न ही उसने उस विषय से जुड़े काम किए हों, तो स्वाभाविक तौर पर उसके लिए उस विषय विशेष में सफल हो पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. इसलिए किसी भी काम के लिए व्यक्ति का चयन करते वक़्त उसके ज्ञान और अनुभव को विशेष तौर पर देखना चाहिए.

किसी भी इंसान के जीवन प्रबंधन में उसकी नेतृत्व क्षमता का अहम योगदान होता है. इसलिए जीवन में सफलता की चाह रखने वालों को अपने अंदर यह क्षमता विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए. इस प्रक्रिया में चाणक्य द्वारा सदियों पहले दिए गए सूत्र बेहद अहम हैं. उन्होंने एक जगह लिखा है-स्वयमेवावस्कन्नं कार्य निरीक्षेत. मतलब यह कि स्वयं बिगड़े या अन्यों के बिगाड़े कार्यों

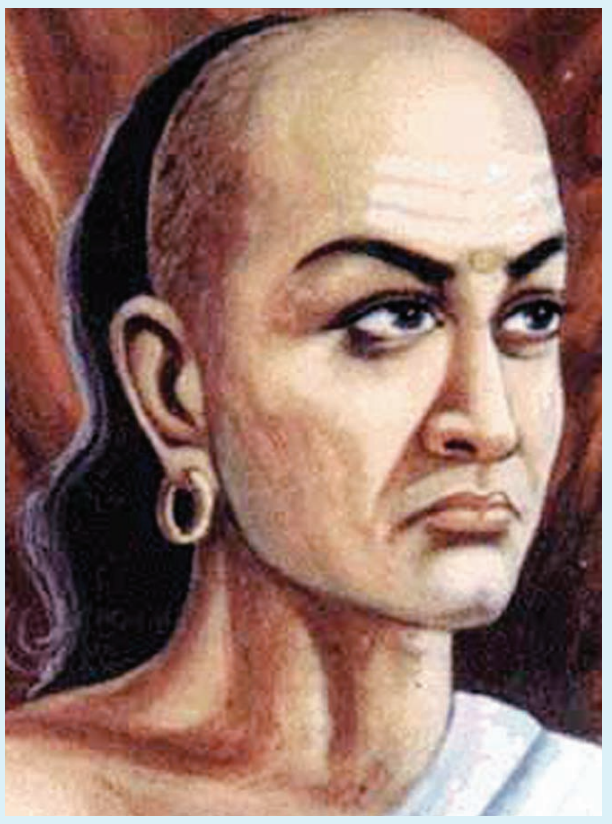

का स्वयं निरीक्षण करना चाहिए. नेतृत्व करने और ऐसी इच्छा रखने वालों के लिए यह एक बेहद अहम सूत्र है. एक योग्य नेतृत्वकर्ता का यह बुनियादी गुण है कि जिस तरह से सफलता का श्रेय उसे ख़ुद मिल जाता है, उसी तरह से उसे आगे बढ़कर असफलता की ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए. जब नेतृत्वकर्ता आगे बढ़कर ख़ुद काम को देखता है और उसे निपटाने में कामयाब रहता है, तो इसका सकारात्मक असर उसके साथ काम करने वाले लोगों पर भी पड़ता है. सही मायने में कहा जाए तो एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत हो जाता है. सफल नेतृत्वकर्ता बनने के लिए यह भी बेहद ज़रूरी है कि आपने अगर कोई काम किसी को सौंपा है तो उस पर निगाह बनाए रखें. अगर कोई समस्या आती है तो समाधान के लिए ख़ुद आगे बढ़ें. ऐसा करने से आपने जिसे उस काम की ज़िम्मेदारी दे रखी है, उसके मन में आपके प्रति सम्मान बढ़ता है. इसके अलावा वह उस काम को पूरा करने में दोगुने उत्साह के साथ लग जाता है.

इसी तरह जीवन में सफल होने के लिए सही समय की पहचान भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो सही समय को पहचानने में कामयाब नहीं रहते हैं, उनका जीवन कई मुश्किलों से भर जाता है. अवसर तो हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन उन अवसरों को सही समय पर जो पहचान लेता है, वह सफल हो जाता है. जो इन अवसरों को पहचानने में चूक कर देते हैं, वे असफल लोगों में शुमार किए जाने लगते हैं. इस काम में भी आचार्य चाणक्य अपने सूत्रों के ज़रिए आज भी लोगों की मदद करते हुए दिखते हैं. उन्होंने एक जगह लिखा है- प्रत्यक्षपरोक्षानुमानैः कार्याणि परीक्षेत.

मतलब यह कि उपलब्ध साधनों एवं अनुमानों से कार्यों की परीक्षा करें. दरअसल, किसी भी कार्य को सफल बनाने में यह सूत्र बड़ा सहायक है. कार्य को शुरू करने से पहले इस बात का विचार करना बेहद ज़रूरी है कि कार्य को करने में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कार्य को अंजाम देने के लिए ज़रूरी चीज़ों में से आपके पास क्या-क्या है, क्या-क्या चीज़ें मंगानी हैं और उक्त ज़रूरी चीज़ें कहां से मिलेंगी. इन बातों पर विचार करके कार्य की शुरुआत करने पर उसमें हानि नहीं होती है और काम पूरा होता है. ऐसा करने के लिए उपलब्ध साधनों पर निगाह डालना ज़रूरी है. साथ ही अपने और दूसरों के नए-पुराने अनुभवों का इस्तेमाल भी इसमें करना चाहिए.

जीवन प्रबंधन में किसी भी व्यक्ति के चरित्र की अहम भूमिका होती है, क्योंकि चरित्र के आधार पर ही किसी व्यक्ति का विचार एवं व्यवहार तय होता है. चरित्र के आधार पर ही व्यक्ति का आचरण होता है. आचरण के मुताबिक ही कर्म होते हैं और फिर उसी कर्म के आधार पर फल मिलता है. इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी भी इंसान की सफलता में चरित्र की कितनी अहम भूमिका है. चरित्र निर्माण के लिए भी आचार्य चाणक्य ने कई सूत्र दिए हैं. उनके द्वारा दिया गया एक सूत्र है-आर्यवृत्तमनुतिष्ठेत. मतलब यह कि श्रेष्ठ स्वभाव को बनाए रखें. इस सूत्र के निहितार्थ बड़े गहरे हैं. सामान्य और सुखद परिस्थितियों में और ख़ासतौर पर अपने प्रियजनों के साथ स्वभाव की श्रेष्ठता तो बरक़रार रहती है, लेकिन जैसे ही इन परिस्थितियों में बदलाव आता है, स्वभाव पर फ़र्क़ पड़ जाता है. सफलता की चाह रखने वालों को इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए. किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि आपके संपर्क में जो भी लोग आएं, उनसे आप अच्छा व्यवहार करें. ऐसा तभी संभव हो पाएगा, जब आपका स्वभाव ठीक होगा. स्वभाव की ख़राबी स्वाभाविक तौर पर काफी नुक़सान पहुंचाती है. बने हुए काम भी अच्छा बर्ताव न करने की वजह से बिगड़ जाते हैं. वहीं कई बिगड़े हुए काम भी बढ़िया स्वभाव की वजह से बन जाते हैं. जिसका स्वभाव श्रेष्ठ होता है, उसके संबंध सभी से अच्छे होते हैं. वहीं जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होता, लोग उससे कटने लगते हैं. ऐसे लोगों के लिए सफलता की राह बेहद मुश्किल हो जाती है. इसलिए सफलता के आकांक्षी लोगों के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि वे अपने स्वभाव को अच्छा बनाएं.

हिमांशु शेखर
feedback@chauthiduniya.com

बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़ सीडान भारतीय बाज़ार के लिए ख़ास है, क्योंकि इसमें ट्विन टर्बो और वॉल्वेट्रॉनिक स्ट्रेट सिक्स पेट्रोल इंजन है, जो विश्व में पहली बार इसी सीरीज़ की गाड़ियों में इस्तेमाल किया गया है.

कार की शानदार सवारी

शानदार कारों की निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू भारत में मिली सफलता से बेहद ख़ुश है. कंपनी ने भारत में फाइव सीरीज़ में नई कारें लांच की हैं. बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़ रेंज में दो नए मॉडल 535–आई एवं 523–आई डीजल इंजन और 530–डी एवं 525–डी पेट्रोल इंजन वाले हैं. उक्त कारें चमचमाते सफ़ेद, स्पेस ग्रे, टिटानियम सिल्वर, ब्लैक सफायर, सिल्वर डीप सी ब्लू एवं इंपीरियल ब्लू आदि रंगों में उपलब्ध हैं. कार की सीटों को आरामदायक और ख़ूबसूरत बनाने के लिए डकोटा लेदर का इस्तेमाल किया गया है, जो ओएस्टर ब्लैक, ब्राउन ब्लैक, ओएस्टर डार्क एवं ओएस्टर लाइट आदि रंगों में उपलब्ध है. बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़ सीडान स्टाइल, पावर और लुक की बैलेंस शोपीस कार है. पेट्रोल इंजन 530–डी एवं 525–डी कार की क़ीमत क्रमश: 45,90,000 और 39,90,000 रुपये है.

डीजल इंजन 523–आई एवं 535–आई की क़ीमत क्रमश: 38,90,000 और 58,00,000 रुपये है. उक्त कारें कंपनी के चेन्नई स्थित प्लांट में बनाई जाएंगी. बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़ सीडान भारतीय बाज़ार के लिए ख़ास है, क्योंकि इसमें ट्विन टर्बो और वॉल्वेट्रॉनिक स्ट्रेट सिक्स पेट्रोल इंजन है, जो विश्व में पहली बार इसी सीरीज़ की गाड़ियों में इस्तेमाल किया गया है. बीएमडब्ल्यू 523–आई और 525–डी में आठ स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हैं.

बीएमडब्ल्यू 535–आई और 530–डी में आठ स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ स्टेयरिंग व्हील पर शिफ्ट पैडल हैं. बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़ की गाड़ियों की ख़ासियत इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग के साथ सर्वोट्रॉनिक है. कंपनी की अन्य गाड़ियों में यह फीचर नहीं है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ब्लैक बेरी की नई रेंज

उपभोक्ता रोजमर्रा के लिए एक ऐसा मोबाइल सेट चाहते हैं, जो उनकी बहुत सी ज़रूरतों को एकसाथ पूरा कर सके. मोबाइल कंपनियां उपभोक्ताओं को कुछ नया और बेहतर देने के लिए रोज़ नए प्रयोग भी कर रही हैं. ब्लैकबेरी मोबाइल तो युवाओं में फैशन और स्टाइल का पर्याय माना जाने लगा है. ब्लैकबेरी ने अपने दो नए हैंडसेट ब्लैक बेरी बोल्ड–9650 और ब्लैक बेरी पर्ल–3जी के नाम से मार्केट में उतारे हैं. कंपनी के प्रेसिडेंट एवं सीईओ माइक लेजार्डिस का कहना है कि यह नया मॉडल कम्युनिकेशन, मल्टी मीडिया एवं कनेक्टिविटी का एक नया और बेहतरीन अनुभव देगा. इसकी तुलना दुनिया के बेहतरीन मोबाइलों से की जा सकती है. इसके डिज़ाइन में भी आकर्षक परिवर्तन किया गया है. मोबाइल का की–पैड वाई–फाई के साथ ऑप्टिकल ट्रैक वाला है. यूजर्स इसमें वेब ब्राउज़ करने, मेल भेजने और प्राप्त करने के दौरान बातचीत भी कर सकते हैं. यह मोबाइल

प्री–लोडेड 512 एमबी फ्लैश और एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड के साथ उपलब्ध है. इसमें 32 जीबी माइक्रोसॉफ्ट एसडीएचसी कार्ड्स भी है. ब्लैक बेरी का नया मॉडल बोल्ड–9650 स्मार्टफोन 3जी नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है. इसका कैमरा फ्लैश के साथ 3.2 मेगा पिक्सल का है. साथ ही ज़ूम, इमेज स्टेबलाइज़ेशन एवं ऑटो फोकस वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध हैं. अन्य विशेषताओं में एडवांस मीडिया प्लेयर, पिक्चर्स, म्यूज़िक और ब्लूटुथ के सपोर्ट के लिए 3.5 एमएम का स्टीरियो हैंडसेट जैक है. वहीं पर्ल 3जी का स्क्रीन 2 इंच से भी कम खुला हुआ है और इसका वजन 93 ग्राम है. दोनों मोबाइलों में जीयो टैगिंग है, जिससे जीपीएस को सपोर्ट मिलता है. इसमें ब्लैक बेरी मैप और अन्य मैपिंग एप्लीकेशंस मौजूद हैं. इसमें वो सारी ख़ूबियां हैं, जो एक अच्छे मोबाइल हैंडसेट में होनी चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

यामाहा की एफज़ेड सीरीज़ का नया रूप

यामाहा ने अपनी एफज़ेड–16 एवं एफज़ेड–एस सीरीज़ की मोटरसाइकिलें नई कलर स्कीम और ग्राफिक्स के साथ पेश की हैं. इसके अलावा यामाहा अब एफज़ेड– 16 एवं एफज़ेड–एस मोटरसाइकिलों को एक ही स्टाइल स्टेटमेंट के तहत रखेगी, जिसे स्टाइलिश माचो कहा जाएगा. नई एफज़ेड–एस ब्लैक, साइबर ग्रीन, सिल्वर एवं इलेक्ट्रिक ब्ल्यू रंगों और एफज़ेड–16 लावा रेड एवं मिडनाइट ब्लैक रंगों में उपलब्ध होगी. यामाहा ने इन पर एक नया लोगो भी लगाया है. नई मोटरसाइकिलें बीएस–3 उत्सर्जन नियमों के अनुरूप होंगी. कंपनी के निदेशक एवं प्रमुख बिक्री अधिकारी कोजी अराई ने बताया कि एफज़ेड–16 एवं एफज़ेड–एस सीरीज़ के ताज़ा संस्करणों के साथ हम 150 सीसी एवं उससे अधिक क्षमता की मोटरसाइकिलों के सेगमेंट में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहते हैं. हमारी योजना है कि वर्ष के अंत तक इस सेगमेंट में अपने हिस्से को 12 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुंचाएं. एफज़ेड सीरीज़ की मोटरसाइकिलों में बदलाव करते हुए हमने इनका मौलिक अंदाज़ बरक़रार रखा है. इनमें 153 सीसी का एयरकूल 4–स्ट्रोक, सिंगल सिलिंडर हाई टॉर्क इंजन लगा है, जो चलाने वाले को सक्रिय रखेगा और आक्रामक राइडिंग का अनुभव देगा. इसके ऋणात्मक प्रेशर टाइप 26–एमएम कार्बोरेटर के साथ टीपीएस थ्रोटल पोजीशन सेंसर की वज़ह से इंजन की प्रतिक्रिया उम्दा होती है. इसका 5–स्पीड ट्रांसमिशन बाइक ड्राइविंग को आसान बनाता है. मिडशिप मफलर मशीन के केंद्र की ओर मौजूद होने के कारण बाइक के भार को अच्छा संतुलन मिलता है. साथ ही निकास क्षमता एवं हैंडलिंग बेहतर है. मोनोक्रॉस रियर सस्पेंशन यह सुनिश्चित करता है. बाइक्स की यह सीरीज़ युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

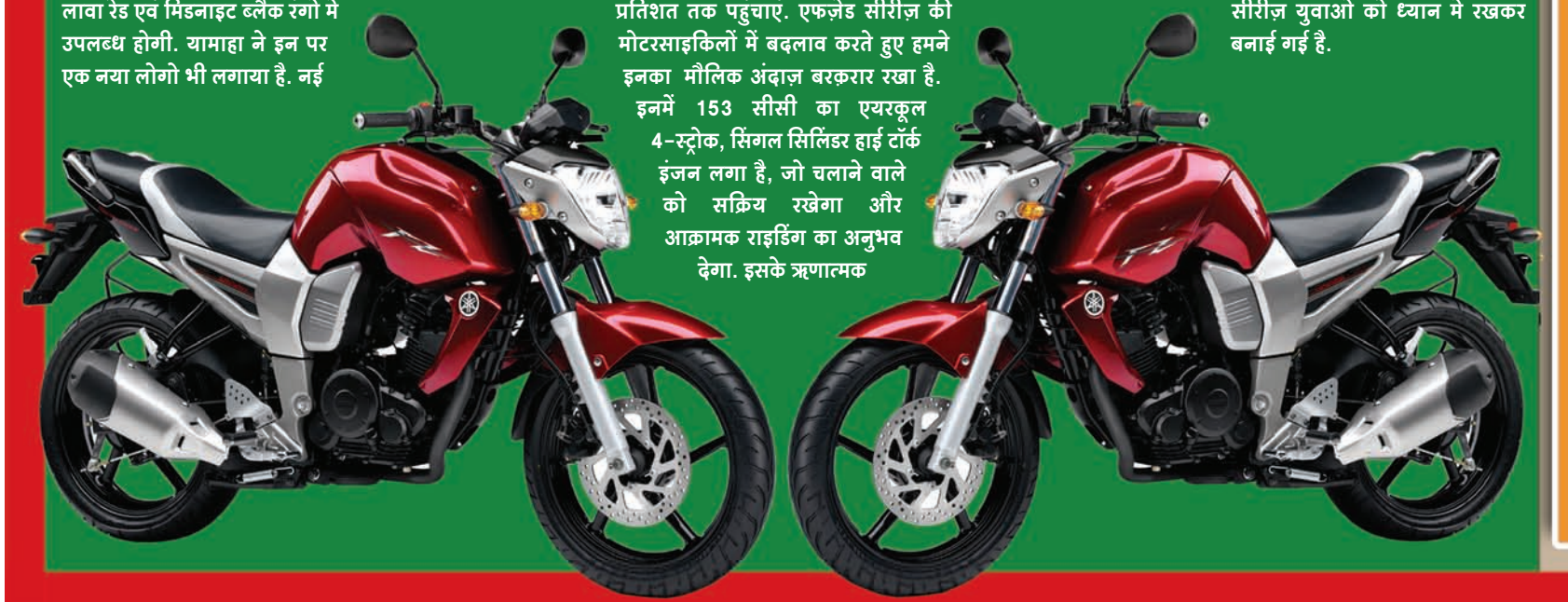

बिपाशा रियल एक्टिव की नई ब्रांड एंबेसडर

युवाओं में फिटनेस की चाहत को देखते हुए जानी–मानी कंपनी डाबर ने अपने प्रॉडक्ट रियल एक्टिव के लिए बॉलीवुड की हेल्थ आइकन बिपाशा बसु को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है.

इस मौक़े पर बिपाशा ने कहा कि मैं देश की इस विश्वसनीय कंपनी के प्रॉडक्ट नो शुगर 100 परसेंट जूस रियल एक्टिव से जुड़कर ग़ौरवान्वित महसूस कर रही हूं. मैं काफी समय से इसे इस्तेमाल करती आ रही हूं. आज के आधुनिक दौर में हम महिलाएं किसी सुपर वुमेन से कम नहीं हैं. हम काम और घर दोनों को साथ–साथ संभालते हैं. ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य की अक्सर अनदेखी करते हैं. पहले मैं खाने–पीने को लेकर बिल्कुल अव्यवस्थित थी. कोई निर्धारित समय नहीं था, कभी भी खा लिया. यह एक प्राकृतिक विकल्प है, जो मेरी व्यस्ततम और चुनौती भरी दिनचर्या में भी मुझे फिट रखता है. रियल एक्टिव जूस एक बढ़िया पेय है, जो आपके पसंदीदा स्नैक्स जैसे समोसे और सैंडविच की तुलना में 50 प्रतिशत कम कैलोरी देता है. साथ ही आसानी से पचता है. गर्मियों में यह आपको एनर्जी से भरपूर रखेगा. इसकी विशेषता यह है कि इसमें आपको शुद्ध फलों का स्वाद मिलेगा. कंपनी के मार्केटिंग हेड केके चुटानी ने कहा कि हमारे ब्रांड और बिपाशा बसु का परफेक्ट मैच है. दोनों ही हेल्थ और फिटनेस के पर्याय हैं. रियल एक्टिव प्राकृतिक जूस है. यह शुगर और कलर फ्री है और तीन फ्लेवर में उपलब्ध है. रियल एक्टिव आरेंज कैरोट जूस–यह आरेंज और कैरोट से बना है. यह एंटी ऑक्सिडेंट न्यूट्रिएंट्स है, जो बीटा कैरोटिन और विटामिन सी के गुणों से भरपूर है. रियल एक्टिव मिक्स्ड फ्रूट, साग और खीरे का जूस–यह फल और सब्जियों से बना है. यह सेव, संतरा, अमरूद, अनानास, आम, केला, एप्रीकोट और खीरे आदि का मिश्रण है. यह कैल्शियम एवं पोटेशियम से भरपूर है. रियल एक्टिव मिक्स्ड फ्रूट, चुकंदर और गाजर का जूस– यह कई फलों एवं सब्ज़ियों का मिश्रण है. इसमें भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और पोटेशियम है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

सवाल यह है कि इस देश में खेल और खिलाड़ियों का भविष्य क्या है? क्या हमारी पीढ़ियां पदकों की आस लिए इसी तरह बूढ़ी होती रहेंगी?

ऐसे क़ानून का क्या मतलब है

खेल संघों के पदाधिकारियों के कार्यकाल की अधिकतम सीमा तय करने संबंधी खेल मंत्री एम एस गिल के आदेश में ऐसा कुछ नहीं है, जिस पर हाय-तौबा मचे. यदि 25-30 साल तक अपने पद पर बने रहकर भी कोई पदाधिकारी खेल और खिलाड़ियों का भला न कर सके, तो फिर उसके होने का औचित्य क्या है? ओलंपिक हो या राष्ट्रमंडल खेल, पदकों की दौड़ में हमारे खिलाड़ी अभी भी सबसे पीछे रहते हैं. पदक जीतने के लिए उन्हें न तो ज़रूरी साज़ोसामान उपलब्ध कराया जाता है और न ही खेलों को अलविदा कहने के बाद कोई उनकी सुध लेता है. हमारा सवाल यह है कि सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं देती? खेल संघों को राजनीतिज्ञों के चंगुल से बाहर निकाल उन्हें पारदर्शी और ज़िम्मेदार बनाने के लिए पहल क्यों नहीं करती?

पिछले साल जब निशा शेट्टी की गिरफ्तारी हुई तो देश में खेल और खिलाड़ियों की हालत की असलियत सामने आ गई. छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने निशा को वेश्यावृत्ति के जुर्म में गिरफ़्तार किया था. काम गैरक़ानूनी है और असामाजिक भी, लेकिन अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए निशा मजबूर थी. खेल मंत्री और खेल संघों के कर्ताधर्ताओं के लिए यह एक शर्मनाक घटना थी, क्योंकि निशा राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाली एथलीट थी. कई प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के बाद भी निशा को कहीं नौकरी नहीं मिली. निशा का पति सुनील शेट्टी भी राष्ट्रीय स्तर का एथलीट था. नौकरी नहीं मिली और दुनियादारी की चिंताओं ने उसे शराबी बना डाला. फिर कुछ दिनों बाद शराब की इस आदत ने उसे इस दुनिया से ही रुख़सत कर दिया. निशा शेट्टी कोई आम लड़की नहीं है. निशा भी पी टी ऊषा की तरह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन करना चाहती थी. उसकी उपलब्धियां ऐसी हैं, जिन्हें पाने के लिए कई लड़कियां तमाम उम्र सपने ही देखती रह जाती हैं. लेकिन भारतीय खेल जगत के रहनुमाओं की कृपा से उसके सपने तो क्या, आज वह ख़ुद भी टूट चुकी है. केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेल संघों के पदाधिकारियों के कार्यकाल की समय सीमा निर्धारित करने पर उठे बवाल के बीच ज़्यादा मौज़ूं सवाल यह है कि अपनी कुर्सी बचाने की चिंता में लगे इन अधिकारियों को खिलाड़ियों की कितनी फ़िक्र है. क्या गिरफ़्तारी के बाद भी किसी ने निशा की कोई सुध ली? शायद नहीं. हर समय अपनी ही नौकरी (कुर्सी) बचाने की चिंता में लगे इन अधिकारियों के पास इतना समय कहां कि वे खिलाड़ियों के लिए नौकरी की चिंता करें, उनकी भलाई के लिए कुछ काम करें. किसी पूर्व या मौजूदा खिलाड़ी की दुर्दशा की ख़बरें आती हैं तो ये ऐसे बगलें झांकने लगते हैं, जैसे उनका कोई लेना-देना ही न हो, जबकि इनमें से कई ऐसे हैं, जो दशकों से विभिन्न खेल संघों के सर्वेसर्वा बने बैठे हैं. सवा अरब से ज़्यादा आबादी वाला भारत अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदकों की आस लिए बूढ़ा होता जा रहा है, लेकिन आज जब सरकार क़ानून बनाकर उनकी राजशाही को ख़त्म करने की कोशिश करती है तो उन्हें इसी साल दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की चिंता सताने लगती है. इसलिए नहीं कि इससे भारत के प्रदर्शन पर कोई असर पड़ेगा. उन्हें इसकी ज़रा भी फ़िक्र नहीं है कि प्रतियोगिता की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं और साज़ोसामान मुहैया कराया गया है या नहीं. उन्हें मलाल तो केवल इस बात का है कि सरकार उन्हें उनके मलाईदार पदों से हटाने की साजिश रच रही है.

सुरेश कलमाड़ी

अब ज़रा इन नामों और आंकड़ों पर ग़ौर करें. सुरेश कलमाड़ी-1996 से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं एथलेटिक्स फेडरेशन के आजीवन अध्यक्ष, विजय कुमार मल्होत्रा-1973 से राष्ट्रीय तीरंदाज़ी संघ के अध्यक्ष, सुखदेव सिंह ढींढसा-1996 से साइकिलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष, वी के वर्मा-1998 से बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष, बी एस आदित्यन-1998 से राष्ट्रीय बालीबाल फेडरेशन के अध्यक्ष, अभय चौटाला-2001 से राष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ के अध्यक्ष, अजय चौटाला-2000 से टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष, यशवंतसिंहा-2000 से ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष. सवाल यह है कि इनमें से कितने ऐसे लोग हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय ही नहीं, स्थानीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी उन खेलों का प्रतिनिधित्व किया है, जिसके आज वे सर्वेसर्वा बने बैठे हैं. इनमें विरले ही ऐसे हैं, जिनका खेलों से दूर का भी कोई रिश्ता रहा है. ये तो राजनीति की दुनिया के मठाधीश हैं, जो जोड़-तोड़ कर किसी तरह खेल संघों के पदाधिकारी बन बैठे हैं. इसके अपने फ़ायदे हैं. राजनीतिक पदों के विपरीत खेल संघों में अपने पद पर बने रहने के लिए जनता के सामने नहीं जाना पड़ता, अपने पिछले कार्यकाल का हिसाब नहीं देना पड़ता, सरकार और अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं से खेलों के विकास के लिए जो फंड मिलता है, उसका लेखा-जोखा भी नहीं रखना पड़ता. मोटी चमड़ी वाले इन नेताओं को और भला क्या चाहिए. इन अधिकारियों के कार्यकाल की अधिकतम सीमा निर्धारित करने संबंधी एम एस गिल के नए आदेश के विरोध की असली वजह यही है. खेल संघों की स्वतंत्रता पर चोट पहुंचने का अंदेशा तो एक बहाना भर है.

ख़ैर, यह तो हुई खेल संघों के अधिकारियों की बात. अब जरा खेल मंत्री के उस आदेश पर भी नज़र डालें, जिसके चलते यह सारा हंगामा खड़ा हुआ है. खेल मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि खेल संघों के अध्यक्ष या सचिव अधिकतम 12 साल तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं. इसके अलावा इसमें यह व्यवस्था भी है कि कोई भी अधिकारी 70 साल की उम्र के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता. अपने आदेश के पक्ष में तर्क देते हुए एम एस गिल कहते हैं कि यह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के मानकों के अनुरूप है. ग़ौरतलब यह भी है कि साल 1975 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी ऐसा ही एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन तमाम विरोध के बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और आज तक उस पर अमल नहीं हो पाया. फिर अब अचानक इस आदेश को जारी करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? इसके पीछे आख़िर सरकार की मंशा क्या है? खेल संघों और उनके पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने का तर्क गले से नहीं उतरता, क्योंकि ऐसा होता तो सरकार पहले उनसे उनकी अब तक की गतिविधियों का हिसाब-किताब मांगती, उनकी उपलब्धियां देखती, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है. नए आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि पदाधिकारी अपने मौजूदा कार्यकाल तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं. मतलब यह कि खेल संघों को अपनी व्यक्तिगत जागीर समझने वाले इन राजनीतिज्ञों को अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए पर्याप्त समय दे दिया गया है. इसके तार कहीं न कहीं अक्टूबर में शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े हैं. दरअसल, इन खेलों के लिए तैयारियों में जुटी सरकार को यह अंदेशा होने लगा है कि नए स्टेडियम, होटल, पुल और स्वीमिंग पूल भले बन जाएं, लेकिन पदकों के नाम पर देश को एक बार फिर शर्मसार होना पड़ सकता है. इन तैयारियों के पीछे सरकार अरबों रुपये ख़र्च कर रही है. इन पैसों को यदि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता तो देश के लिए नासूर बनती जा रही यह समस्या ख़त्म हो जाती. सरकार इन्हीं सवालों से घबरा रही है. उसे लग रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर पब्लिक मनी के इस्तेमाल का परिणाम सिफर रहा तो वह जनता को क्या जवाब देगी. ऐसी हालत में यह नया आदेश सरकार के लिए मददगार हो सकता है. सारा दोष खेल संघों और उनके पदाधिकारियों पर मढ़ कर वह अपना चेहरा बचा सकती है.

लेकिन सवाल यह है कि इन हालात के मद्देनज़र इस देश में खेल का भविष्य क्या है? क्या हमारी पीढ़ियां पदकों की आस लिए इसी तरह बूढ़ी होती रहेंगी? यदि समय रहते क़दम न उठाए गए तो शायद यही हमारी नियति बनकर रह जाएगी. वरना खेल पदाधिकारियों के कार्यकाल की अधिकतम सीमा 12 वर्ष निर्धारित करने का क्या औचित्य है? इन संघों की कार्यशैली कैसी है, इनके पदाधिकारियों का चुनाव कैसे होता है और इनकी बैठकों में फ़ैसले कैसे लिए जाते हैं, इन सब बातों की कोई चर्चा खेल मंत्रालय के आदेश में नहीं की गई है. होना तो यह चाहिए कि खेल संघों पर सरकार का नियंत्रण हो और इनके पदाधिकारियों को केवल एक साल के लिए चुना जाए. चुनाव गुप्त मतदान से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीक़े से हों और ऐसे ही लोगों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिले, जो खेल से जुड़े हों और जिनके पास कोई विजन हो. फिर कार्यकाल पूरा होने के बाद उनके प्रदर्शन की समीक्षा होनी चाहिए, ताकि पदाधिकारियों पर दबाव बना रहे. खेल संघों की आर्थिक गतिविधियों का सालाना लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार की आशंका कम हो. पदाधिकारियों के कार्यकाल की अधिकतम सीमा हो या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है. ज़्यादा अहम यह है कि इनकी ज़िम्मेदारियां तय हों, इनके प्रदर्शन का पैमाना निश्चित किया जाए. राजनीतिज्ञों के बजाय पूर्व खिलाड़ियों की भागीदारी हो, जो खेल को खिलाड़ियों के नज़रिए से देखें, न कि राजनीति के.

खेल मंत्री एम एस गिल के आदेश पर चाहे जितना भी शोरशराबा क्यों न हो, वास्तविकता यही है कि इसमें इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है. सरकार का यह प्रयास फटे कपड़े पर पैबंद लगाने से ज़्यादा कुछ नहीं है. आने वाला राष्ट्रमंडल खेल इसके लिए एक बढ़िया मौक़ा हो सकता है. सरकार को चाहिए कि वह अपनी खेल नीति स्पष्ट करे और इसमें इन सब तथ्यों को जगह मिले. तभी हम भविष्य में अपने खिलाड़ियों से पदकों की उम्मीद कर सकते हैं, वरना जाने कितनी निशा शेट्टी इसी तरह वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर होती रहेंगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विजय कुमार मल्होत्रा

रणधीर सिंह

रैना को रैना ही रहने दो

भारतीय क्रिकेट में अक्सर ऐसा ही होता है. किसी क्रिकेटर में भविष्य की संभावनाएं क्या दिखीं, लोग बेवजह की तुलनाएं कर उसे सिर आंखों पर बैठा लेते हैं. सुरेश रैना के साथ भी ऐसा ही हो रहा है. हालिया सफलताओं के बाद लोग उन्हें अगला सौरव गांगुली घोषित करने की जल्दबाज़ी में नज़र आ रहे हैं. लेकिन बेहतर होगा कि रैना को रैना ही बना रहने दें, वरना उनका भी हाल कहीं इरफान पठान की तरह होकर न रह जाए.

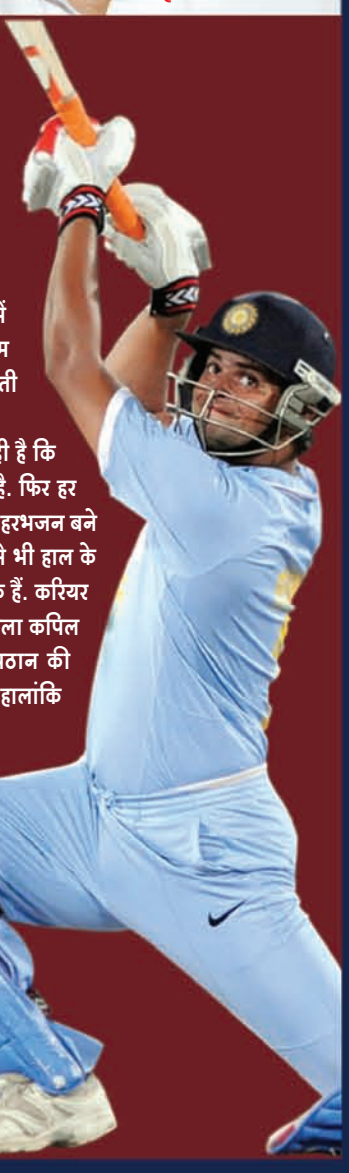

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम मौजूदा दौर में उन्हें विश्व क्रिकेट का सबसे चमकता हुआ सितारा मानते हैं तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर को लगता है कि वह टीम इंडिया में सौरव गांगुली द्वारा खाली की गई जगह को भर सकते हैं. मांजरेकर सहित तमाम क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें अब टेस्ट टीम में भी जगह मिलनी चाहिए. लेकिन, टीम इंडिया के बल्लेबाज सुरेश रैना न तो इन तुलनाओं की फ़िक्र करते हैं और न ही बढ़ी उम्मीदों के बोझ तले दब जाने का ख़ौफ़ उन्हें सता रहा है. रैना का तो बस यही मानना है कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहने से टीम में उनकी जगह सुरक्षित हो सकती है.

टी-20 वर्ल्ड कप के शुरुआती दौर में दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ उनकी शतकीय पारी को देखने के बाद रैना से बेशक़ उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन उन्हें सौरव गांगुली का विकल्प मानना जल्दबाज़ी हो सकती है. महज़ 23 साल के रैना ने 2005 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी. टीम इंडिया के तत्कालीन कोच ग्रेग चैपल ने तभी उन्हें बेशक़ीमती टैलेंट माना था, लेकिन प्रदर्शन में निरंतरता की कमी के चलते उन्हें जल्द ही टीम से बाहर होना पड़ा. इसके बाद टीम के अंदर और बाहर होने का सिलसिला चलता रहा. इंग्लैंड में हुए दूसरे टी-20 विश्व कप के बाद तो एक बार ऐसा लगा कि शॉर्ट पिच गेंद के ख़िलाफ़ कमज़ोरी के चलते रैना के अंतरराष्ट्रीय करियर पर ग्रहण लग सकता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आईपीएल के तीसरे सीज़न में चेन्नई सुपर किंग्स की खिताबी जीत में रैना की बल्लेबाज़ी की अहम भूमिका रही. हर तरह की गेंदबाज़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने जमकर रन बनाए. खेल के प्रति अच्छी समझ और बल्लेबाज़ी की आक्रामक शैली के बूते रैना आने वाले सालों में भारतीय क्रिकेट के खेवनहार बन सकते हैं, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी सौरव गांगुली के समतुल्य खड़ा करना ख़तरनाक हो सकता है.

टी-20 वर्ल्ड कप के शुरुआती दौर में दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ उनकी शतकीय पारी को देखने के बाद रैना से बेशक़ उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन उन्हें सौरव गांगुली का विकल्प मानना जल्दबाजी हो सकती है. वन डे और टी-20 में कामयाबी को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन सच्चाई यही है कि टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन ही किसी क्रिकेटर की सफलता का असली मापदंड माना जाता है.

गांगुली वन डे और टेस्ट क्रिकेट के सफलतम बल्लेबाज़ों में से एक रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 18 हज़ार से ज़्यादा रन उनके नाम दर्ज हैं. इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तानों में भी उनकी गिनती होती है. इसके विपरीत रैना अभी भी अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं. उन्होंने अब तक टेस्ट क्रिकेट खेला भी नहीं है.

वन डे और टी-20 में कामयाबी को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन सच्चाई यही है कि टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन ही किसी क्रिकेटर की सफलता का असली मापदंड माना जाता है. फिर हर खिलाड़ी की अपनी अलग पहचान होती है. हरभजन सिंह दूसरे प्रसन्ना नहीं बन सकते, लेकिन हरभजन बने रहकर ही वह भारतीय टीम के लिए मैच जिताऊ गेंदबाज़ी करते रहें तो इसमें बुराई क्या है. वैसे भी हाल के दिनों में हम अजीत आगरकर और इरफान पठान का हश्र देख चुके हैं. करियर के शुरुआती दौर में पठान ने अच्छा प्रदर्शन क्या किया, उन्हें अगला कपिल देव घोषित करने की मानों होड़ लग गई. नतीजा, दबाव में पठान की गेंदबाज़ी की धार कुंद होकर रह गई और आज वह टीम से बाहर हैं. हालांकि रैना को देखने से नहीं लगता कि इन तुलनाओं से वह घबरा जाएंगे या सफलता के रास्ते पर चलते हुए उनके पैर डगमगा जाएंगे, लेकिन कामयाबी का नशा कुछ ऐसा होता है कि युवा मन अक्सर अपना नियंत्रण खो बैठता है. डर इसी बात का है कि उम्मीदों के बोझ तले रैना भी दबाव में भटक न जाएं और भारतीय क्रिकेट को उनकी प्रतिभा से वंचित न होना पड़े. इसके लिए ज़रूरी है कि रैना को रैना ही बना रहने दें, उन्हें ज़बरदस्ती दूसरा सौरव गांगुली बनाने की भूल न करें.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 17 मई–23 मई 2010

पुणे शहर में पली-बढ़ीं सोनाली अपने घर को जन्नत कहती हैं. उनका मानना है कि घर में वह बिल्कुल फ्री और रिलैक्स महसूस करती हैं.

लक पर भरोसा

श्रुति हसन की पहली फ़िल्म *लक* बॉक्स ऑफिस पर भले ही सफल नहीं रही, पर यह नहीं कहा जा सकता कि सिक्का खोटा है. फ़िल्म *लक* की असफलता स्वीकारते हुए श्रुति कहती हैं कि उन्हें इस असफलता से सीख मिली है कि स्वयं की मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है. वह ग़लतियां सुधारने की कोशिश करेंगी. वह यह भी समझ गई हैं कि सब को ख़ुश रख पाना संभव नहीं है. सुनने में आ रहा है कि श्रुति ने हाल में गजनी के निर्देशक मुरुगदौस के साथ एक बड़ी फ़िल्म दक्षिण के सुपरस्टार सूर्या के अपोजिट साइन की है. हालांकि श्रुति अपनी आने वाली फ़िल्मों के बारे में बात नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि अभी तक उनकी किसी फ़िल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई है. ऐसे में कुछ कहना जल्दबाज़ी होगी. उनकी आने वाली दूसरी फ़िल्म में उनके सह अभिनेता सिद्धार्थ हैं, जिनके साथ उनके अफेयर की ख़बरें भी आ रही हैं. श्रुति बताती हैं कि यह सिर्फ़ अफवाह है. उन दोनों को एक-दूसरे का स्वभाव अच्छा लगता है, साथ ही दोनों की पृष्ठभूमि एक जैसी है जिससे लोगों को बोलने का मौक़ा मिल गया है.

लेकिन, सिद्धार्थ नहीं तो फिर कौन होगा श्रुति के सपनों का राजकुमार? जवाब में श्रुति कहती हैं कि उसका टैलेंटेड होना ज़रूरी है. वह स्वभाव से मज़ाकिया और दिमाग से बुद्धिमान होना चाहिए. वह कहती हैं कि मैं जितनी गंभीर दिखती हूं, दरअसल उतनी हूं नहीं. मेरा चेहरा सपाट है जिससे लोगों को लगता है कि मैं काफी गंभीर स्वभाव की हूं. सारिका और कमल हसन की बेटी होने के कारण लोगों को उनसे बहुत अपेक्षा थी, पर वह पूरी नहीं हो सकी. इस बारे में श्रुति स्पष्ट करती हैं कि उनका लालन-पालन एक स्टार संतान की तरह नहीं हुआ. आज तक जो भी काम कर रही हैं, वह उनकी स्वयं की मेहनत का फल है. श्रुति का मानना है कि अपने माता-पिता के काम पर मुझे गर्व है, पर उनके काम को आधार बनाकर मैं कभी काम मांगने नहीं गई और न ही मिला. श्रुति बताती हैं कि स्टार संतान होने का आपको तब तक कोई फ़ायदा नहीं मिलता, जब तक आपके काम में दम न हो. हम उम्मीद करते हैं कि श्रुति की आने वाली फ़िल्में उनके प्रशंसकों को ज़रूर ख़ुश करेंगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

एक आइडिया ने बना दी काइट्स: राकेश रोशन

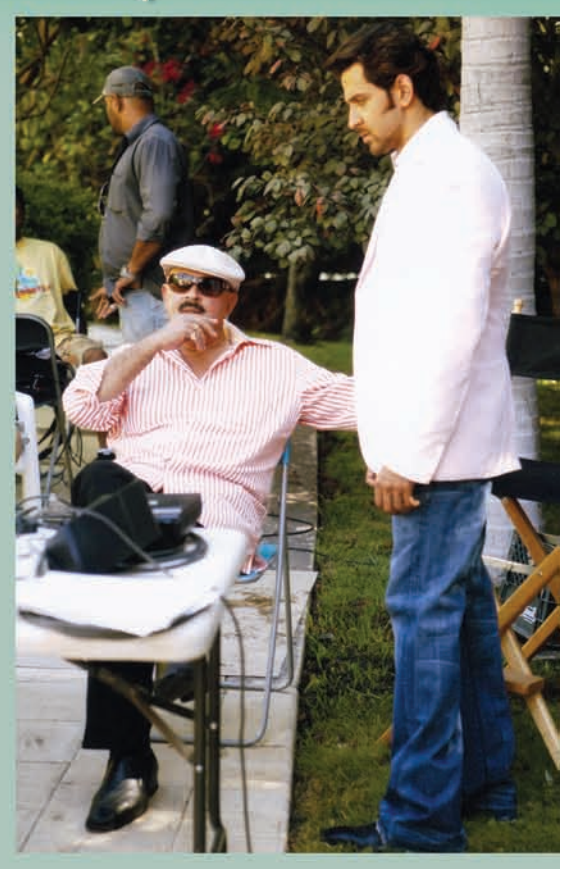

राकेश रोशन कई बेहतरीन फ़िल्में बना चुके हैं, जैसे *ख़ून भरी मांग, करण अर्जुन, कोई मिल गया, कृष, कहो ना प्यार है, कोयला एवं कामचोर.* उनकी एक और फ़िल्म *काइट्स* रिलीज़ होने के लिए तैयार है. इसमें देशी-विदेशी कलाकारों का संगम है. फ़िल्म में रितिक रोशन, मैक्सिको की अभिनेत्री बारबरा मोरी एवं कंगना रानावत भी हैं. निर्देशन अनुराग बासु ने किया है. काइट्स की स्क्रिप्ट से लेकर शूटिंग लोकेशन खोजने तक प्रोडक्शन के हर काम में राकेश रोशन पूरी तरह जुड़े रहे. पेश है चौथी दुनिया की संवाददाता रीतिका सोनाली की उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश:

काइट्स जैसे अलग विषय पर फ़िल्म बनाने का विचार कैसे आया?

कृष बनाने के बाद कृष-2 के लिए काफी लंबा समय था तो मैंने सोचा कि किसी दूसरी स्क्रिप्ट पर काम करूं. एक अच्छा आइडिया आया तो मैंने अनुराग बासु से मुलाक़ात की और उन्हें वह आइडिया दिया. उन्होंने उस पर पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली. बस फिर क्या था, तैयार थी काइट्स की कहानी.

आपने मैक्सिकन अभिनेत्री को क्यों लिया, जबकि आप किसी भी बॉलीवुड अभिनेत्री को लेकर उसे मैक्सिकन लड़की के रूप में दिखा सकते थे?

हम फ़िल्म को वास्तविक रूप देना चाहते थे. कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते थे, जिससे फ़िल्म बनावटी लगे और हंसी का पात्र बने. इसलिए हमने किसी बॉलीवुड अभिनेत्री को नहीं लिया और मैक्सिकन अभिनेत्री की तलाश शुरू कर दी. इसके लिए हमने मुंबई में मैक्सिकन लड़कियों का ऑडिशन लिया. उसी समय हमने लॉस एंजिल्स में सेलिब्रिटी एजेंट से मैक्सिकन लड़की के लिए बात की. तभी मेरे एक दोस्त का फोन आया और उसने हमें बारबरा मोरी की फ़िल्म *माय ब्रदर्स वाइफ* देखने को कहा. फिर मैंने एवं रितिक ने वह फ़िल्म देखी और हमें बारबरा जंच गई. उसके बाद बारबरा से दोस्तों और ई-मेल के ज़रिए बात हुई. फिर उन्हें फ़िल्म की कहानी सुनाने के लिए मैं और अनुराग मैक्सिको गए. उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आ गई. बारबरा को बॉलीवुड के फ़िल्म पैटर्न, जिसमें डांस और गाने मुख्य होते हैं, को लेकर डर था. हमने उन्हें रितिक की फ़िल्म *जोधा अकबर* की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने का आमंत्रण दिया. फ़िल्म देखने के बाद उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि क्या उन्हें भी नाचना और गाना पड़ेगा. तब हमने उन्हें समझाया कि गाना तो है, पर वह बैकग्राउंड में बजेगा. यह सुनकर वह ख़ुश हो गईं. उन्हें कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने हां कर दी.

फ़िल्म की शूटिंग कहां-कहां हुई?

बारबरा से मिलने के बाद लोकेशन खोजने के लिए हमारी मैक्सिको जाने की योजना थी, पर तभी हमें किसी ने बताया कि न्यू मैक्सिको भी बिल्कुल मैक्सिको जैसा है, जो अमेरिका में स्थित है. फिर मैंने एवं अनुराग ने इंटरनेट पर खोजा तो पता लगा कि हमारी सारी लोकेशंस वहीं मिल जाएंगी, इसलिए सारी शूटिंग हमने न्यू मैक्सिको में ही पूरी की.

इस फ़िल्म के स्टंट सीन काफी चुनौती भरे हैं, जो पहले कभी नहीं देखे गए. क्या इसमें किसी हॉलीवुड टेक्नीशियन की सहायता ली गई है?

मैं अपने स्टंट डायरेक्टर से ज़्यादा ख़ुश नहीं था. मैंने सोचा कि अगर हॉलीवुड फ़िल्मों को मात देना है तो किसी नए स्टंट डायरेक्टर को लाया जाए. मैंने अपना यह विचार रितिक और अनुराग को बताया. फिर हमने प्रशांत शाह से बात करनी शुरू की, जो हॉलीवुड में शूटिंग की सभी ज़रूरी चीजें बॉलीवुड के लोगों को दिलाते हैं, मगर उस समय वह फ़िल्म *कमबख्त इश्क* में व्यस्त थे. उन्होंने मुझे स्पीरो राजंटोस के बारे में बताया. उन दिनों वह ब्रेक पर थे तो उन्होंने हमारी बात मान ली और काम करने के लिए तैयार हो गए. उन्होंने कहा कि इस फ़िल्म के स्टंट में काफी सामान जैसे हेलीकॉप्टर, स्पेशल कैमरा, स्टंट ड्राइवरों की टीम और टेक्नीशियन की ज़रूरत है. उनकी बातें सच थीं और इन्हीं सामानों की मदद से हमने फ़िल्म में बड़े-बड़े स्टंट किए. रितिक ने वे सारे स्टंट ख़ुद किए और बिना किसी प्रकार की दुर्घटना के.

सोनाली की चाहत

हाल में आई श्याम बेनेगल की फ़िल्म *वेल डन अब्बा* में रवि किशन की पत्नी की भूमिका में सोनाली ख़ूब जंची हैं. बहुत कम फ़िल्में करने के बाद भी सोनाली की गिनती बॉलीवुड की अच्छी अभिनेत्रियों में होती है. क्या सोनाली अपनी उपलब्धियों से ख़ुश हैं? इस सवाल के जवाब में सोनाली कहती हैं कि वह जल्दी में नहीं हैं. वह जहां तक पहुंची हैं, वहां संतुष्ट हैं और उन्हें सही वक़्त का इंतज़ार है. अलग-अलग भूमिकाएं निभा कर वह उन किरदारों से अपनी निजी ज़िंदगी में भी सीख लेती हैं. पुणे शहर में मराठी परिवार में पली-बढ़ी सोनाली अपने घर को जन्नत कहती हैं. उनका मानना है कि घर पर वह ख़ुद को बिल्कुल फ्री और रिलैक्स महसूस करती हैं. जब वह शूटिंग नहीं कर रही होती हैं, तब उनका दिन प्राणायाम से शुरू होता है और फिर वह चाय लेती हैं. उन्हें खाना पकाने का बहुत शौक़ है. उनके प्रतिदिन के खाने में उनकी मां द्वारा सिखाए गए पारंपरिक व्यंजन होते हैं. वह खाना पकाते हुए धीमा संगीत सुनना पसंद करती हैं. वह प्रतिदिन वर्कआउट ज़रूर करती हैं, क्योंकि उनका वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है. लंच से पहले वह प्रतिदिन दस मिनट का ध्यान करती हैं. सलोनी अलौकिक शक्ति का अभिनंदन प्रतिदिन शाम को अपने घर में दीप जलाकर करती हैं. वह काफी समय तक विवा पत्रिका की अतिथि संपादक रही हैं. इस पत्रिका में हर हफ्ते उनका संपादकीय *सो कूल* नाम से छपता रहा है. अभी कुछ दिनों पहले उनके इसी कॉलम में छपे सौ लेखों को संपादित करके एक किताब का रूप दिया गया है, जिसका नाम भी सो कूल है. सोनाली कहती हैं कि इस किताब के आने से वह बहुत ख़ुश हैं, क्योंकि उन्हें लिखना बहुत पसंद है. यह किताब उन्हें ज़िंदगी में मिले अमूल्य तोहफ़े की तरह है. जब वह कहीं भी दूर लंबी यात्रा पर निकलती हैं तो कुछ लिखने के ख्याल से कलम और डायरी अपने पास ज़रूर रखती हैं.

फ़िल्म प्रिव्यू

राजनीति

दामुल एवं अपहरण जैसी फ़िल्मों के माध्यम से बिहार में बंधुआ मज़दूरी और अपहरण जैसे मसलों को उठाने वाले प्रकाश झा अब नई फ़िल्म राजनीति के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. *गंगाजल* के बाद प्रकाश ने एक बार फिर अपने पसंदीदा विषय पर फ़िल्म बनाई है. इस बार उन्होंने महाभारत के चरित्रों को अपना आधार बनाया है. फ़िल्म में उन सभी मसालों का पुट है, जो उनकी फ़िल्मों के यूएसपी माने जाते हैं. मसलन उनके पसंदीदा कलाकार अजय देवगन एवं नाना पाटेकर है. इसके अलावा युवाओं को ध्यान में रखते हुए रणवीर कपूर एवं कैटरीना कैफ की जोड़ी भी है. साथ ही नसीर, मनोज वाजपेयी एवं अर्जुन रामपाल भी प्रमुख किरदारों में नज़र आएंगे. फ़िल्म में राजनीति में होने वाले घिनौने खेलों और बदलते चरित्रों को दिखाया गया है. फ़िल्म उसी समय से चर्चा में है, जब कैटरीना के पोस्टर सोनिया गांधी के लुक में जारी किए गए थे. अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि राजीव और सोनिया से मिलता-जुलता लुक रणवीर और कैटरीना पर आज़माया गया है. हालांकि झा ने कहा है कि इसमें किसी भारतीय राजनीतिज्ञ, राजनीतिक पार्टी अथवा वर्तमान या बीते समय की घटनाओं को नहीं दर्शाया गया है. उनके मुताबिक़, मैंने सिर्फ़ सत्ता के लिए सब कुछ छोड़ने वाले परिवार की कहानी दिखाने की कोशिश की है. उन्होंने बताया कि बॉलीवुड के शीर्ष सितारों, चार साल की कड़ी मेहनत और भारी-भरकम बजट वाली इस फ़िल्म के निर्देशक नहीं चाहते कि उनके साथ कोई संकट खड़ा हो. उनका मानना है कि दर्शक ही फ़िल्म देखकर अपना निर्णय देंगे. सच्चाई चाहे जो भी हो, पर फ़िल्म को सुर्खियां ख़ूब मिल रही हैं. यूटीवी मोशन पिक्चर्स इस फ़िल्म की सह निर्माता है. संगीत निर्देशन इयान शार्पे का है. इयान इससे पहले *गंगाजल* के लिए पुरस्कृत हो चुके हैं. गीत गुलजार, समीर एवं स्वानंद किरकिरे ने लिखे हैं, जबकि स्क्रीनप्ले प्रकाश और अंजुम राजाबाली का है. 4 जून को रिलीज़ हो रही इस मेगा बजट फ़िल्म से बॉक्स ऑफिस को काफी आशाएं हैं.

आईपीएल की आंधी की मार

भट्ट कैंप की कई फ़िल्में करके अपनी ग्लैमरस इमेज बनाने वाली उदिता गोस्वामी हालिया रिलीज़ फ़िल्म *रोक* में बिल्कुल नॉन ग्लैमरस लड़की की भूमिका में नज़र आईं, लेकिन दर्शक तो उस हॉट उदिता को देखना चाहते थे, जो उन्हें *पाप, ज़हर, अक्सर* एवं *अगर* आदि फ़िल्मों में नज़र आईं थीं. हाल में आई फ़िल्म *चेज* में भी उन्होंने एक्टिंग की है, लेकिन यह फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई. उदिता कहती हैं कि एक्शन रोल करना उनके लिए नया अनुभव था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी फ़िल्म में ऐसा नहीं किया. उदिता कहती हैं कि फ़िल्म चेज का थ्रिलर लाजवाब था, पर यह ग़लत वक़्त पर रिलीज़ होने की वज़ह से चल नहीं पाई. थ्रिलर ऐसा सब्जेक्ट है, जिससे दर्शकों का मनोरंजन होता है. चेज से पहले आई उनकी फ़िल्म रोक हॉरर थ्रिलर होने के बावजूद नहीं चल पाई. इसका भी उन्हें अफसोस है. इसका कारण भी वह फ़िल्म का ग़लत वक़्त पर रिलीज़ होना बताती हैं. जब रोक और चेज रिलीज़ हुई, तब आईपीएल मैच चल रहे थे. भारत क्रिकेट प्रेमियों का देश है, इसलिए आईपीएल की आंधी में कई अच्छी फ़िल्में उड़ गईं. लेकिन इस हार के बार भी उदिता ने एक कड़ा फैसला लिया है कि अब वह उन्हीं फ़िल्मों में काम करेंगी, जो दर्शक का हर वर्ग देख सकेगा, चाहे वह बच्चे हों या बुज़ुर्ग. वह अब रोमांटिक-कॉमेडी फ़िल्में ज़्यादा करना चाहेंगी. उन्हें लगता है कि ग्लैमरस, थ्रिलर या हॉरर फ़िल्में बच्चे नहीं देख पाते. अब तक आईं उनकी फ़िल्में थ्रिलर और हॉरर जॉनर हैं या फिर वैसी हैं, जिनमें उनका रोल काफी ग्लैमरस है. उदिता की आने वाली फ़िल्मों में *अमर जोशी शहीद हो गया, बेगुनाह, द मैन और हैलो इंडिया* आदि प्रमुख हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 17 मई–23 मई 2010

www.chauthiduniya.com

सुप्रीम कोर्ट, बिहार सरकार और बंधुआ शिक्षक

शशिशेखर

अमूमन सुप्रीम कोर्ट की कही हर बात अंतिम होती है. उसका आदेश क़ानून माना जाता है और जिसे मानने के लिए हर व्यक्ति, संस्था या सरकार बाध्य है, लेकिन जब कोई राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानने में आनाकानी या देरी करे तो इसे क्या कहेंगे? शायद यही कि पंचों का हुक्म सिर माथे, लेकिन नाला वहीं बहेगा. मतलब अदालत कुछ भी कहे, हम तो वही करेंगे, जैसा हम चाहते हैं. कुछ यही हाल है बिहार सरकार का. मामला प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली और सरकारी वेतनमान का है.

बिहार सरकार, चुनावी राजनीति और शिक्षक भर्ती में काफी गहरा रिश्ता है. लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक ने शिक्षक नियुक्ति के मामले को अपने-अपने राजनीतिक फायदे के लिए खूब भुनाया. दरअसल बिहार में पहले प्रशिक्षित शिक्षकों की सीधी बहाली की जाती थी. यानी जो उम्मीदवार टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स पूरा कर लेता था, उसे शिक्षक के पद पर सीधे नियुक्त कर दिया जाता था, लेकिन 1991 के बाद जब लालू यादव सत्ता में आएं तो पूरा मामला ही उलट दिया गया. लालू यादव के समय शिक्षकों की भर्ती खुली प्रतियोगिता परीक्षा के ज़रिए की गई, जिसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षित होना ज़रूरी नहीं था. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक शर्त है. नतीजतन, जो अप्रशिक्षित उम्मीदवार सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए थे, उन्हें भी बाद में टीचर्स ट्रेनिंग दिलाई गई. 2005 में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली, तब उन्होंने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लाखों की संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने की घोषणा की. सर्व शिक्षा अभियान की वजह से ऐसा करना ज़रूरी भी था, लेकिन इस बार भी नीतीश कुमार उन प्रशिक्षित उम्मीदवारों को भूल गए, जो लालू यादव के शासनकाल में नौकरी पाने से वंचित रह गए थे. इसके विपरीत तीन से पांच हज़ार रुपये के नियत वेतनमान और प्राप्तांक के आधार पर शिक्षा मित्र एवं पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई. इस क्रम में ऐसे उम्मीदवारों की भी नियुक्ति हुई, जो प्रशिक्षित नहीं थे. बाद में अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी इग्नू से एक करार करके टीचर्स ट्रेनिंग दिलवाई गई. इस दौरान प्रशिक्षित उम्मीदवार भी रोज़गार के लालच में पांच हज़ार रुपये के नियत वेतनमान पर पंचायत शिक्षक के तौर पर नौकरी करने लगे. इस आशा में कि कभी न कभी उन्हें भी सरकारी वेतनमान मिलेगा, लेकिन अभी भी क़रीब 35 हज़ार प्रशिक्षित शिक्षकों में से अधिकांश को नौकरी नहीं मिल सकी है या फिर जिन्हें नौकरी मिली भी है, वे सरकारी वेतनमान से वंचित हैं. यानी प्रशिक्षित शिक्षक एक तरह से बंधुआ मजदूर की हैसियत से काम कर रहे हैं. ग़ौरतलब है कि दिसंबर 2009 में ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है. अपने फ़ैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को सहायक शिक्षकों के 34,540 पदों पर प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नियुक्त करने का आदेश दिया था और साथ ही छह सप्ताह के भीतर इसकी रिपोर्ट देने को कहा था. लेकिन, सुशासन का दंभ भरने वाली नीतीश सरकार को न तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की चिंता है और न ही उन प्रशिक्षित उम्मीदवारों की, जो बेरोज़गार हैं.

हालांकि 2003 से ही इस पूरे मामले में अदालती कार्रवाई चल रही है और नौकरी पाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की लड़ाई भी. दरअसल 2003 में राज्य सरकार ने शिक्षकों के 34,540 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था. यह विज्ञापन प्रशिक्षित और ग़ैर प्रशिक्षित दोनों तरह के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए था. पटना हाईकोर्ट ने विज्ञापन अधिसूचना रद्द कर दी और राज्य सरकार को प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का निर्देश दिया था. फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया. दिसंबर 2009 में इस मामले में न्यायालय ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए बिहार सरकार को 34,540 पदों पर प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया और साथ ही छह सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट सौंपने को कहा. सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने जनवरी 2006 में अदालत को प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का वचन दिया था, इसलिए वह उस वचन से बंधी हुई है. सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2003 के भर्ती विज्ञापन में दी गई 34,540 रिक्तियों की संख्या को ही सही माना. खंडपीठ ने राज्य सरकार को उसी संख्या के आधार पर प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती वरिष्ठता के क्रम में करने का निर्देश दिया, लेकिन छह सप्ताह बीतने के बाद भी बिहार सरकार न्यायालय के आदेश पर अब तक अमल नहीं कर सकी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बिहार सरकार ने तय समय सीमा के भीतर प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सरकारी वेतनमान पर नियुक्त नहीं किया है. इसके बाद नवनियुक्त शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं याचिकाकर्ता एन के ओझा ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दायर की और आदेश पर अमल कराने का अनुरोध किया. अवमानना के इस मामले पर अभी अंतिम फ़ैसला होना बाकी है, लेकिन राज्य सरकार अपने रवैये से शायद यही संदेश देना चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उसके लिए कोई मतलब नहीं है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

35 हज़ार बनाम 70 हज़ार

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही 35 हज़ार प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश राज्य सरकार को दिया है, लेकिन इस मामले में नीतीश सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई को देखते हुए यही लगता है कि हज़ारों प्रशिक्षित उम्मीदवारों का इंतजार अभी ख़त्म नहीं होने वाला. इसका सबूत है मानव संसाधन विकास विभाग की वह घोषणा, जिसमें एक खास वेतन पर 70 हज़ार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही गई है. जब दिसंबर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के अंदर 2003 के विज्ञापन के आधार पर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश दिया था, तब सरकार ने इसमें असमर्थता व्यक्त करते हुए अदालत से जून तक का समय मांगा.

इसके बाद मानव संसाधन विभाग ने शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी नियमावली एक शपथपत्र के साथ अदालत में जमा भी की. हालांकि इस पर अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं लिया है. इस बीच प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की बात बताकर मानव संसाधन विभाग ने दूसरे चरण के 70 हज़ार प्राथमिक शिक्षक उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त करने का फ़ैसला कर लिया है. मानव संसाधन विभाग के इस फ़ैसले पर नवनियुक्त शिक्षक संघ के अध्यक्ष एन के ओझा कहते हैं कि नीतीश सरकार का यह फ़ैसला सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अंगूठा दिखाने जैसा है. हम लोग इसे कोर्ट की अवमानना मान रहे हैं. इसलिए फिर से सरकार के ख़िलाफ़ कोर्ट में आए हैं. हम यह कोशिश करेंगे कि पूरी कैबिनेट को अवमानना के मामले में अदालत तक खींच कर लाएं. बहरहाल, अवमानना के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख का पता तो बाद में चलेगा, लेकिन नीतीश सरकार के सुशासन में प्रशिक्षित शिक्षकों का एक दशक से भी पुराना इंतजार ख़त्म होता नहीं दिख रहा है. इसके अलावा सरकार का यह फ़ैसला नीतिगत कम राजनीतिक ज़्यादा लग रहा है.

बिहार सरकार ने नियत वेतनमान पर 70 हज़ार शिक्षकों को नियुक्त करने का जो फ़ैसला लिया है, वह पूरी तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है. जाहिर है, बिहार में शिक्षक नियुक्ति का यह मामला अब वोट की राजनीति में बदलता दिख रहा है. ओझा इसे 35 हज़ार बनाम 70 हज़ार का मामला कहते हैं. उनके मुताबिक़, राज्य सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि अगर 70 हज़ार लोगों को नौकरी दी जाएगी तो इससे उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ज़्यादा फ़ायदा होगा, बजाय 35 हज़ार प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सरकारी वेतनमान पर नियुक्त करने के.

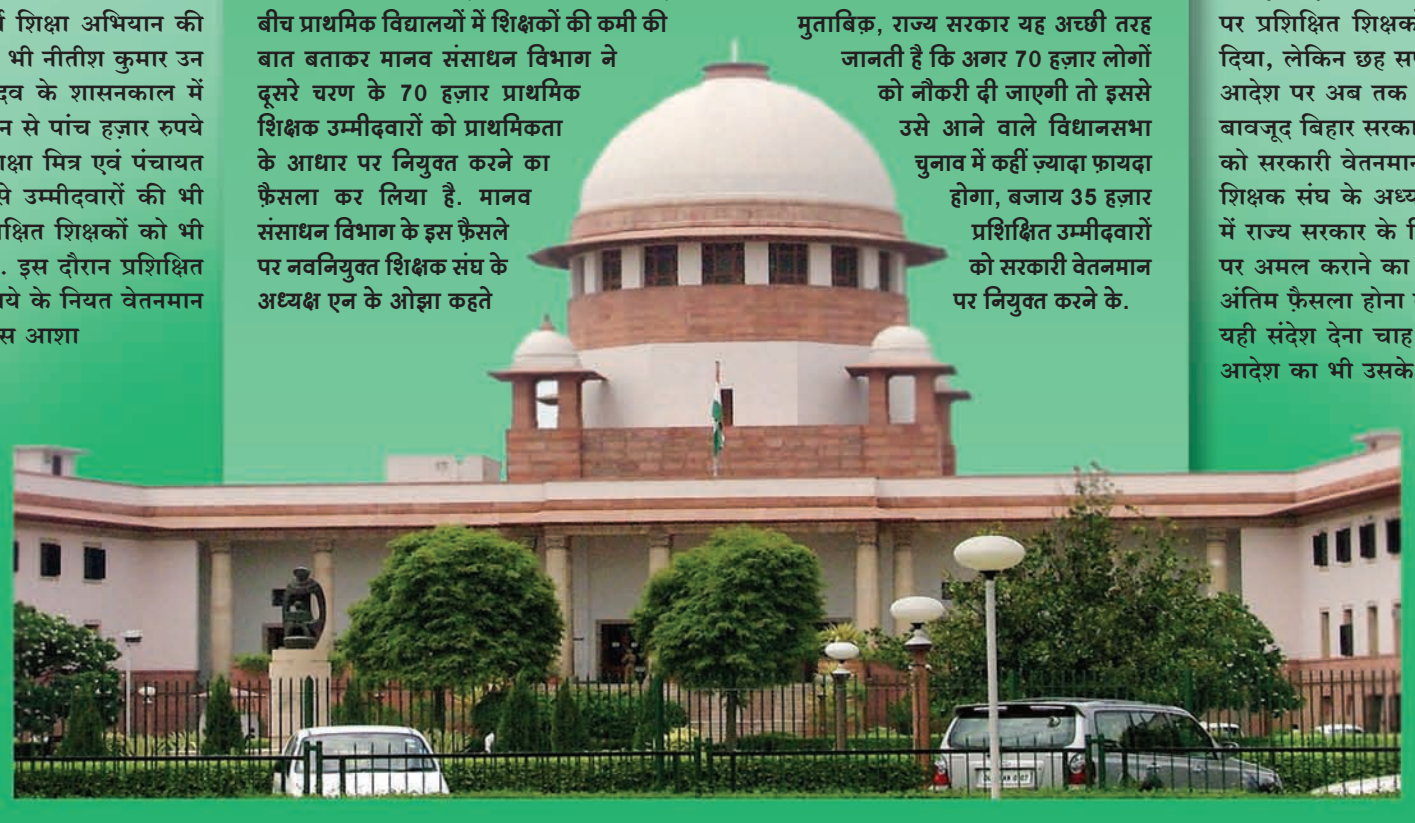

- दिसंबर 2009 में ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फ़ैसला.
- सरकारी वेतनमान पर नियुक्त करें प्रशिक्षित उम्मीदवारों को.
- छह सप्ताह में आदेश पर अमल करना था, लेकिन नहीं हुआ.
- अनुबंध पर 70 हज़ार शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा.
- अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका.
- महज़ पांच हज़ार रुपये पर काम कर रहे हैं प्रशिक्षित शिक्षक.

बिहार सरकार का यह फ़ैसला पूरी तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है. शिक्षक नियुक्ति का यह मामला अब वोट बैंक की राजनीति में बदल गया है. राज्य सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि अगर 70 हज़ार लोगों को नौकरी दी जाएगी तो इससे उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में ज़्यादा फ़ायदा होगा, बजाय 35 हज़ार प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सरकारी वेतनमान पर नियुक्त करने के.

-एन के ओझा, याचिकाकर्ता एवं अध्यक्ष, नवनियुक्त शिक्षक संघ, बिहार.

शेरघाटी में दहाड़ने लगे राजनीतिक शेर

विधानसभा चुनाव में कुछ महीने शेष रह गए हैं, लेकिन चुनावी बिसात पर मोहरे बिछने लगे हैं. गया ज़िले में नवगठित शेरघाटी विधानसभा सीट पर दिग्गजों ने दहाड़ना शुरू कर दिया है. शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र को बोधगया और गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया गया है, जिसमें डोभी, शेरघाटी और आमस प्रखंड को शामिल किया गया है. तीनों ओर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्रों इमामगंज, बाराचट्टी और बोधगया के बीच अनारक्षित इस विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों से आसानी से संपर्क किया जा सकता है. लिहाज़ा यहां से चुनाव लड़ने वालों की तादाद काफी है. राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-2 (ग्रांड ट्रंक रोड) से सटे होने के कारण उम्मीदवारों को मतदाताओं से संपर्क करने में काफी आसानी होगी. हालांकि यह विधानसभा क्षेत्र भी प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की जद में है. पिछले तीन साल में दर्ज़नों नक्सली घटनाएं इन तीनों प्रखंड में हो चुकी हैं, लेकिन परिसीमन के बाद शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के उदय होने पर राजग, कांग्रेस, भाजपा, जदयू, लोजपा के दिग्गजों का ध्यान इस विधानसभा क्षेत्र पर आ गया है. गुरुआ के राजद विधायक शकील अहमद खां भी शेरघाटी सीट पर अपना भविष्य तलाश रहे हैं. यही वज़ह है कि शेरघाटी शहर के हर छोटे-बड़े कार्यक्रमों में वह अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराना नहीं भूलते. वैसे राजद के एक दर्ज़न नेता यहां से अपनी दावेदारी जता रहे हैं. ज़िला परिषद के उपाध्यक्ष और डोभी निवासी कृष्णा यादव का कहना है कि डेढ़ दशकों से उन्होंने क्षेत्र की लोगों की सेवा की है और क्षेत्र को नज़दीक से देखा है. विधायक बनने के बाद वह शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम को बिहार का मॉडल बनाएंगे. इस तरह डोभी के ही एक राजद नेता भगत यादव भी चुनाव को लेकर गंभीर हैं और लालू यादव से नज़दीकी जता कर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं. जगदेव सेना के रविंद्र यादव भी यहां से राजद की उम्मीदवारी जता रहे हैं. भाजपा की मंजू अग्रवाल अपनी मज़बूत दावेदारी के साथ खड़ी हैं. वह शेरघाटी नगर पंचायत की वार्ड सदस्य, दुर्गावाहिनी की ज़िलाध्यक्ष और महिला धार्मिक न्यास बोर्ड की प्रदेश मंत्री के साथ कई ज़िम्मेदारी संभाल रही हैं. उन्होंने कहा कि मैं शेरघाटी के लोगों की सेवा कर रही हूं, जिसके चलते यहां की जनता ख़ुद मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है. उन्होंने कहा कि जनता ने यहां से मौक़ा दिया तो इसका बहुमुखी विकास होगा. इसके अलावा भाजपा के ही वार्ड सदस्य अजय कुमार सिंह, मुन्ना सिंह, चिंटू सिंह, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता भी भाजपा से अपनी दावेदारी जता रहे हैं. विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजद-लोजपा गठबंधन के तालमेल में यह सीट किसे मिलेगी कहना मुश्किल है, लेकिन राजद तथा लोजपा के नेता अपनी दावेदारी जता रहे हैं. लोजपा के ज़िलाध्यक्ष अताउल्लाह खां विधानसभा चुनाव में पार्टी से अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं. वह कहते हैं कि पिछले दो दशक से वह राजनीति कर रहे हैं. वह क्षेत्र के लोगों के हर दुःख-दर्द में शामिल होते रहे हैं. और हो न हो क्षेत्रीय होने का लाभ भी उन्हें मिलेगा. कांग्रेस के कई दिग्गज भी इस सीट पर नज़र गड़ाए बैठे हैं. प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तनवीर अख़्तर यहां से कांग्रेस के सशक्त प्रत्याशी बताए जाते हैं. फिलहाल वह स्टेट बैंक डायरेक्टर ऑफ बोर्ड के सदस्य हैं तथा कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय राजनीति में अल्पसंख्यकों की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण उनकी उम्मीदवारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. वह शेरघाटी के स्थानीय निवासी भी हैं. कांग्रेस के अन्य नेताओं में राणा सिद्दीकी अपनी उम्मीदवारी जताते हुए कहते हैं कि आज़ादी के बाद शेरघाटी को छला गया है. परिसीमन के बाद स्थानीय लोग जब यहां के विधायक होंगे तभी क्षेत्र का विकास होगा. उन्होंने ऐलान किया है कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे. प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अलेक्जेंडर खां, कलीम अंसारी, अजीत सिंह, शाहीद इमाम, उमेश सिंह और महमुद आलम भी कांग्रेस के दावेदार हैं. निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर समाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले वसिम अकरम भी चुनावी दंगल में अपनी क़िस्मत आजमाने को तैयार हैं. उनका कहना है कि मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं और लगातार उनकी सेवा कर रहा हूं. इससे बेहतर सेवा के लिए जनता को मुझे विधानसभा में पहुंचाना होगा. कुल मिलाकर आज़ादी के बाद पहली बार बने विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई अंतत: हिंदू-मुस्लिम कार्ड पर ही होगी. इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,93008 है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 91,630 तथा पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,1378 है. ऐसे में किसे किस दल से टिकट मिलता है कौन मतदाताओं को अपनी ओर प्रभावित कर पाता है यह तो समय बताएगा. फिलहाल शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में संभावित उम्मीदवारों की आवाजाही तेज़ हो गई है.

अताउल्लाह खां

महमूद आलम

मंजू अग्रवाल

राणा सिद्दीकी

शकील अहमद खां

तनवीर अख्तर

वसीम अकरम

विधानसभा क्षेत्र
शेरघाटी

सुधींद्र प्रसाद वर्मा
feedback@chauthiduniya.com

झारखंड में भाजपा की फजीहत

नवल किशोर सिंह

भाजपा की भयग्रंथि ही दरअसल झारखंड के वर्तमान राजनीतिक संकट का मूल कारण है, वरना इतना ढुलमुल रवैया इस पार्टी के अंदर पहले कभी नहीं देखा गया था. हेमंत सोरेन जैसे झामुमो के पहली बार विधायक बने नेता ने भाजपा को न सिर्फ़ प्रदेश बल्कि केंद्रीय नेतृत्व तक को लट्टू की तरह नचाकर बैकफुट पर ला दिया.

उसके सारे तेवर ढीले कर दिए. समर्थन वापसी का पत्र सौंपने के लिए राज्यपाल से तीन बार समय मांगने के बाद भी समर्थन वापस लेने का साहस भाजपा नहीं कर पाई, जिससे उसकी जगहंसाई ही हुई, उसके बाद हेमंत ने भाजपा नेताओं को नए-नए ऑफर देकर अपनी शर्तों को मानने के लिए तैयार कर लिया. हेमंत ने सबसे पहले शिबू सोरेन के कटौती प्रस्ताव में कांग्रेस का साथ देने को मानवीय भूल बताते हुए क्षमा मांगी, फिर शिबू सोरेन के इस्तीफ़े और भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की पेशकश की. साथ ही यह शर्त भी रख दी कि अगला सीएम आदिवासी ही हो.

उनके प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए भाजपा ने समर्थन वापसी के मामले को होल्ड करके रखा और भाजपा के भावी मुख्यमंत्री पर विचार विमर्श शुरू कर दिया. इसी बीच भाजपा नेतृत्व के नर्म रुख़ को देखते हुए हेमंत ने फिर पैंतरा बदला और शिबू सोरेन को छह माह पूरे होने यानी 29 जून तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का प्रस्ताव दे डाला. दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीज़े आने के बाद से ही भाजपा सुरक्षात्मक स्थिति में है. एक तो 29 सीट से खिसक कर 18 सीट पर सिमट आने के कारण उसका मनोबल गिरा, दूसरा भाजपा से बगावत कर अपनी ज़मीन तैयार करने वाले झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी पहली बार अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर 12 सीटों पर जीत का परचम लहराया. मरांडी संघ के संगठक रह चुके हैं और संगठन खड़ा करने की कला उन्हें आती है. झाविमो का गठन कर उन्होंने इसे सिद्ध भी कर दिया. भाजपा नेताओं को इस बात का भय था कि बाबूलाल सत्ता में आ गए तो वह इतने मज़बूत हो जाएंगे कि भाजपा को झारखंड में अपनी ज़मीन बचाए रखने में कठिनाई होगी.

इसीलिए उसने किसी भी क़ीमत पर मरांडी की सरकार बनने से रोकना अपना पहला लक्ष्य बनाया था. वह शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के गठन में सहयोग और समर्थन के लिए राज़ी हो गई. एक अनुशासित और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाली पार्टी होने के बावजूद झामुमो जैसी क्षेत्रीय और राजनैतिक सौदेबाज़ी के लिए चर्चित पार्टी की तमाम शर्तों को मान लेना ही भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक पराजय थी. संतोष सिर्फ़ यह था कि उसने कांग्रेस-झाविमो की सरकार नहीं बनने दी. शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद नक्सलियों के प्रति नर्म रुख़ अपनाए रहे. लोकसभा की सदस्यता बरक़रार रखी और विधायक बनने की औपचारिकता पूरी करने के प्रति उदासीन रहे. फिर भी भाजपा उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकी.

शिबू सोरेन ने कटौती प्रस्ताव में बिना किसी राय विचार के कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया तो पानी भाजपा के सिर के ऊपर से गुज़रने लगा. उसका मरा हुआ स्वाभिमान जागा और उसके संसदीय बोर्ड ने शिबू सरकार से समर्थन वापसी का निर्णय लिया, लेकिन इसके नतीज़े पर ग़ौर करने के बाद भाजपा डर गई कि कहीं झामुमो पाला बदलकर कांग्रेस के खेमे में न चला जाए और बाबूलाल के साथ उसका तालमेल न बन जाए. कांग्रेस से वार्ता कर हेमंत ने इसका संकेत भी दे दिया. इसी खौफ़ के कारण भाजपा समर्थन वापस लेने में संकोच करती रही, लेकिन जिस बात से वह डरती रही, अब उसका ख़तरा बढ़ता जा रहा है. बाबूलाल मरांडी ने धर्म निरपेक्ष दलों की नब्ज़ टटोलनी शुरू कर दी है और झारखंड को स्थायी सरकार देने की बात करने लगे हैं. झामुमो के आठ विधायकों का उन्हें समर्थन प्राप्त होने की बात सामने आ रही है. यदि ऐसा हुआ तो सरकार बनाने का दावा करने और बहुमत जुटाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी. आजसू को पाला बदलने में भी वक्त नहीं लगेगा. फिर भाजपा को जिस बात का भय था वही हो जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

संघ और भाजपा के रिश्तों में खटास

धनंजय मिश्र

पिछले साल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बीच दूरी बढ़ती जा रही है. इस दूरी ने अब संघ और भाजपा को आमने-सामने कर दिया है. वैसे तो इसके पीछे कई वज़ह है, लेकिन इसका मुख्य कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हर फ़ैसले पर भाजपा की चुप्पी नीति को माना जा रहा है.

दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय वरीय नेताओं की अति महत्वाकांक्षी विचारधारा को भी इस बढ़ती दूरी का कारण समझा जा रहा है. ज़ाहिर है, इसी महात्वाकांक्षी नीति का नतीज़ा है कि आरएसएस नेताओं की नज़दीकी अन्य दलों के नेताओं के साथ बढ़ती जा रही है. यह नज़दीकी हिंदुओं को सीवान में एकजुट करने के मक़सद से आरएसएस ने अपने चिंतन रणनीति के तहत आरंभ किया है. अगले विधानसभा के मद्देनज़र, अन्य वैचारिक शक्ति के अहसास ने अन्य दलों के नेताओं को ख़ासा प्रभावित किया. मसलन अन्य दलों के नेता संघ से अपना भावनात्मक लगाव बढ़ाने को आतुर होने लगे. इसके बाद रघुनाथपुर की जदयू विधायक जगमातो देवी की पहल पर पिछले साल संघ ने उनके गांव नंदामुड़ा में सात दिवसीय प्राथमिक शिक्षा वर्ग शिविर का आयोजन किया. ज़िले में हर वर्ष एक बार होने वाले इस प्राथमिक शिक्षा वर्ग में ज़िले के साठ नए शिक्षकों को मानसिक, शारीरिक, वैचारिक एवं बौद्धिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है.

दूसरा वाकया यह रहा कि पिछले महीने हुए श्रीराम जन्मोत्सव के मौक़े पर भाजपा से निष्कासित तत्कालीन नेता एवं सीवान के वर्तमान विधान पार्षद मनोज सिंह के द्वारा नगर के चौक-चौराहों पर कई भव्य स्वागत तोरणद्वार बनवाए गए. इन तोरणद्वारों पर मनोज सिंह के करबद्ध कई कटआउट्स भी लगाए गए, लेकिन इस पर भाजपा के किसी भी वरीय नेता का कटआउट नहीं लगा. इसी प्रकार इसके पहले भी संघ द्वारा पूरे देश में चलाए गए विश्व गौ ग्राम यात्रा के अवसर पर

जगमतो देवी

मनोज सिंह

ओ.पी. यादव

दलों के नेता भी आरएसएस को समय-समय पर सहयोग कर उससे अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं, जिससे भाजपा के वरीय नेता आरएसएस से अपनी नाराज़गी जताते हुए दूरियां बढ़ाते जा रहे हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी आजकल भाजपा से काफी नाराज़ चल रहे हैं. खासकर हाल के एक घटनाक्रम ने इस नाराज़गी को बढ़ने में अहम भूमिका निभाई है. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किशनगंज में खोलने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के विरोध में आंदोलन कर रहे अभाविप के कार्यकर्ताओं को जहां एक ओर पुलिस ने बर्बरता से पिटा, वहीं भाजपा की मूकदर्शक एवं मौन नीति से उसके सहयोगी संगठनों में आक्रोश और अविश्वास फैल गया. इससे भाजपा के वरीय नेताओं की बेचैनी भी बढ़ गई है. स्थानीय भाजपा मंत्री व नेता भी नीतीश कुमार की नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं. इसके बाद यहां भाजपा के कैडर वोट में बिखराव होने की आशंका भी बढ़ गई है. जानकारों का कहना है कि संघ से भाजपा की नाराज़गी पिछले उपचुनाव, ज़िला एवं नगर परिषद चुनाव और ज़िला को-ऑपरेटिव बैंक के चुनाव से ही शुरू हो गई थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई. एनडीए प्रत्याशी एवं मंत्री वृषिण पटेल को जब सीवान संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए जदयू से टिकट मिला तो स्थानीय जदयू नेता ओमप्रकाश यादव बागी रूख अपनाते हुए बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी समर में कूद गए. सीवान के चुनावी लहर में ओमप्रकाश यादव की ओर रुझान देखकर संघ को लगा कि सीवान में राजद के माय समीकरण को ध्वस्त करने का यह बेहतर मौक़ा है. लिहाज़ा आरएसएस के हज़ारों कार्यकर्ताओं ने ओमप्रकाश यादव के पक्ष में शहर से गांवों तक हिंदू जनमत को गोलबंद करने का प्रयास तेज़ कर दिया. नतीज़ा ब्राह्मण, वैश्य एवं यादव जाति का अधिकांश वोट ओमप्रकाश के पक्ष में पड़ा. इस तरह से ओमप्रकाश की जीत हुई. संघ की इस सीवान ज़िले में सांसद ओमप्रकाश यादव, विधान पार्षद मनोज सिंह और जदयू विधायक जगमातो देवी के कई कटआउट्स लगाए गए, परंतु भाजपा के किसी मंत्री या विधायक का एक भी कटआउट देखने को नहीं मिला.

भाजपा नेताओं की संघ से नाराज़गी की सबसे बड़ी घटना यह बताई जा रही है कि पिछले महीने सीवान के हकाम स्थित गांव में सांसद ओमप्रकाश यादव ने महावीरी शिशु मंदिर विद्यालय के कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन किया और अपने सांसद कोष से इस विद्यालय को 10 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा भी की. उद्घाटन समारोह में संघ के प्रमंडलीय विभाग प्रचारक लखी प्रसाद, संघ के वरीय कार्यकर्ता वाल्मीकि प्रसाद यादव आदि उपस्थित थे, लेकिन इसमें भाजपा का कोई भी स्थानीय पदाधिकारी, विधायक और मंत्री शामिल नहीं हुए. बता दें कि महावीरी शिशु मंदिर विद्यालय आरएसएस के द्वारा संचालित किया जाता है. ज़ाहिर है संघ के इस बदले रूख से भाजपा के नेता ख़ासे नाराज़ हैं, लेकिन भाजपा के स्थानीय दिग्गज नेताओं के कथित अहं से आहत संघ के पुराने कार्यकर्ताओं में से तीन कार्यकर्ता खुलकर अब भाजपा के स्थानीय दिग्गज नेताओं की आलोचना कर रहे हैं. इन तीन नेताओं में पहले गदाधर विद्रोही हैं, जो उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के पुराने दौर के सहयोगी रहे हैं, दूसरे वाल्मीकि प्रसाद यादव हैं, जो संघ और भाजपा के पुराने समर्थक हैं और तीसरे प्रमोद तिवारी हैं, जो स्वास्थ्य राज्यमंत्री व्यासदेव प्रसाद के सहयोगी रहे हैं. इन नेताओं का कहना है कि संघ और भाजपा की बढ़ती दूरी का मुख्य कारण भाजपा के स्थानीय वरीय नेताओं की मनमानीपूर्ण नीति है. इसी का नतीज़ा है कि सीवान में आजकल संघ और भाजपा आमने-सामने हो गए हैं. वहीं भाजपा को मालूम है कि संघ के ख़िलाफ़ मुखर होना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है. शायद इसी का नतीज़ा है कि भाजपा के वरीय नेता आरएसएस के कृत्य पर चुप्पी साधे बैठे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

परिसीमन ने बढ़ाई पटेल की परेशानी

राजेश सिन्हा

बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में इस बार अभी से विभिन्न पार्टी के नेताओं के बीच घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है. टिकट के लिए एक ही पार्टी से कई उम्मीदवार आलाकमान या अपने आका के दरबार में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. यहां तक कि कई दावेदार टिकट नहीं मिलने की स्थिति में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर चुनाव लड़ने का मन भी बनाने लगे हैं, जबकि सत्ता का सुख भोग चुके नेता अपने आका के साथ-साथ मतदाताओं को रिझाने में लग गए हैं. कई जगह ऐसे नेताओं को मतदाताओं की खरी-खोटी भी सुनने को मिल रही है. वैसे तो लगभग सभी पार्टी में टिकट के लिए होड़ मची है, लेकिन जदयू में घमासान की स्थिति सबसे अधिक है. हालात यह है कि पिछले चुनाव तक एक-दूसरे के साथ गलबहियां करने वाले नेता भी कुर्सी की चाहत में एक-दूसरे की लुटिया डूबोने को आतुर दिख रहे हैं. अन्य नेताओं की कौन कहे. चौथम (अब बेलदौर विधानसभा) के जदयू विधायक पन्नालाल सिंह पटेल के लिए पिछले चुनाव तक संकटमोचक की भूमिका अदा करने वाले चौथम प्रखंड के जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार इस बार उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में खड़े होने को बेताब हैं. सुनील इस बार पटेल के प्रति मतदाताओं की नाराज़गी को भुनाने में लग गए हैं.

काफी कुरेदे जाने के बाद भी उन्होंने पार्टी की उम्मीदवारी के संदर्भ में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा आलाकमान का आदेश सर आंखों पर. इधर कुछ स्थानीय मतदाताओं का कहना है कि अगर जदयू के द्वारा इस बार पन्नालाल सिंह पटेल को ही उम्मीदवार बनाया गया तो पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि विधायक पटेल अपने कार्यकाल में न ही जनता का विश्वास हासिल कर सके और न ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का. पिछले चुनाव में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसराहा की सभा में नीतीश कुमार ने विधायक पटेल की गलतियों के लिए जनता से माफ़ी मांगकर उन्हें वोट दिलाया था. बावजूद इसके वह लोजपा की सुनीता शर्मा को महज़ एक हज़ार कुछ मत से ही पराजित कर सके थे. इस स्थिति को भांपकर सुनील कुमार ने पार्टी से टिकट के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है. विधायक पटेल नए परिसीमन के आधार पर होने वाले चुनाव के कारण भी परेशान दिख रहे हैं. दरअसल उनके विधानसभा क्षेत्र का न केवल नाम ही बदल गया है, बल्कि नए परिसीमन के कारण उनके क्षेत्र का जातीय समीकरण भी गड़बड़ा गया है, लेकिन पटेल इस तरह की बातों से इत्तेफ़ाक नहीं रखते. उनका कहना है कि उनके द्वारा किए गए विकास कार्य के एवज में जनता उन्हें झोली भरकर वोट देगी. उनका कहना है कि पूरी पार्टी उनके साथ है. अन्य पार्टी की स्थिति पर अगर नज़र डाली जाए तो लोजपा की पूर्व विधायक सुनीता शर्मा लोजपा की प्रबल उम्मीदवार बताई तो जा रही हैं, लेकिन किशोर चौधरी शर्मा की राह का रोड़ा बनने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं. वैसे नागर जाति के मतदाता सहित अन्य जाति के मतदाताओं के बीच चौधरी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह कोई खास करिश्मा दिखा सकें. सुनीता शर्मा भी कहती हैं कि उन्हें जनता की सेवा का जब-जब मौक़ा मिला है, तब-तब उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई है. इसलिए जनता की आंखों में वह बसती हैं. अगर राजद-लोजपा गठबंधन से राजद की उम्मीदवारी पर सहमति बनती है तो चुकती घराने से कोई उम्मीदवार खम ठोक सकता है. इसके लिए अभी से ही चुनावी बिसात बिछाई जा रही है. कांग्रेस से फिलहाल ज़िला पार्षद इंद्रमोहन सिंह उर्फ़ चुन्नु बाबू तथा जयप्रकाश सिंह का नाम सामने आ रहा है. एक अन्य ज़िला पार्षद जयकृष्ण सिंह ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर चुनावी जोर-आजमाइश शुरू कर दी है. भरत यादव अपनी क्षेत्रीय पार्टी किसान विकास पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने से परहेज़ नहीं करेंगे. क्योंकि इससे पूर्व भी विधानसभा चुनाव में उन्हें अच्छा खासा मत मिला था. यह बात अलग है कि वह कभी भी जीत का स्वाद नहीं चख सके. सपा प्रत्याशी के रूप में धीरेन्द्र कुमार सिंह को टिकट का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है. राजपूत बिरादरी से ताल्लुकात रखने वाले सिंह समय-समय पर आम जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाकर तथा जन आंदोलन कर मतदाताओं के बीच गहरा साख बनाए हैं. बीते दिनों सपा के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारी भीड़ जमा कर उन्होंने पार्टी हाईकमान की नज़रें अपनी ओर खींचने में सफलता हासिल की है. अगर उन्हें पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया तो वह दिग्गजों का जायका तो बिगाड़ ही सकते हैं. सिंह का भी कहना है कि चौथम (अब बेलदौर) विधानसभा की जनता को जनप्रतिनिधियों ने इस कदर ठगा है कि उसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा.

वामपंथी पार्टी की स्थिति पर नज़र डाली जाए तो सीपीआई के पूर्व विधायक सत्यनाराण सिंह के नाम पर कार्ड खेला जा सकता है. बहरहाल, टिकट के मामले पर किस पार्टी से किसके सर होगा ताज और किसे टिकट के खेल में मिलेगी हार, यह दावे के साथ कहना शायद न्यायसंगत नहीं होगा. वहीं इतना तय है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बेलदौर विधानसभा (अब चौथम विधानसभा) की तस्वीर बदली-बदली नज़र आने वाली है. संभव है कि कोई नया चेहरा इस बार के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक समीकरण को ध्वस्त करते हुए जीत का ताज पहन ले.

विधानसभा क्षेत्र
बेलदौर

भरत यादव

धीरेंद्र कुमार सिंह

पन्ना लाल पटेल

सुनील कुमार

जयप्रकाश सिंह

> पिछले चुनाव में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसराहा की सभा में नीतीश कुमार ने विधायक पटेल की गलतियों के लिए जनता से माफ़ी मांगकर उन्हें वोट दिलाया था. बावजूद इसके वह लोजपा की सुनीता शर्मा को महज़ एक हज़ार कुछ मत से ही पराजित कर सके. इस स्थिति को भांपकर सुनील कुमार ने पार्टी से टिकट के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है.

feedback@chauthiduniya.com

हर किसी को जीत का भरोसा

मनोज कुमार राव

विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप वाला इलाक़ा केसरिया, वैसे तो हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर यहां राजनीतिक गहमागहमी परवान चढ़ रही है. इस क्षेत्र की गलियों, चौराहों, मुख्य सड़कों तथा गांव की पगडंडियों पर टिकट लेने वालों और दिलाने वालों की पंचायत जमने लगी है.

यहां से एक तरफ राजद के विधायक बबलू देव ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सुमित्रा यादव सहित दर्ज़नों नेताओं की टोली है, जो चुनावी अखाड़े में भाग्य आजमाने के लिए बेताब हैं.

विधायक राजेश रौशन उर्फ़ बबलू देव ने अपने को मतदाताओं का चहेता बताते हुए कहा कि इस बार भी जनता उन्हीं को चुनने का मन बना चुकी है. उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले बौद्ध स्तूप देखने आए देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए ठहरने की व्यवस्था करवाई, जिसमें क़रीब 50 लाख की लागत आई. उन्होंने यह भी बताया कि जो केसरिया महोत्सव पहले समाजिक सहायता से होता था, उसे 2007 से सरकारी महोत्सव का दर्ज़ा उन्होंने ही दिलवाया. लगभग 17 करोड़ 84 लाख की लागत से उन्होंने चकिया केसरिया सत्तर घाट सड़क का निर्माण करवाया, जिससे एनएच से सीधे स्तूप तक पहुंचना आसान हो गया. सत्तर घाट पुल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस पुल के लिए सरकार से आश्वासन मिल चुका है, कार्य जल्द प्रारंभ होगा. शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि केसरिया प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय एवं सिसवां पटना प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय के निर्माण कार्य की मंज़ूरी मिल चुकी है. सिर्फ़ टेंडर प्रक्रिया बाकी है. उन्होंने कहा कि केसरिया हाई स्कूल में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. पांच स्कूलों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है.

यह पूछे जाने पर कि चर्चा हो रही है कि नए विधानसभा क्षेत्र कल्याणपुर से उनकी उम्मीदवारी हो सकती है या नहीं, इस पर उन्होंने बताया कि फिलहाल मैं कल्याणपुर के 34 पंचायतों में से 22 पंचायतों का और केसरिया के 18 पंचायतों का विधायक हूं, इसीलिए मेरे कार्यक्षेत्र में ये दोनों क्षेत्र आते हैं और कल्याणपुर की जनता भी मेरे विकास कार्यों से भली-भांति वाक़िफ़ हैं. यही वज़ह है कि मुझे केसरिया और कल्याणपुर विधानसभा में से जिस विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलेगा, उस क्षेत्र से जीत हासिल करुंगा.

इधर प्रत्याशियों की सबसे बड़ी सूची कांग्रेस की ही है. सुमित्रा यादव, यतींद्र कश्यप, रविशंकर पांडेय, इरफानुल हक और ध्रुव सहनी के नाम की चर्चा ज़ोरों पर है. कांग्रेस ज़िलाध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ल ने बताया कि सभी नामों पर चर्चा चल रही है, योग्य उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा. इधर अपने कार्यों के लिए चर्चित सुमित्रा यादव ने बताया कि केसरिया में विकास कार्य ठप हो चुका है और जनता नया नेता चुनने का मन बना चुकी है और इस बार ज़मीनी स्तर का नेता ही विधायक बनेगा. उन्होंने बताया कि बतौर प्रखंड प्रमुख मैंने जिस तरीक़े से काम किया है, उससे यहां की जनता काफी ख़ुश हैं. अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं इन ग़रीबों की दिन रात सेवा करुंगी. उन्होंने यह भी कहा कि मैं और लोगों की तरह मतदाताओं से कोई वादा नहीं करती, बल्कि मेरा उनके प्रति एक कमिटमेंट है और मैं हर हाल में उसे पूरा करुंगी. उन्होंने कहा कि इतना मैं ज़रूर कहूंगी कि अगर कांग्रेस टिकट के लिए मेरा चुनाव करती है, तो उसे यहां से ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि यहां के मतदाता इस बार मुझे अपना मत ज़रूर देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने की प्रेरणा भी यहां के मतदाताओं ने ही दिया है और मौक़ा मिला तो मैं उनके सपनों को ज़रूर साकार करुंगी. इधर यतींद्र कश्यप ने भी कांग्रेस से टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि क्षेत्र की अधिकांश जनता मुझ में अपने भावी विधायक को देखती है और अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो यहां से उसे सफलता ज़रूर मिलेगी. उन्होंने कांग्रेस के वरीय नेताओं में अपनी आस्था जताते हुए बताया कि पार्टी का जो आदेश होगा, वो मान्य होगा. इधर राजद की ओर से रविंद्र प्रताप सिंह भी अपनी दावेदारी को लेकर काफी मशक़्क़त कर रहे हैं. प्रारंभ से ही सुर्ख़ियों में रहने वाले रविंद्र प्रताप ने बताया कि राजद की सीट यहां से खाली होने वाली है और इस बार उन्हें टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो उनकी जीत पक्की है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रारंभ से ही यह मेरा कार्यस्थल रहा है और जनता हमेशा से मेरे साथ है. इधर हरसिधी विधायक महेश्वर सिंह का इस बार केसरिया से चुनाव लड़ने की चर्चा ज़ोरों पर है और अगर लोजपा से उन्हें टिकट मिलता है, तो महेश्वर सिंह अन्य प्रत्याशियों के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं. इधर पूर्वी चंपारण ज़िला राष्ट्रीय जनता दल के संगठन सचिव प्रभाष प्रताप सिंह के नाम की चर्चा भी ज़ोरों पर है. 1997 में समता पार्टी के प्रदेश सचिव रहे और 1999 में मोतिहारी लोकसभा चुनाव के दौरान अजेय पार्टी से प्रत्याशी रहे प्रभाष प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर रहे एवं अजेय पार्टी को सूबे में सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त भी हुए.

विधानसभा क्षेत्र
केसरिया

बबलू देव

महेश्वर सिंह

प्रभाष प्रताप सिंह

रविन्द्र प्रताप

सुमित्रा यादव

यतेन्द्र कश्यप

युवा मतदाताओं का रुझान भी उनकी ओर अधिक दिख रहा है. फिलहाल आश्रय स्थल नामक संस्था के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण स्वच्छता अभियान से भी अपने आपको जोड़ रखा है. अपने चुनावी अनुभव के माध्यम से केसरिया विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के बीच इनकी भी चर्चा है. लोजपा से ही एक अन्य उम्मीदवार अभय सिंह के नाम की चर्चा ज़ोरों पर है. उनके समर्थकों ने बताया कि अगर उन्हें टिकट मिलता है, तो वह सीधी लड़ाई में रहेंगे और जीत भी मिलेगी. सीपीआई से रामशरण यादव खासे चर्चा में हैं. उधर जदयू की ओर से मज़बूत दावेदारी करते नज़र आ रहे हैं व्यवसायी अनिल सिंह. उनकी छवि भी प्रभावशाली है. अगर उन्हें जदयू की ओर से प्रत्याशी बनाया जाता है तो समीकरण बदलते देर नहीं लगेगा. इधर विधायक रह चुके मो. ओबैदुल्लाह या उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने की भी चर्चा है और अगर इन दोनों में से कोई मैदान में उतरता है, तो उनके पुराने राजनीतिक अनुभव का उन्हें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और इनका कद कई अन्य नेताओं के लिए सिरदर्द भी साबित हो सकता है. इधर नारायण यादव भी इस बार चुनाव लड़ने के लिए चर्चित हो रहे हैं और मतदाताओं के बीच अंदरुनी रूप से अपनी दावेदारी भी पेश करना प्रारंभ कर चुके हैं. बहरहाल टिकट के लिए नेताओं ने पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ शुरू कर दी है. अब किसका सितारा चमकेगा यह तो समय ही तय करेगा.

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 17 मई–23 मई 2010

गंगोत्री में भी उन्हें बिग बी का साथ मिला और उन्होंने अपने किरदार के दम पर गंगा से भी कहीं ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की.

कहीं देर न हो जाए...

भोजपुरी फ़िल्मों में बॉक्स ऑफिस के आधार पर किसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्म की चर्चा की जाती है तो उसमें यक़ीनन गंगा का ज़िक्र होता है. इस फ़िल्म में भोजपुरी फ़िल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी, रवि किशन से लेकर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने काम किया था. 2006 में बनी इस फ़िल्म में गंगा का केंद्रीय किरदार नगमा ने निभाया था. ज़ाहिर है इस फ़िल्म से नगमा को भी समीक्षकों और प्रशंसकों ने हाथोहाथ लिया था. एक साल बाद जब इस फिल्म का सीक्वल प्लान किया गया, तब गंगा के किरदार के लिए एक ऐसी अभिनेत्री की ज़रूरत पड़ी जो नगमा का बेहतर विकल्प बन सके. अंत में गंगा के सीक्वल गंगोत्री के लिए चुलबुली और गर्लनेक्सट डोर अभिनेत्री भूमिका चावला का चुनाव हुआ. भूमिका उस समय बिग बी के साथ हिंदी फ़िल्म फैमिली में भी काम कर रही थीं. गंगोत्री में भी उन्हें बिग बी का साथ मिला. इसे संयोग ही कहा जाएगा कि हिंदी और भोजपुरी दोनो ही फ़िल्मों में एक ही समय वह महानायक अमिताभ के साथ काम कर रही थीं. उन्होंने अपने किरदार के दम पर गंगा से भी कहीं ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की. इस फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद दर्शकों को लगा कि वह जल्द ही दूसरी भोजपुरी फ़िल्म में जलवे बिखेरती नज़र आएंगी, लेकिन भूमिका ने इसी दौरान शादी कर ली और भोजुपरी इंडस्ट्री से गायब सी हो गईं. कुछ लोगों को लगा कि शादी की वजह से वह फिल्मों को अलविदा कह रही हैं, पर ऐसा भी नहीं है. वह तेलगू फ़िल्मों में बराबर नज़र आ रही हैं. तो फिर ऐसी क्या बात हुई जो भूमिका अचानक से भोजपुरी फ़िल्मों से नदारद हो गईं. जब उनसे पूछा गया तो वही टालमटोल वाला जवाब मिला कि वह एक अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रही हैं. वजह चाहे जो भी हो पर इतना ज़रूर है कि उनको जो सफलता भोजपुरी सिनेमा में मिली है वह कहीं और नहीं मिलेगी. इसलिए बेहतर है कि वह गंगोत्री की सफलता को कायम रखें और दर्शकों को भोजपुरी स्क्रीन में नज़र आएं नहीं तो दर्शकों की याद्दाश्त से उतरते देर नहीं लगेगी.

feedback@chauthiduniya.com

बिहार के प्रति बेरुख़ी क्यों?

अनंत विजय

एक बार फिर बिहार के प्रति केंद्र सरकार की बेरुख़ी और भेदभावपूर्ण रवैया सामने आया है. सूबे में बेहतर काम कर रही नीतीश सरकार ने छब्बीस ज़िलों में सूखे की वजह से अपनी फ़सल गंवा बैठे किसानों को राहत देने के लिए चौदह हज़ार करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन बिहार के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित केंद्र ने यहां भी राजनीति की और सूखे की मार झेल रहे किसानों के राहत के लिए सिर्फ़ दो सौ उनहत्तर करोड़ रुपये देने का फ़ैसला किया. राहत राशि के नाम पर केंद्र सरकार का ये अनुदान ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, क्योंकि सूबे के छब्बीस ज़िलों में पिछले साल भयंकर सूखा पड़ा था और फ़सल चौपट होने से किसानों को काफी नुक़सान हुआ था, जिसकी भरपाई ज़रूरी है. नुक़सान और किसानों की बदतर हालत को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने किसानों को डीजल पर अनुदान दिया था, जिसकी केंद्र सरकार ने जमकर तारीफ की थी, लेकिन जब केंद्र के सामने मदद करने का प्रस्ताव आया तो यूपीए सरकार ने अपना असली रंग दिखा दिया और महज़ दो सौ उनहत्तर करोड़ रुपये देकर अपना पल्ला झाड़ लिया. वहीं दूसरी ओर सूखा राहत के नाम पर पंजाब सरकार को आठ सौ करोड़ रुपये और हरियाणा को चार सौ करोड़ रुपये देने का फरमान जारी हुआ है, जबकि पंजाब और हरियाणा में अपेक्षाकृत कम सूखा पड़ा था और वहां के किसान आर्थिक रूप से बिहार के किसानों से ज़्यादा संपन्न भी हैं.

इसके पहले भी कई बार केंद्र सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है. तेरहवें वित्त आयोग ने भी आपदाग्रस्त बिहार की आवश्यकताओं की ज़बरदस्त अनदेखी की. अगले पांच साल के लिए राज्य आपदा राहत कोष का आकार तक़रीबन अठारह हज़ार करोड़ रुपये निर्धारित किया, लेकिन जब बात बुंदेखखंड की आती है, तो केंद्र सरकार अपने ख़ज़ाने का मुंह खोल देती है. बुंदेलखंड को सवा सात हज़ार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के अलावा कृषि पैकेज के नाम पर बारह हज़ार करोड़ रुपये और दे दिया. बुंदेलखंड पर केंद्र की मेहरबानी इसलिए समझ में आती है कि वहां कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की विशेष रुचि है और उसे वह अपनी राजनीति की प्रयोगशाला भी समझते हैं. इसलिए केंद्र उस इलाक़े पर मेहरबान है.

दो साल पहले जब कोसी के कहर ने उत्तर बिहार में पांच सौ से ज़्यादा लोगों की जान ली थी और हज़ारों करोड़ की संपत्ति तबाह हो गई थी, हज़ारों गांवों के तक़रीबन पैंतीस लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ गए थे, उस वक्त भी केंद्र ने बिहार को पर्याप्त आर्थिक मदद नहीं की थी. बाढ़ की विभीषिका से जूझ रही बिहार की जनता से ज़्यादा फिक्र केंद्र को श्रीलंका के मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान जाफ़ना में मारे गए तमिलों की थी. दरअसल बिहार के प्रति केंद्र सरकार की बेरुख़ी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही जारी है. देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच मतभेद की वजह से बिहार को काफी नुक़सान उठाना पड़ा. डॉ राजेंद्र प्रसाद को रबर स्टांप बनना मंजूर नहीं था और वो नेहरू की नीतियों की खुलकर आलोचना करने से नहीं चूकते थे. यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि नेहरू के ना चाहने के बावजूद राजेंद्र बाबू लगातार दूसरी बार भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति बने. गांधी-नेहरू परिवार की बेरुख़ी बाद के दिनों में भी जारी रही और राजेंद्र बाबू के साथ-साथ बिहार को भी उसका वाज़िब हक नहीं मिला.

संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साज़िश रची गई और संविधान निर्माता के रूप में भीमराव आंबेडकर का नाम प्रचारित कर दिया गया, जबकि संविधान सभा की बहस के दस्तावेज को अगर देखें तो यह तथ्य साबित होता है कि भारतीय संविधान के असली आर्किटेक्ट राजेंद्र प्रसाद थे. कांग्रेस की राजेंद्र प्रसाद के प्रति बेरुख़ी का आलम यह रहा है कि अब तक संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा नहीं लगाई जा सकी है. राजेंद्र प्रसाद को साज़िशन संसद भवन से बाहर रखा गया है, जबकि कई ऐसे महानुभावों की प्रतिमाएं संसद भवन में लगाई गई हैं, जिनका देश के प्रति योगदान राजेंद्र प्रसाद से कम है.

बिहार के प्रति कांग्रेसियों की इस बेरुख़ी को सूबे की जनता पिछले छह दशक से झेल रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस के लोग अपनी मानसिकता को बदलें और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करना छोड़ दें.

feedback@chauthiduniya.com

गुलाबबाग मंडी

अतिक्रमणकारियों की चपेट में

नीरज कुमार सिंह

गुलाबबाग मंडी की स्थापना किसानों की आर्थिक दशा को मज़बूत करने के लिए की गई थी, लेकिन आज यह ख़ुद बदहाली और अतिक्रमणकारियों की चपेट में है. बाज़ार समिति का प्रांगण अनैतिक कार्यों का अड्डा बन गया है. अतिक्रमाणकारियों ने उसकी ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लिया है. अगर समय रहते संबंधित विभाग ने कार्रवाई नहीं की तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा. केंद्र व राज्य सरकार किसानों के हित के लिए चाहे कितने भी दावे करें. सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं. ग़ौरतलब है कि गुलाबबाग कृषि उत्पादन एवं विपणन बाज़ार समिति की स्थापना 1971 में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर की गई थी, जहां किसान अपने उत्पादों को आसानी से बेच सके और उत्पादों को अच्छी क़ीमत के लिए कुछ दिनों तक रखते थे. इससे सरकार को भी भारी भरकम राजस्व की आमदनी होती थी, इससे प्राप्त होने वाले राजस्व के कुछ हिस्से को बाज़ार प्रांगण के विकास कार्यों में लगाया जाता था, जिससे निरंतर बाज़ार का विकास हो रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने किसान हित की बात करते हुए बाज़ार समिति से राजस्व वसूली व अन्य नियंत्रण हटा लिए. लिहाज़ा राजस्व वसूली एवं अन्य नियंत्रण हटा लेने के कारण संपूर्ण बाज़ार प्रांगण की हालत जर्जर हो चुकी है. भवन क्या पक्की सड़क भी गड्ढे में तब्दील हो चुके हैं. जगह-जगह कूड़े-कचरे का अंबार लग है. पेयजल तो क्या सरकारी लाइट व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है, वैसे प्रांगण चोरी, जुआ व अन्य अनैतिक कार्यों का अड्डा बनते जा रहा है. वर्तमान में इस जगह पर अतिक्रमणकारियों ने अपनी दुकान स्थापित कर लिए हैं. साथ ही दुकानों के अंदर व बाहर अपने सुविधा अनुसार ग्रील, मार्बल, टाइल्स एवं आवासीय रूम बनाकर अवैध निर्माण करा लिए हैं. हालांकि

क़ानून के मुताबिक़ प्रांगण के अंदर, ईट, बालू, गिट्टी जैसे निर्माण सामग्री को ले जाना प्रतिबंधित है, लेकिन गार्ड को कुछ ले-दे कर इन सामग्रियों को आसानी से ले जाया जा सकता है. एक व्यवसायी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अतिक्रमण का आलम यह है कि दुकान किसी और के नाम से आवंटित है, जबकि व्यवसाय कोई दूसरा कर रहा है. वहीं एक कारोबारी ने बताया कि एक व्यवसायी ने मुख्य सड़क से लगे अपने मकान को बाज़ार प्रांगण की तरफ वाली चाहरदीवारी को तोड़कर गेट और ग्रील लगा लिया है, ताकि इस रास्ते से होकर माल को बाज़ार के अंदर व बाहर आसानी से ले जाया जा सके. एक व्यवसायी ने बताया कि पूर्व में 35 दुकानों के आवंटन में बाज़ार समिति के कर्मियों ने धांधली किया गया था. इस संबंध में जब सदर अनुमंडल पदाधिकारी व पदेन सचिव कृषि उत्पादन बाज़ार समिति गुलाबबाग, नीरज खेरवाल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पदाधिकारियों की कमी के कारण वर्तमान में अतिक्रमणकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में देरी हो रही है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दोषी चाहे जो भी हो उन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

> भवन क्या पक्की सड़क भी गड्ढे में तब्दील हो चुके हैं. जगह-जगह कूड़े-कचरे का अंबार लग है. पेयजल तो क्या सरकारी लाइट व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है, वैसे प्रांगण चोरी, जुआ व अन्य अनैतिक कार्यों का अड्डा बनते जा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

ISO 9001:2000 Certified

World Standard Quality Now Available in India

Italian International Paints

Long Life for Paints & Walls

ITALIAN Wall Putty

* Made from DPMC
* Marvelous White
* Super Smoothness
* 100% Damp proof
* 100% Crack proof
* World Class Packing

World Standard

ITALIAN

Decorative Premium

WHITE CEMENT

welcome

ITALIAN International Paints.

Plot No.8, 2nd Floor, Nitin Palace, CHANDKHEDA, Near-O.N.G.C.IRS, Ahmedabad,Pin-382424(Gujarat)

Slight Costly but Superior

Fax No.079-23972402 / 033-25224090

चौथी दुनिया

दिल्ली, 17 मई–23 मई 2010

www.chauthiduniya.com

महेश्वर नर्मदा जल परियोजना

केंद्र और राज्य आमने-सामने

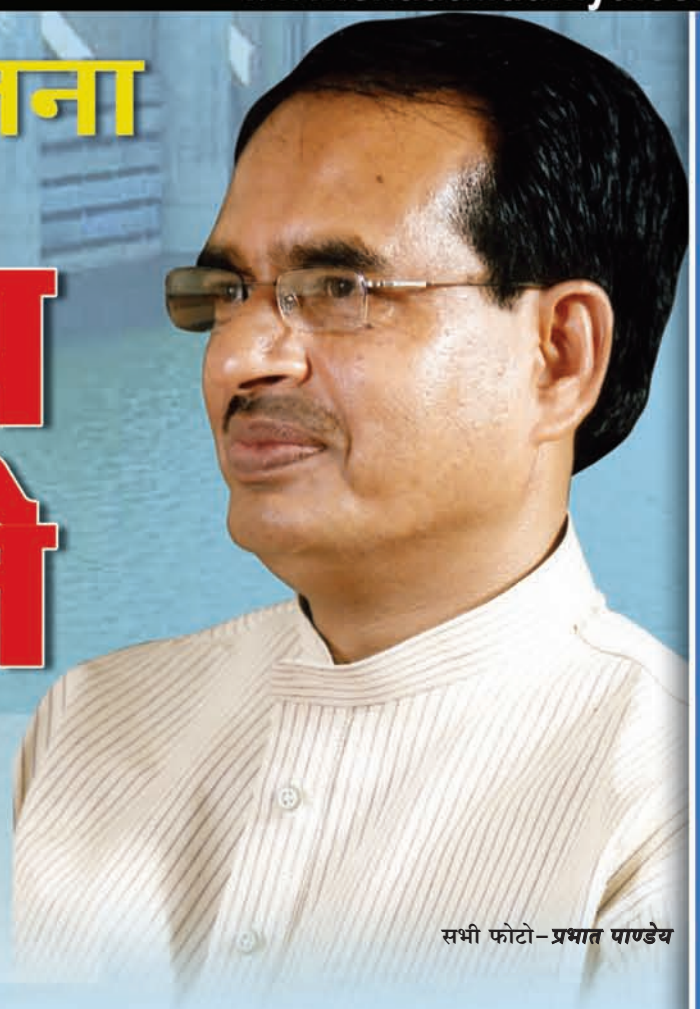

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से नाराज़ हैं. वजह, केंद्र सरकार ने विस्थापित लोगों का समुचित पुनर्वास न होने के कारण परियोजना विशेष पर रोक लगा दी है. राज्य और केंद्र के बीच चल रही यह तनातनी इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

विनय दीक्षित

महेश्वर नर्मदा जल परियोजना को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार में तनातनी चल रही है. प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर इस पर आगे काम बंद करने के निर्देश दिए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भड़क उठे. उन्होंने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश के विकास के प्रति अनुदार और संवेदनहीन बताया. लेकिन, सच्चाई मुख्यमंत्री को भी मालूम है. नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं को सरकारी तंत्र की तुलना में इस क्षेत्र की समस्याओं की कहीं ज़्यादा अच्छी समझ है. वे इन समस्याओं के समाधान के व्यवहारिक तरीक़े भी जानते हैं, लेकिन भाजपा सरकार से उनके संबंध अच्छे नहीं हैं. इसीलिए सरकार उनकी सुनना नहीं चाहती है. आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को तो मुख्यमंत्री एवं भाजपा के बड़े नेता प्रदेश और विकास विरोधी ठहरा चुके हैं, इसीलिए अब सरकारी अफ़सर उनकी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन जनता को राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. उसे तो अपनी समस्याओं से मतलब होता है.

मध्य प्रदेश में बिजली और पानी का संकट है, इसीलिए राज्य सरकार अपने जल संसाधनों का भरपूर उपयोग करना चाहती है. वह नदी जल का उपयोग सिंचाई और बिजली दोनों के लिए करना चाहती है. फिर नर्मदा जल के उपयोग का भी सवाल है. नर्मदा प्राधिकरण के पंचाट के अनुसार, मध्य प्रदेश अभी तक अपने हिस्से के जल का उपयोग नहीं कर पाया है. सरकार की सुस्ती एवं लापरवाही के चलते अगले दस सालों में भी मध्य प्रदेश अपने हिस्से के नर्मदा जल का उपयोग नहीं कर पाएगा. ऐसे में गुजरात और महाराष्ट्र को नर्मदा के पानी के उपयोग का अधिकार मिल जाएगा. गुजरात ने तो प्राधिकरण के फ़ैसले के दिन से ही नर्मदा जल के अधिकतम उपयोग के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और अब वह नर्मदा का पानी कच्छ के मरुस्थल तक ले जाने की स्थिति में आ गया है. फिर भी मध्य प्रदेश की ओर से नर्मदा जल के उपयोग के लिए अच्छी शुरुआत हो रही है, लेकिन जल्दबाज़ी में जो कुछ हो रहा है, उससे सरकार अपने लिए नई-नई समस्याएं पैदा कर रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर बताया है कि नर्मदा की महेश्वर परियोजना से प्रतिदिन 7.2 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी, जबकि राज्य की औसत ख़पत 1,000 लाख यूनिट प्रतिदिन है. इससे स्पष्ट है कि महेश्वर से राज्य की बिजली ख़पत का एक प्रतिशत से भी कम अंश प्राप्त होगा. फिर भी इसे अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी बताया जा रहा है. बिजली उत्पादन के लिए राज्य सरकार ने महेश्वर परियोजना से विस्थापित होने वाले 61 गांवों के 70 हज़ार से अधिक परिवारों के पुनर्वास कार्यों को पूरा कराने पर विशेष ध्यान नहीं दिया. यही कारण है कि परियोजना से विस्थापित होने वाले ग्रामीण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए राजनेताओं और राजनीतिक दलों पर कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं. वे नर्मदा बचाओ आंदोलन के झंडे तले अपनी आवाज़ उठा रहे हैं.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चालाकी का परिचय देते हुए सरकार के लिए समर्थन जुटाने का भी प्रयास किया. उन्होंने कहा कि महेश्वर परियोजना से इंदौर शहर को प्रतिदिन 300 मिलियन लीटर पानी मिल सकेगा और 2024 तक की पानी की ज़रूरत इससे पूरी हो सकेगी, लेकिन विस्थापितों के पुनर्वास के बारे में मुख्यमंत्री खुलकर कुछ नहीं बोलते. या यूं कहें कि बोलने से बचना चाहते हैं. नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता आलोक अग्रवाल एवं चितरूपा पालित ने एक नया गले उतरने लायक तर्क छोड़ा है कि मुख्यमंत्री परियोजना के निर्माण कार्य में लगे पूंजीपति ठेकेदारों के हितों की ज़्यादा चिंता कर रहे हैं. इसीलिए वह नर्मदा आंदोलन और यहां तक कि अपनी मर्यादा भूलकर देश के प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ भी नासमझी भरे बयान खुलकर दे रहे हैं. आलोक एवं चितरूपा ने राज्य सरकार पर आम जनता की अपेक्षा निजी परियोजनकर्ता के हितों की चिंता किए जाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि परियोजनकर्ता को 400 करोड़ रुपये की गारंटी इस शर्त पर दी गई थी कि उसकी होल्डिंग कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम से लिए गए पैसे वापस करने होंगे. जबकि गारंटी मिलने के बाद कंपनी द्वारा दिए गए 55 करोड़ रुपये के 20 चेक बाउंस हो गए. निगम द्वारा कंपनी के ख़िलाफ़ 20 आपराधिक प्रकरण भी कायम किए गए. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कंपनी से न तो जनता का पैसा वापस लिया गया और न ही आज तक गारंटी रद्द की गई. चितरूपा पालित ने कहा कि परियोजनकर्ता ने विद्युत मंडल एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 130 करोड़ रुपये की संपत्तियों का पैसा पिछले 14 सालों में आज तक सरकार को नहीं दिया. परियोजनकर्ता के अनुसार, उक्त संपत्तियां अब उनके नाम पर हो गई हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जवाब दे कि बिना पैसा लिए उक्त संपत्तियां परियोजनकर्ता के नाम कैसे हो गईं? उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय के आदेश का पालन करते हुए प्रभावितों का संपूर्ण पुनर्वास किए जाने, परियोजनकर्ता को दी गई गारंटी रद्द करने, विद्युत मंडल एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की संपत्तियों का पैसा परियोजनकर्ता से वसूलने और विद्युत क्रय समझौता रद्द करने की मांग की है.

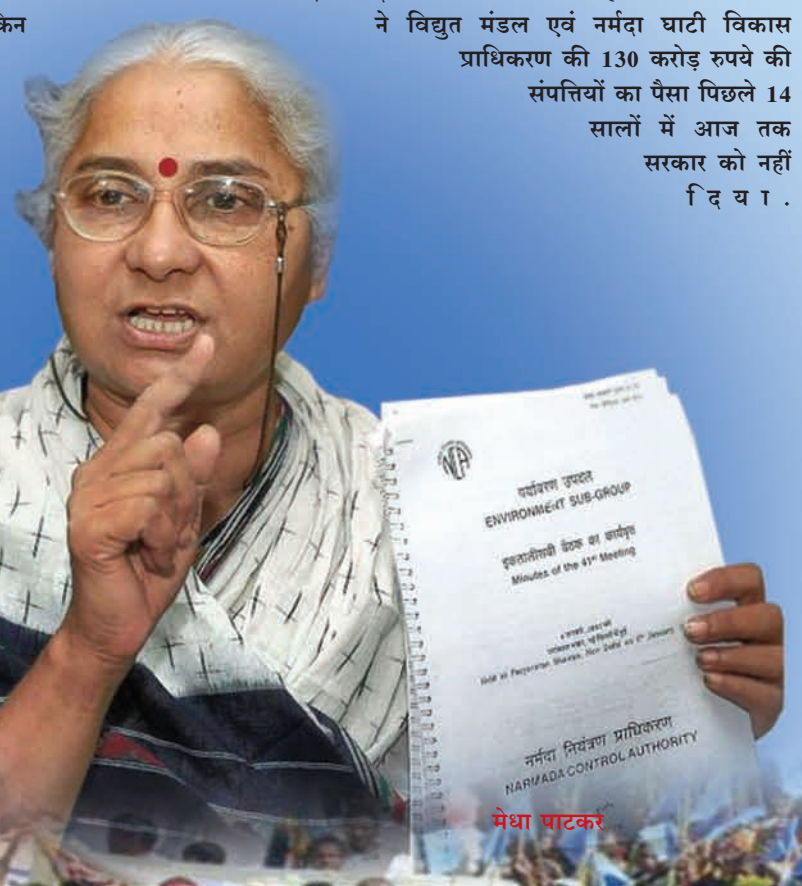

मेधा पाटकर

प्रदेश को अंधेरे में धकेलने का आरोप

मध्य प्रदेश की महेश्वर, पेंच परियोजनाओं और कोयले के ब्लाक के दोहन पर रोक लगाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने केंद्र सरकार पर और विकास विरोधी होने के आरोप लगाए हैं तथा इसे प्रदेश को अंधेरे में धकेलने की साज़िश बताया. उनका कहना है कि कहा कि महेश्वर परियोजना के निर्माण कार्य पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं है. इस बारे में वह पहले ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री को पत्र लिख चुके हैं. अब लगता है कि वन मंत्रालय कांग्रेस पार्टी और नर्मदा बचाओ आंदोलन के दबाव में काम कर रहा है. यदि महेश्वर परियोजना पर काम होता रहता तो जून 2010 में जल विद्युत परियोजना की पहली इकाई शुरू हो सकती थी, लेकिन रोक लग जाने से प्रदेश में 400 मेगावाट बिजली की कमी होगी और इसके लिए केंद्र सरकार ही ज़िम्मेदार होगी. उन्होंने कहा कि पेंच की दो ताप विद्युत इकाइयों को पानी देने से रोका गया है, इससे भी बिजली उत्पादन में कमी आएगी.

कांग्रेस प्रवक्ता अरविंद मालवीय ने मुख्यमंत्री की इन दलीलों को व्यर्थ बताते हुए कहा कि महेश्वर परियोजना का काम वैसे भी धीमी गति से चल रहा है. फिर पुनर्वास कार्य में तो सरकार ने कोई सक्रियता दिखाई नहीं, जबकि परियोजना की शर्त यही थी कि निर्माण कार्य के साथ-साथ विस्थापितों के पुनर्वास का काम भी पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक केवल एक गांव में पुनर्वास पैकेज लागू हो पाया है. पांच गांवों में पैकेज मान लेने के बाद भी पुनर्वास कार्य शुरू नहीं हुए. यदि मुख्यमंत्री की बात मान ली जाए तो बिना पुनर्वास के यदि जून में महेश्वर की पहली इकाई चालू होती है, तो आगामी बरसात में परियोजना के डूब क्षेत्र में 50 से ज़्यादा गांव बिना पुनर्वास के ही डूब जाएंगे, इसकी चिंता मुख्यमंत्री को नहीं है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी का कहना है कि

(शेष पृष्ठ 18 पर)

पेयजल में फ्लोराइड जैसे घातक पदार्थों के घुल जाने से लोगों में विकलांगता बढ़ती जा रही है.

भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के निर्देशों को ताख पर रखते हुए राजधानी से क़रीब 100 किमी दूर पत्थरों की अवैध खुदाई ज़ोरों पर चल रही है.

सार -संक्षेप

सुंदरी, ब्लैकमेलिंग और अफ़सरशाह

प्रदेश के नौकरशाह तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार में तो लिप्त हैं ही, पर अफ़सरों का एक वर्ग सुरासुंदरी के मोह में भी फंसा हुआ है. एक मामला हाल ही में उजागर हुआ है. [illegible]

एक वर्ष में 7 हज़ार से ज़्यादा मौतें

[illegible]

मुख्यमंत्री सड़क पर और अफ़सर एसी में

[illegible]

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

केन्द्र और राज्य आमने-सामने

पृष्ठ एक का शेष

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को यह भरोसा दिलाया था कि महेश्वर परियोजना से प्रभावित अंतिम व्यक्ति का पुनर्वास होने तक बांध में पानी का भराव नहीं किया जाएगा, लेकिन शायद वह अपनी बात भूल गए. [illegible]

करोड़ों रुपये ख़र्च, लेकिन तालाबों में पानी नहीं

[illegible]

हथाईखेड़ा डैम में अवैध खेती

[illegible]

feedback@chauthiduniya.com

पुरवा नहर
21 साल में 30 कोस

पुष्पेंद मौर्या

जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार के साथ-साथ लेट लतीफी के कारण तमाम जनहित की सरकारी परियोजनाओं का काम इतनी धीमी गति से होता है कि राज्य को उनका समय पर लाभ नहीं मिल पाता है. परियोजनाओं के निर्माण में देरी से निर्माण लागत भी कई गुना बढ़ जाती है. विंध्य क्षेत्र की सोन नदी पर बन रही बाणसागर परियोजना की लागत सात गुना बढ़ी है, लेकिन अभी भी बाणसागर बांध का लाभ इस क्षेत्र को मिल सके, इसके लिए नहरों का जाल बिछाने का काम सुस्त रफ्तार से चल रहा है. इस कारण सूखे से प्रभावित इस क्षेत्र में सोन नदी के पानी का लाभ नहीं मिल पा रहा है. फिलहाल बाणसागर बांध का पानी उद्योगों और बिजली परियोजनाओं के ही काम आ रहा है.

सतना ज़िले की पुरवा नहर, बाणसागर परियोजना का ही हिस्सा है. पिछले 21 वर्षों में इस नहर का काम केवल 30 कोस तक ही पूरा हो सका है और अभी भी 129 किलोमीटर लंबी इस नहर को पूरा करने में और कितने वर्ष लग जाएंगे, यह बताना मुश्किल है.

पुरवा नहर के निर्माण के लिए अब तक 30 करोड़ रुपया ख़र्च होना बताया गया है, लेकिन अब अधिकारियों का कहना है कि बाकी निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 20 करोड़ रुपया और चाहिए. फ़िलहाल इतना रुपया मिलने वाला नहीं है इसलिए पुरवा नहर का भविष्य अभी संकट में है. रीवा के सहेजा गांव से गुज़रते हुए पुरवा नहर का पानी मौजूदा समय में सतना ज़िले के बेलहटा के पास मरौहा गांव तक पहुंच चुका है. फ़िलहाल अभी पुरवा नहर का पानी सतना शहर में भी प्रवेश नहीं कर पाया है. पुरवा नहर के पानी का इंतज़ार इन दिनों ज़िले के सैकड़ों गांव के ग्रामीण कर रहे हैं. पुरवा नगर का पानी बेलहटा से सतना शहर होते हुए कोटर का मार्ग से ज़िले के अंतिम छोर तक भेजा जाएगा, एक ओर जहां पुरवा नहर ज़िले के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है वहीं दूसरी ओर इसके निर्माण कार्य से कई ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है.

सोनोरा ग्राम के पास क्रासिंग होने के चलते बाणसागर प्रबंधन द्वारा प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के तहत बनी सड़क को खुदवाकर वहां से नहर निकाली गई है, लेकिन जहां पर ग्रामीणों का रास्ता है, वहां पर दो पाइप लाइन लगा दी गई हैं, लेकिन तीसरी पाइप लाइन न लगाने की वजह से रास्ता पूरी तरह जाम हो गया है, जिसके चलते हिरनिया, बेलहटा, जराय, चकदही, लखहा, बरहा, मौहार, अमरइहा सहित कई गांव के ग्रामीणों का रास्ता प्रभावित है. बाणसागर प्रबंधन की दलीलों के मुताबिक़ पुरवा नहर का निर्माण कार्य पूरा न होने का मुख्य कारण बजट का समय पर न आना है. बाणसागर के अधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष पुरवा नहर के नाम पर 2 से 3 करोड़ रुपये मिलते हैं, जिस पर लगभग छह माह तक कार्य कराया जाता है और बाकी के दिनों निर्माण कार्य बंद रहता है.

देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. मोरारजी देसाई की यह परिकल्पना थी कि वर्ष 2008 तक बाणसागर की पुरवा नहर रीवा से गुज़रते हुए सतना के अधिकतर गांवों में पहुंच जाए ताकि इसका फ़ायदा ज़िले के लाखों किसानों को मिल सके. लेकिन अब तक उक्त योजना का कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिसके चलते अब भी पूर्व प्रधानमंत्री का सपना आधा-अधूरा है. सूत्र बताते हैं कि पहले पुरवा नहर के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2008 था, लेकिन विभाग में बजट की कमी के चलते लक्ष्य को बढ़ाकर वर्ष 2011 कर दिया गया है. बाणसागर परियोजना के अंतर्गत अपर पुरवा नगर का निर्माण कार्य 12 अगस्त 1989 से शुरू हुआ था और अब तक जारी है. पुरवा नहर के माध्यम से पिछले वर्ष कुल 4798 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का कार्य किया गया, इसके अलावा यदि यदि बात पुरवा नहर के सिंचाई क्षेत्र की जाए तो इस आधार पर कुल 59267 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का क्षेत्र उपलब्ध बताया जा रहा है. वहीं पुरवा नहर के जल प्रवाह की धारा के बारे में विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुरवा नहर की धार 4220 किमी प्रति घंटा है. पुरवा नहर में जगह-जगह पुलिया निर्माण के कार्य अधूरे होने के चलते सिंचाई के सीजन में किसानों की सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह तहस-नहस हो जाती है. पुरवा नहर का पानी गर्मी के मौसम में छोड़ा तो ज़रूर जाता है, लेकिन इसका सही उपयोग ज़िले के किसान नहीं कर पाते. ऐसी विकट स्थिति में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुरवा नहर केवल दिखावे तक ही सीमित रह गई है.

जल संसाधन मंत्रालय भोपाल से स्वीकृत बज़ट पर स्थानीय बाणसागर प्रबंधन पुरवा नहर का निर्माण कार्य निजी एजेंसियों के माध्यम से कराता है, जिसमें एजेंसी ठेकेदार द्वारा पैसा बचाने के चक्कर में निर्माण कार्य की गुणवत्ता को पूरी तरह नज़र अंदाज़ कर देते हैं. इस पूरे खेल में बाणसागर प्रबंधन के इंजीनियर व अधिकारियों की मिलीभगत होती है, जिसका नतीजा यह देखने को मिल रहा है कि नहर का कार्य पूर्ण होने के पहले ही जगह-जगह पुलियां दम तोड़ती नज़र आ रही हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई

feedback@chauthiduniya.com

फ्लोराइड का ज़हर
बच्चों में विकलांगता

प्रदेश में भीषण जल संकट तो है ही, साथ ही कई स्थानों पर प्रदूषणग्रस्त पेयजल में फ्लोराइड जैसे घातक पदार्थों के घुल जाने से जीवन जल, विकलांगता का कारण बन रहा है. ऐसा नहीं कि सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी होते हुए भी संवेदनहीन सरकारी अमला अकर्मण्य बन बैठे हैं.

केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कमलनाथ के संसदीय चुनाव क्षेत्र छिंदवाड़ा ज़िले में जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाकोड़ी में सरकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने पांच साल पहले गांव वालों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई हैंडपंप लगवाए थे, लेकिन इनसे फ्लोराइड युक्त पानी निकलने लगा. तब भी सरकारी अफ़सरों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया.

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सूत्र बताते हैं कि नियम है कि धरती से जब पानी निकाला जाता है, तब उसकी जांच की जाती है और देखा जाता है कि पानी पीने योग्य है या नहीं. वहीं शायद ग्राम बाकोड़ी में हैंडपंप से निकले पानी की किसी ने जांच नहीं की और भोलेभाले ग़रीब अनपढ़ लोग सरकार पर भरोसा करके सरकारी हैंडपंप का पानी पीते रहे. अब दो वर्ष बाद गांव वालों को सरकारी हैंडपंप से निकलने वाले पानी के दुष्प्रभाव का पता चला, क्योंकि गांव में कई बच्चे और किशोर विकलांगता के शिकार हो चुके थे. दो वर्षों से लगातार इस पानी का उपयोग करने वालों के शरीर पर पानी का घातक प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है. बच्चों के दांत ख़राब हो गए हैं और कई शारीरिक रूप से विकलांग हो गए. इन बच्चों के शरीर में एक तरह की ख़तरनाक बीमारी फैल गई, जिसकी वज़ह से गांव में आधे से अधिक बच्चों के हाथ-पैर में सूजन और टेढ़ापन आ गया है.

> ग्राम बाकोड़ी में हैंडपंप से निकले पानी की किसी ने जांच नहीं की और भोलेभाले ग़रीब अनपढ़ लोग सरकार पर भरोसा करके सरकारी हैंडपंप का पानी पीते रहे. अब दो वर्ष बाद गांव वालों को सरकारी हैंडपंप से निकलने वाले पानी के दुष्प्रभाव का पता चला.

2 वर्ष बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने आनन-फानन में वहां के हैंडपंप को बंद करवा दिया. ग्रामीण सुकटो ने बताया कि बच्चे जन्म के समय स्वस्थ थे, मगर फ्लोराईड युक्त पानी के उपयोग से इन बच्चों में यह बीमारी उत्पन्न होने लगी है. कुछ समय पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में शिविर लगाया गया था. केवल खानापूर्ति के लिए कुछ दवाईयां बच्चों को दी गई. बच्चों को इलाज के लिए ज़िला चिकित्सालय में भी बुलाया गया, लेकिन रास्ता सही न होने की वज़ह से शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के पालक, ज़िला चिकित्सालय नहीं पहुंच सके. बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 65 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं.

संध्या पाण्डे
feedback@chauthiduniya.com

7000 से ज़्यादा स्थानों पर पानी दूषित

मध्य प्रदेश में कुल सात हज़ार से ज़्यादा बस्तियों में पानी पीने योग्य नहीं है. कहीं पेयजल में फ्लोराइड है, तो कहीं नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा, तो कहीं-कहीं पानी ज़रूरत से ज़्यादा खारा है. कई ज़िलों में पेयजल स्त्रोतों में लौह तत्व और सीसा (लेड) भी घुलमिल गया है. इस कारण पानी पीने योग्य नहीं बचा है. सरकारी सूत्रों के अनुसार राज्य में कुल 1 लाख 27 हज़ार बस्तियों में से 26 ज़िलों की सात हज़ार 64 बसाहटों के 11569 जल स्त्रोतों में फ्लोराइट की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है. ऐसे घातक जल स्त्रोत मंडला, डिंडौरी, झाबुआ, शिवपुरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, उज्जैन, भिंड, मंदसौर और नीमच में हैं. इन ज़िलों में जल स्त्रोतों में फ्लोराइड 5.56 प्रतिशत तक घुलमिल गया है. जबकि 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक फ्लोराइड शरीर के लिए घातक होता है. राज्य में 391 बस्तियों के 663 जलस्त्रोतों में नाइट्रेट ज़्यादा है. नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने की वज़ह से भूमिगत चट्टानों, खेतों में रासायनिक उर्वरकों के बहाव और प्रदूषण आदि हैं. इससे बच्चों में कमज़ोरी और ख़ून में नीलेपन की बीमारी होती है.

राज्य में कई स्थानों पर जल स्त्रोतों में सीसा (लेड) भी घातक मात्रा में है. इसके अलावा लौह तत्व भी सिवनी, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, नीमच, छिंदवाड़ा, बालाघाट, उमरिया और सिवनी में 747 जल स्त्रोतों में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में पाया गया है. राज्य के लगभग 600 गांव में भूमिगत जल स्त्रोतों में खारेपन की मात्रा ज़्यादा है. बताया जाता है कि केंद्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत दूषित और घातक प्रभावित जलस्त्रोतों को बंद कर पानी के लिए वैकल्पिक प्रबंध करने हेतु भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को लगभग 100 करोड़ रुपयों की सहायता दी है, लेकिन पता नहीं राज्य सरकार ने इस धनराशि का कहां और किस प्रकार उपयोग किया है.

45 हज़ार हैंडपंप सूख चुके हैं

गरमी के मौसम में पेयजल संकट फिर गरमाने लगा है. इस बीच प्रदेश के 10 फीसदी हैंडपंप सूखे पड़े हैं. प्रदेश में कुल 4,37,884 हैंडपंप हैं, इसमें से पीएचई और अन्य विभागों के चालू हैंडपंपों की संख्या 4,15,590 है. इसमें से 22,294 हैंडपंप ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं. जल स्तर कम होने के कारण 13,093 हैंडपंप बंद हैं, 8,132 हैंडपंप ऐसे हैं, जिन्हें सुधारना अब संभव नहीं है. गुणवत्ता के कारण बंद कर दिए गए हैंडपंपों की संख्या 1,069 है.

सांस्कृतिक धरोहरों पर हमला

मध्य प्रदेश में भू-माफिया और खदान माफिया स्वार्थवश भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहरों को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण विदिशा ज़िले में देखने को मिला है. अब पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित कई शैलचित्र भू-माफियाओं की अवैध खुदाई के चलते नष्ट हो रहे हैं. विदिशा ज़िला प्राचीन भारतीय संस्कृति के वैभवशाली युग का साक्षी रहा है. महाभारत काल में यह क्षेत्र दशाण राज्य का अंग रहा है. दशाण राज्य के नरेश के यहां महारथी शिखंडी का विवाह हुआ था. मौर्य काल में यह क्षेत्र काफी समृद्ध व्यापारिक केंद्र रहा. सम्राट अशोक का विवाह विदिशा में ही एक व्यापारी की पुत्री देवी से हुआ था. अशोक निर्मित सांची का स्तूप विदिशा के निकट ही है, लेकिन इससे भी प्राचीन आदिम सभ्यता के शैलचित्र और गुफाचित्र विदिशा ज़िले में यत्र-तत्र उपलब्ध है. कुरवई तहसील के ग्राम पठारी के पास कई अदभुत प्राचीन शैलचित्र हैं. अब पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित इन शैलचित्रों का अस्तित्व संकट में आ गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में वैध-अवैध खुदाई, भूमि पर क़ब्ज़े और खनिज व्यापार की गतिविधियां तेज़ी से चल रही हैं और भू-माफिया तथा खनिज माफिया अपने लाभ के लिए शैलचित्रों के रूप में प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करने में लगा हुआ है. इस बारे में पुरातत्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को अभी तक कोई जानकारी नहीं होना, आश्चर्य की बात है.

आयुक्त मनोज श्रीवास्तव

भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के निर्देशों को ताखे पर रखते हुए राजधानी से क़रीब 100 किमी दूर पत्थरों की अवैध खुदाई ज़ोरों पर चल रही है. इससे न सिर्फ़ सैकड़ों साल पुराने शैलचित्रों को नष्ट किया जा रहा हैं, बल्कि हर महीने करोड़ों रुपये की राजस्व हानि भी हो रही है.

पत्थरों की खदान का एक बड़ा क्षेत्र माने जाने वाले विदिशा ज़िले के ग्राम पठारी में कई पत्थरों की खदानें ऐसी हैं, जिनकी सीमा ख़त्म हो चुकी है. अपनी सीमा को लांघते हुए अब खदान मालिकों ने पहाड़ में कटाई कराना शुरू कर दिया है. कुछ समय पहले पुरातत्व विभाग द्वारा तार फैसिंग कर यहां की जगह को संरक्षित कर दिया गया था, पर पुरातत्व द्वारा संरक्षित क्षेत्र में भी खुलेआम खुदाई जारी है और प्रशासन मौन है. जिस जगह पत्थर कटाई का काम चल रहा है, उससे क़रीब 150 फीट की दूरी पर आदिवासी छात्रावास भी बना हुआ है. पत्थर निकालने के लिए खदानों में 90 नंबर ईडी बारुद से ब्लास्ट किया जाता है. ब्लास्ट के समय पत्थर 500 फीट दूर तक भी बिखर जाता है, इससे हमेशा छात्रों की जान को ख़तरा बना रहता है. वहीं खदान से 15-20 फीट की दूरी पर लाखों साल पुराने शैलचित्र भी हैं. खुदाई से पहले कई सैलानी इन्हें देखने के लिए जाया करते थे, पर अब खुदाई के बाद यहां का रास्ता भी काफी ख़राब हो गया है. सूत्र बताते हैं कि खदान मालिकों ने यहां पेट्रोल डालकर इन शैलचित्रों को नष्ट करने की कोशिश भी की थी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बच्चों के क़ब्रिस्तान पर भी क़ब्ज़ा

खनिज माफियाओं ने धार्मिक और मानवीय मूल्यों को दरकिनार करते हुए क़ब्रिस्तान की ज़मीन पर भी क़ब्ज़ा कर लिया है. इस क्षेत्र में मृत बच्चों का यह आरक्षित क़ब्रिस्तान है, लेकिन इसके आसपास खदानों में कटाई और ब्लास्ट के मलवे से क़ब्रिस्तान पूरी तरह ढक चुका है और बर्बाद हो गया है. माफिया की नज़र क़ब्रिस्तान की ज़मीन पर है. स्थानीय निवासियों ने इस बारे में शासन से कई बार शिकायत भी की है, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है.

अब प्रशासन चेता है

हाल ही भोपाल संभाग के आयुक्त मनोज श्रीवास्तव को विदिशा के कुछ प्रबुद्ध नागरिकों और पत्रकारों ने जब इस बारे में जानकारी दी तो उन्होंने तुरंत इसे गंभीर मामला मानते हुए आश्वासन दिया कि वे विदिशा के कलेक्टर को इस मामले की जांच का निर्देश देंगे. आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि खनन कार्यों में नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और विशेषकर पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित शैलचित्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए. यदि खनिज ठेकेदारों द्वारा शैलचित्रों को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो खनन कार्य रुकवा दिया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी. पुरातत्व विभाग के प्रमुख अधिकारी मनोज गोविल ने कहा कि इस बारे में पुख़्ता शिकायतें आने पर वे अवश्य जांच कराएंगे.

सार -संक्षेप

महामृत्युंजय द्वार के निर्माण कार्यों की जांच

प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रशासन में सुधार और सफ़ाई करने में पूरी तरह विफल रही है. अब तो सरकार के मंत्रियों ने साफ़ सुथरे प्रशासन की आस भी छोड़ दी है. हिंदू संस्कृति और भगवा एजेंडे में भरोसा करने वाली भाजपा सरकार को झांसा देने के लिए सरकारी तंत्र तरह-तरह के उपाय करता रहता है. उज्जैन में महामृत्युंजय द्वार बनाने की एक ऐसी ही योजना है, लेकिन इसमें भी घपले घोटाले हुए और निर्माण लागत वास्तविकता से कहीं ज़्यादा बताई गई है. राज्य के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह पिछले दिनों उज्जैन में एक सरकारी बैठक में भाग लेने गए. उन्हें उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित महामृत्युंजय द्वार की लागत एक करोड़ 15 लाख रुपये बताई गई. द्वार की वास्तविक स्थिति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी भारी लागत के बाद भी द्वार की हालत ऐसी है. मंत्रीजी ने फौरन निर्माण कार्य की जांच करने के आदेश दे दिए. कुछ वर्ष पूर्व उज्जैन कुंभ मेले की तैयारी के लिए किए गए निर्माण कार्यों में भारी घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले चर्चा में आए. कुछ मामलों में शिकायत भी हुई और जांच भी हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ. उज्जैन की पवित्र क्षिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और नदी में जल प्रवाह बढ़ाने के उपायों पर अब तक करोड़ों रुपया ख़र्च हो चुका है, लेकिन सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार के कारण यह पैसा बर्बाद ही हुआ, क्योंकि गर्मी के दिनों में यह नदी सूख जाती है और कहीं-कहीं ही नदी में पानी जमा रहता है. पुराणों में यह वर्णन है कि समुद्र मंथन के बाद जब गरूड़जी अमृतकलश लेकर आकाश में उड़े थे, तब मार्ग में कुछ बूंदे क्षिप्रा नदी में छलक गई थी. इसलिए पुराणों में इस नदी को परमपवित्र और सतत प्रवाही नदी कहा गया है, लेकिन भाजपा सरकार के कार्यकाल में अमृत की बूंदों वाली क्षिप्रा नदी का स्वरूप देखकर आम आदमी को भी आश्चर्य होता है.

अफ़सरों की मिलीभगत से जंगल कटते हैं

सरकार राज्य में वनक्षेत्र वृद्धि का दावा करती है और केंद्र सरकार ने भी इस दावे को सही मान लिया है. इतना ही नहीं भारत सरकार ने 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में वनों के संरक्षण के लिए लगभग पांच अरब रुपये देने की घोषणा की गई है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि राज्य में समृद्ध वन क्षेत्रों में क़ीमती वृक्षों की कटाई, वन विभाग के अफसरों और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के संरक्षण में हो रही है. वृक्षों की इस अवैध कटाई से करोड़ों रुपयों का अवैध कारोबार भी हो रहा है. सीहोर ज़िले की बुधनी तहसील, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चुनाव क्षेत्र और गृहक्षेत्र है. वन संपदा से भरपूर इस क्षेत्र में वनों की अवैध कटाई धड़ल्ले से जारी है और वन विभाग का अमला इस अवैध कटाई में पूरी तरह से वनमाफिया का सहयोगी और भागीदार बना हुआ है. इस इलाक़े में मिडघाट चौका और भीमकोटि के आसपास के सघन वनों से सागौन काट कर ट्रेनों के रास्ते होशंगाबाद में बेचा जा रहा है. जीआरपी ने एक मालगाड़ी से सागौन के 38 नग बरामद किए हैं.जीआरपी को एक मुख़बिर से सूचना मिली थी कि मालगाड़ी के एक खाली डिब्बे में अवैध सागौन लाया जा रहा है. बुदनी में गाड़ी को रोककर डिब्बा खोला गया तो उसमें 38 नग सागौन पाई गई. जीआरपी उपनिरीक्षक रमेश के नेतृत्व में हवलदार एमएस ख़ान, आरक्षक तहसीलदार सिंह तथा विनोद यादव ने लकड़ी ज़ब्त कर ली है. आरोपियों की तलाश जारी है. बुदनी वन परिक्षेत्र में सागौन की अवैध कटाई धड़ल्ले से जारी है. लकड़ी चोर दिन में कुल्हाड़ी चलाते हैं, सागौन के कटे पेड़ों को काट छांटकर उन्हें टोल का आकार देते हैं. रात में घने जंगलों से ढोकर पटरी के पास रखते हैं और मालगाड़ी में लादकर होशंगाबाद तक पहुंचाते हैं. गाड़ी जैसे ही पुल पार करती है, लकड़ी पटरी किनारे गिरा दी जाती है और गाड़ी के गुज़रने के बाद वन माफिया उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं. मालगाड़ी के अलावा सागौन चार पहिया वाहनों में भी ढोया जा रहा है. वनों की सुरक्षा के लिए यहां भारी भरकम अमला तैनात है, लेकिन वन माफिया से सांठगांठ के चलते जानबूझकर इसे अनदेखा कर दिया जाता है. आला अधिकारियों तक शिकायत पहुंचने पर दिखाने के लिए कभी-कभार कार्रवाई कर दी जाती है. होशंगाबाद ज़िले की सोहागपुर तहसील में भी वनमाफिया सक्रिय होकर सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच सागौन और दूसरे कीमती वृक्षों की जमकर अवैध कटाई करवा रहे हैं, लेकिन वहां भी वन विभाग तमाशा ही देखता रहता है.

मुख्यमंत्री की घोषणा से ही आंदोलन उपजते हैं

प्रदेश में कर्मचारियों के सभी आंदोलनों के प्रणेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं. कर्मचारियों की मांगों के प्रति उदार मुख्यमंत्री जब तब बिना सोचे समझे उनकी मांगे मानने की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन जब सरकारी अफ़सर उन्हें समझाते हैं तो वह मांगें पूरी करना भूल जाते हैं. इसी कारण राज्य में जब तब कर्मचारी आंदोलन होते रहते हैं. हाल ही में राज्य के स्वास्थ्यकर्मियों ने आंदोलन करने की धमकी दी है. इनका कहना है कि 6 जून 2008 को मुख्यमंत्री ने बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम बदलकर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक करने और उनकी सेवाशर्तों में सुधार करने की जो घोषणा की थी, वह आज तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए कर्मचारी इस माह चरणबद्ध आंदोलन करेंगे. राज्य के 50 ज़िलों में लगभग 12 हज़ार स्वास्थ्यकर्मी इस माह अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए चरणबद्ध अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे. इन कर्मचारियों की 25 सूत्रीय मांगें हैं. इन मांगों को मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक रूप में मंजूर कर लिया था, लेकिन वे मांगें आज तक पूरी नहीं हो सकीं. इसी तरह राज्य में गुरूजी संवर्ग के शिक्षकों ने भी हड़ताल और आंदोलन की धमकी दी है. उनका कहना है कि जब राज्य सरकार शिक्षकों की कमी से जूझ रही है और नई भर्ती करना चाहती है, तब वर्षों से मामूली वेतन पर काम कर रहे गुरूजी संवर्ग के शिक्षाकर्मियों को नियमित शिक्षक के रूप में काम करने का मौक़ा देना चाहिए. पिछले वर्ष मुख्यमंत्री ने वायदा किया था कि वे नियमित शिक्षकों की भर्ती के समय गुरूजी संवर्ग के शिक्षाकर्मियों को प्राथमिकता देने का नियम बनाएंगे, लेकिन आज तक नियम नहीं बनाया गया है. इसी तरह अनुदान प्राप्त ग़ैरसरकारी कॉलेजों के शिक्षकों का मामला भी सर्वोच्च न्यायालय में वर्षों से अनसुलझा पड़ा है, जबकि राज्य सरकार ने न्यायालय में उचित समझौता फॉर्मूला पेश करने का वायदा किया था. आज तक सरकार की ओर से समझौता का यह फार्मूला तैयार नहीं हुआ है. पूरे राज्य के महाविद्यालयों में शिक्षकों के 1500 से ज़्यादा पद रिक्त हैं और अनुदान प्राप्त कॉलेजों में लगभग 500 शिक्षक हैं. यदि इन शिक्षकों का सरकारी कॉलेजों में संविलयन हो जाता है तो राज्य सरकार को बिना कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ के 500 शिक्षकों की सेवाएं मिल सकती हैं और इसके लिए इन शिक्षकों के संगठनों ने भी मंजूरी दे दी है. इस मामले में भी मुख्यमंत्री ने कुछ वायदे किए थे, लेकिन अफ़सरशाही पर उनकी पकड़ न होने के कारण उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी अभी फॉर्मूला बनाने के नाम पर सर्वोच्च न्यायालय से पेशी पर पेशी की मांग करते रहते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 17 मई–23 मई 2010

मुख्यमंत्री ने ठेला चालकों की श्रमिक पंचायत आयोजित कर सभी ठेला चालकों को मालिक बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन्हें बैंको से ऋण और अनुदान देने की घोषणा भी की थी.

घुघुवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान

अतीत की निधियों का ख़ज़ाना

संध्या पाण्डे

क्या आपने करोड़ों वर्ष पुराने बीज, शंख, पत्तियां, बीज वाले केले और वृक्षों के तनों को देखा है? या फिर जीवोत्पत्ति घड़ी देखी है? अधिकांश का जवाब शायद नहीं होगा. पर यह सवाल भी उठेगा कि ऐसा कैसे संभव है और अगर ऐसा है तो कहां और कैसे देखें? इन सब जिज्ञासाओं का समाधान मध्य प्रदेश में ही विद्यमान है. यह अनूठी वस्तुएं प्रदेश के डिंडौरी ज़िले में घुघुवा स्थित जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में देखी जा सकती है. अधिक जानकारी के लिए यह भी है कि घुघुवा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के किनारे डिण्डौरी ज़िले में शाहपुर से 14 किलोमीटर और जबलपुर संभागीय मुख्यालय से 76किलोमीटर दूर है. घुघुवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान अतीत की निधियों का ख़जाना है. ऐसा ख़जाना जहां ढेर सारे अति प्राचीन जीवाश्म मिले हैं और जो लगभग साढ़े छह करोड़ साल पुरानी है. इस भूभाग में मिली इस अमूल्य संपदा के संरक्षण और जीवाश्मों के अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सन 1983 में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की थी जो आज घुघुवा और उमरिया गांवों के 27.24 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है. आमतौर पर जब भी कोई जीव या पौधा मरता है, उसे बहुत जल्द दूसरे जीव–जंतु खा जाते हैं या वह सड़कर मिट्टी में तब्दील हो जाता है. लेकिन कुछ अवसरों में मृत जीवों के अवशेषों की सड़न की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देता, तब उस जीव या पौधे के पार्थिव अवशेषों में खनिज कण धीरे–धीरे प्रवेश कर जाते हैं और वे जीवाश्म में बदल जाते हैं. सामान्यत: पौधे अथवा जंतु के शरीर के किसी अंग का जीवाश्म बनता है, लेकिन कभी–कभी उसके द्वारा छोड़े गए चिह्नों का भी जीवाश्म बन जाता है, जैसे उसके पैरों के निशान, घोंसले, मल और पत्तियों की छाप.

जीवाश्म इस बात का प्रमाण है कि आज से करोड़ों वर्ष पहले भी इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जीवन का अस्तित्व था. पृथ्वी के जीवन काल में सुदूर भूतकाल में क्या–क्या घटनाएं, कब और कैसे घटी थीं, इसके बारे में भी जीवाश्म महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं. जीवाश्मों की आयु का निर्धारण रेडियोमिति विधि से किया जाता है. जीवाश्म कई प्रकार होते हैं– मसलन प्रतिस्थापन जीवाश्म, पत्थरीकृत जीवाश्म, मुद्राश्म, रोल में दबे जीवाश्म, अनुरेख जीवाश्म और संपीड़न जीवाश्म.

घुघुवा ग्राम में अब तक 18 पादप कुलों के 31 परिवारों के पौधों के जीवाश्म खोजे जा चुके हैं. ये सभी जीवाश्म आज से क़रीब साढ़े छह करोड़ वर्ष पहले इस क्षेत्र में अवस्थित पेड़–पौधों का प्रतिनिधित्व करते हैं. यहां काष्ठीय पौधों, लता–बेलों, पत्तों, फूलों, फलों और बीजों के बहुत अच्छी तरह संरक्षित जीवाश्म मिले हैं. यहां ताड़ प्रजाति और द्विबीज पत्री पौधों के जीवाश्म विशेष रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं. यह प्राचीन काल भारत के वानस्पतिक इतिहास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय अधिकांश आधुनिक पौधों ने अपना अंतिम रूप ग्रहण किया. इन जीवाश्मों की खोज का पहला श्रेय तत्कालीन मंडला ज़िले के (आज का डिण्डौरी ज़िला, तब मंडला ज़िले का ही हिस्सा था) तत्कालीन सांख्यिकी अधिकारी और ज़िला पुरातत्व संघ के पदेन सचिव डॉ. धर्मेंद्र प्रसाद को जाता है. इसके बाद जबलपुर के विज्ञान कॉलेज के डॉ. एसआर इंग्ले और लखनऊ के बहुप्रतिष्ठित बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान के डॉ. एमबी बांडे ने इन दुर्लभ जीवाश्मों का विधिवत अध्ययन किया.

उल्लेखनीय और आश्चर्यजनक यह है कि घुघुवा में पाए गए जीवाश्मों मे बदल गए पादपों के कुछ जीवित रिश्तेदार आज भी मौजूद हैं. इनमें से कुछ पश्चिमी घाट, सिक्किम और उत्तर–पूर्वी भारत में उगते हैं, तो कुछ अफ्रीका, मेडागास्कर और आस्ट्रेलिया में. यहां सफेदा वृक्ष (यूकेलिप्टस) के जीवाश्म मिले हैं. यह वृक्ष आज भी आस्ट्रेलिया में मिलता है और वहीं का माना जाता है. घुघुवा में प्राप्त जीवाश्मों में बदल चुके अन्य पौधों में प्रमुख रूप से खजूर, केला, रूद्राक्ष, जामुन और आंवला शामिल हैं.

वनस्पति विज्ञान के अनुसार इनमें से अधिकांश पौधे नमी–पसंद हैं. इससे यह पता चलता है कि साढ़े छह करोड़ साल पहले घुघुवा आज से कहीं अधिक नम क्षेत्र था. उस काल में यहां अत्यधिक बारिश हुआ करती थी. औसत वर्षा दो हज़ार मिलीमीटर या उससे अधिक थी. उन दिनों घुघुवा की जलवायु उमस भरी थी. साल भर एक समान तापमान बना रहता था. घुघुवा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में मटका, देवरीखुर्द, पलासुंदर, तिलठर घाटी पहाड़ियां और छारगांव में शल्कधारी जीवों के भी कुछ जीवाश्म मिले हैं, जो यह बताते हैं कि यहां पहले कोई बहुत बड़ा जल–स्त्रोत रहा होगा. यहां मिले पौधे उत्तर क्रिटशस युग और पुराजीवी कल्प के हैं. निम्न क्रिटेशस युग के अंतिम चरण में खुले बीजों वाले पौधे (जैसे टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स) जो काफी समय से पृथ्वी पर छाए हुए थे, धीरे–धीरे समाप्त होने लगे और उनका स्थान ले लिया पुष्पी पौधों ने. इस कारण से जब प्राचीन समय के जीवाश्म यहां मिल रहे हैं, यह काफी महत्व–पूर्ण है, क्योंकि आजकल के अधिकांश आधुनिक वनों का जन्म इसी सुदीर्घ अतीत में हुआ था.

जिस भूभाग में डिंडौरी स्थित है, वह लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व पश्चिमी घाट और उत्तर–पूर्वी भारत में आज जिस प्रकार के सदाहरित और अर्ध–सदाहरित वन है, उसी प्रकार के वनों से आच्छादित था. इससे साबित होता है कि प्राचीन काल में भारत, आस्ट्रेलिया और अफ्रीका सब एक विशाल भूखंड के अंग थे और उन सबमें एक ही प्रकार की वनस्पति का फैलाव था.

पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और कोटि–कोटि जीवधारियों में उसका पल्लवन 4.5 अरब वर्षों के सुदीर्घ काल में हुआ है. यदि किसी परिचित पैमाने से उसे न जोड़ा गया, तो इतने बड़े कालखंड की कल्पना करना लगभग असंभव हो जाएगी. घुघुवा प्राचीन उद्यान के व्याख्या केंद्र में प्रदर्शित जीवोत्पत्ति घड़ी में इस बड़े कालखंड को 24 घंटे की अवधि में संकुचित करके दर्शाया गया है. मनुष्य की उत्पत्ति दो लाख वर्ष पहले हुआ था, जो इस घड़ी के अनुसार मात्र दो मिनट पूर्व की घटना है. यद्यपि मनुष्य जाति के दो मिनट के अस्तित्व को इतना महत्व नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अपनी जाति के प्रति थोड़ा पक्षपात करते हुए इस घड़ी के प्रादर्श की ऊपरी पट्टी में मानव इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ावों को भी दर्शाया गया है.

अंत में यही कि घुघुवा उद्यान के भ्रमण के दौरान यहां स्थित व्याख्या केंद्र में अवश्य जाना चाहिए. इस केंद्र उद्यान में मिले जीवाश्मों के संबंध में विस्तृत जानकारी आकर्षक ढंग से दी गई है. इस कि उद्यान में बरसात के मौसम को छोड़कर वर्ष भर जाया जा सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

प्रदूषण के कारण गिद्ध प्रजाति ख़तरे में

गिद्ध भले ही डरावने और बदसूरत दिखाई देते हों, लेकिन ये जीव प्रकृति के सबसे बड़े सफ़ाई कर्मचारी हैं, जो धरती पर पड़े लावारिश पशु–पक्षियों के शवों को खाकर अपना पेट भरते हैं. इतना ही नहीं, ये गिद्ध शाकाहारी भोजन का कचरा भी मज़े से खा लेते हैं. लेकिन अब गिद्ध प्रजाति संकट में हैं. शहरों में तथा बड़ी आबादी वाले गांव में तो गिद्ध के दर्शन भी दुर्लभ हो चुके हैं.

आमतौर पर पक्षी वैज्ञानिक मानते हैं कि वायु प्रदूषण और कोलाहल के कारण गिद्ध प्रजाति विलुप्त हो रही है. वनों की कटाई, पर्वतीय क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों के संचालन से गिद्धों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं. भोपाल की वनस्पति विज्ञानी श्रीमती रजनी दीक्षित का कहना है कि हवाई सेवाओं के विस्तार, मोबाइल नेटवर्क के विकिरण आदि कारणों से भी गिद्ध की प्रजातियां ख़तरे में हैं. श्रीमती दीक्षित का यह भी कहना है कि गिद्ध भोजन के रूप में केंचुए ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कृषि के लिए रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग करने से केचुएं भी ज़हरीले प्रभाव से ग्रस्त हो जाते हैं और उन्हें खाकर गिद्ध भी बेमौत मर जाते हैं. जल प्रदूषण के कारण भी गिद्धों की मौत हो रही है. मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में प्रदूषण के कारण गिद्ध प्रजाति विलुप्त हो रही है. इससे प्रकृति चक्र के असंतुलित होने का ख़तरा बढ़ गया है. वन विभाग ने भी गिद्ध प्रजाति को विलुप्त प्रजाति में शामिल कर लिया है. प्रदेश के पन्ना, बांधवगढ़ और कांहा टाईगर रिजर्व में गिद्ध प्रजाति विलुप्त हो चुकी है. इसका ख़ुलासा वन विभाग की एक रिपोर्ट से हुआ है. यह रिपोर्ट गिद्ध संरक्षण को लेकर तैयार की गई थी. गिद्धों की संख्या में कमी को मुख्य कारण बढ़ती आबादी और फैलता प्रदूषण ही माना जा रहा है. सर्वे के अनुसार प्रदेश में अब केवल 600 गिद्ध ही हैं.

राजधानी भोपाल में ही गिद्धों की संख्या केवल 50 रह गई है. इनमें लॉन्ग बिल्ट नामक प्रजाति के गिद्ध ही भोपाल के गिद्ध गढ़ में पाए जाते हैं. रातापानी सेंचुरी में जेथरी के विनेका प्रजाति और बामोरी में लॉन्ग बिल्ट प्रजाति की संख्या 30 तक सिमट गई है. सिंहहोरी सेंचुरी में 60, नरसिंहगढ़ सेंचुरी में 4 ही गिद्ध बचे हैं. पन्ना, कांहा और बांधवगढ़ पचमढ़ी में गिद्ध की सभी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है.

कुल 600 गिद्ध बचे हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

हाथठेला मज़दूरों का सपना टूटा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजनीति के जादूगर हैं. वह राज्य की भोलीभाली जनता को सुनहरे सपने दिखाने में माहिर हैं और कभी–कभी तो कई दिनों तक सपनों के संसार की सैर भी कराते हैं. बाद में अपने वायदे भूलकर जनता को बेरहमी से धरती पर पटक देते हैं. हाल ही शिवराज सिंह ने राज्य के हज़ारों हाथठेला मज़दूरों की वाहवाही लूटने के लिए वायदा किया था कि सभी हाथठेला चालकों को मालिकाना हक़ दे दिया जाएगा. दो वक़्त की रोटी कमाने के लिए ख़ून पसीना बहाने वाले इन मज़दूरों ने ठेला मालिक बनने का सपना देखना शुरू कर दिया और शिवराज सिंह को दिल से दुआएं दीं, लेकिन एक साल हो गए, दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने फिर घोषणा की. तब पता चला कि राज्य में 53 हज़ार हाथठेला श्रमिकों में से केवल 9576 ठेला चालकों को ही उनके हाथठेलों का मालिकाना हक़ मिल पाया है.

इतना ही नहीं, शहरों में हाथठेला ख़रीदकर किराए पर चलाने वाले ठेला मालिकों ने कई ठेला श्रमिकों को काम से हटा भी दिया है, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह भय सताने लगा था कि कहीं उनकी कमाई से ख़रीदे गए ठेले मुफ्त में ठेला चालकों की संपत्ति न बन जाए. एक ग़ैर सरकारी संगठन के अध्ययन के अनुसार भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, कटनी, रीवा शहरों में पांच हज़ार से ज़्यादा हथठेला चालक अपने रोज़ी–रोटी गंवा चुके हैं और कई ठेला मालिकों ने तो एडवांस में अपने ठेला चालकों से क़र्ज़नामा तक लिखवा लिया है.

मजबूरी में रोज़ी–रोटी के लिए इन श्रमिकों ने मालिकों द्वारा तैयार मनमाने क़र्ज़नामे पर दस्तख़त भी कर दिए हैं या अंगूठे लगा दिए हैं. इस तरह इन श्रमिकों की हालत अब ग़ुलामों से भी बदतर हो गई है. प्रचलित रिवाज के अनुसार शहरों में बोझा ढोने के लिए हाथ ठेला सबसे कारगर साधन है. छोटे व्यापारी या छोटी पूंजी वाले वृद्ध या पारिवारिक लोग अतिरिक्त आमदनी के लिए हाथठेला ख़रीदते हैं. एक ठेला का मूल्य औसतन तीन से पांच हज़ार रुपये होता है. ठेला ख़रीदकर ठेला मालिक उसे प्रतिदिन किराए पर चलाने के लिए ठेला चालकों को दे देते हैं. एक दिन का किराया 50 से 100 रुपये तक होता है. लेकिन बरसात या विपरीत मौसम में जब कारोबार कम होता है, तो किराया 25 से 50 रुपये तक कर दिया जाता है. इसके अलावा यदि चालक को कम आमदनी होती है, तो ठेला मालिक तयशुदा किराए में भी कमी कर देता है. कहीं–न–कहीं लेकिन इससे श्रमिकों का शोषण होता है, क्योंकि ठेला चलाकर अपनी मेहनत से कमाई श्रमिक ही करते हैं और ठेला मालिक को मुफ्त में प्रतिदिन उसकी थोड़ी सी पूंजी का भरपूर लाभ मिलता रहता है. जबलपुर, भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में तो एक–एक मालिक के 100 से 150 हाथठेले रोज़ किराए पर चलते हैं. भोपाल में तो कुछ भिखारियों ने भी अपनी कमाई से एक या दो ठेले ख़रीदे, जिन्हें किराए पर देकर वे कमाई करते हैं, लेकिन कुछ अपाहिज और कमज़ोर वृद्धों ने भी अपनी कमाई उन ठेलों में ही लगा दी है और रोज़ उन्हें अपना और परिवार के गुज़ारे लायक पैसा किराए के रूप में मिल जाता है. मुख्यमंत्री की नज़र लगभग एक लाख हाथठेला चालकों के वोट बैंक पर थी, इसीलिए वे ग़रीबों के मसीहा की इमेज बनाने के लिए श्रमिकों को मालिक बनाने की घोषणा कर बैठे, लेकिन वह इस घोषणा पर अमल नहीं कर पाए.

राज्य के प्रमुख पांच नगरों में मज़दूर से मालिक बने ठेला श्रमिकों की स्थिति

क्र.	शहर	पंजीकृत हाथठेला मज़दूर	मालिकाना हक़ के लिए पात्र
1.	भोपाल	8466	270
2.	जबलपुर	7489	642
3.	इन्दौर	3315	153
4.	ग्वालियर	2233	444
5.	उज्जैन	1276	221

मुख्यमंत्री ने ठेला चालकों की श्रमिक पंचायत आयोजित कर सभी ठेला चालकों को मालिक बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन्हें बैंकों से ऋण और अनुदान देने की घोषणा भी की थी. इस घोषणा के एक साल बाद नगरीय क्षेत्रों में कराए गए सर्वेक्षण में कुल 53 हज़ार में से केवल 16641 ठेला श्रमिकों के ऋण प्रकरण बैंकों को भेजे गए और उनमें से 9576 श्रमिकों को बैंक ऋण मंजूर हुआ.

पहली बात तो यह कि सरकारी सर्वेक्षण ही संदेहास्पद है, क्योंकि राज्य में 250 से ज़्यादा शहरों में केवल 53 हज़ार हाथठेले हैं. यह आंकड़ा भरोसेमंद नहीं है. गांव में अनाज, पशुचारे खाद और भवन निर्माण सामग्री तथा अन्य सामान ढोने के लिए हाथठेले का इस्तेमाल होता है और किराए पर हाथठेला देने की प्रथा छोटे शहरों और गांवों में भी प्रचलन में है, लेकिन उनकी ओर सरकारी अमले ने कोई ध्यान नहीं दिया. फिर भी राज्य के पांच बड़े शहरों में 22,779 हाथठेलों को चलाने वाले श्रमिकों ने मालिक बनने के लिए अपना पंजीयन कराया था. इनके अलावा बहुत से श्रमिकों ने अपने ठेला मालिकों को पहले ही क़र्ज़नामा लिखकर दे दिया है. ज़ाहिर है उन्होंने पंजीयन नहीं कराया और उनकी ओर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया. ये पांच शहर हैं भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन. बाकी शहरों के बारे में अभी सरकार ने ही कोई जानकारी हासिल नहीं की है.

कुल मिलाकर राज्य में सर्वेक्षित 53 हज़ार हाथठेला श्रमिकों में से 9,576 श्रमिकों को ही ठेला मालिक बनने का सौभाग्य मिल पाया है और हजारों की संख्या में श्रमिकों को अभी सपनों के संसार में ही भटकना पड़ रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com